R.N.I. NO.HIN/2002/8718 M.P./BHOPAL/642/2021-23

• जैविक खाद के नाम पर घपला • मध्यप्रदेश में खूंखार हुए बाघ

In Pursuit of Truth

पाक्षिक

अक्स

www.akshnews.com

सत्ता, संगठन और संघ का समन्वय

वर्ष 19, अंक-11 1 से 15 मार्च 2021 पृष्ठ-48 मूल्य 25 रूपये

विपक्ष पस्त सरकार मस्त

We Deal in Pathology & Medical Equipments

Anu Sales Corporation

Add: Ground Floor, 17/1, Shanti Niketan
Near Chetak Bridge, Bhopal-462023
M. : 9329556524, 9329556530
E-mail : ascbhopal@gmail.com

इस अंक में

खेती-किसानी

9 | जैविक खाद के नाम पर घपला

एक तरफ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य पर काम कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अफसर उनकी मंशा पर पानी फेर रहे हैं। प्रदेश में किसानों को न तो अच्छी खाद मिल पा रही है...

लालफीताशाही

10–11 | मौत के बाद जागा विभाग

मुरैना में जहरीली शराब से 27 लोगों की मौत के मामले में एसआईटी की जांच में खुलासा हुआ था कि मुरैना कांड में जहरीली शराब बनाने वालों तक ओवर प्रूफ अल्कोहल डिस्टलरी से पहुंचा था।

चौसर

13 | अब ऐलान का इंतजार

मप्र में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव के लिए भाजपा, कांग्रेस सहित तमाम राजनीतिक दल ही नहीं, राज्य निर्वाचन आयोग भी पूरी ताकत से तैयारियों में जुटा हैं। हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ के निकाय चुनाव जल्द कराने के आदेश के बाद तो...

पहल

15 | फिल्म शूटिंग से राजस्व

मप्र देश के सबसे सुंदर राज्यों में से एक है। यहां का प्राकृतिक सौंदर्य इन दिनों बॉलीवुड के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। प्रदेश के लगभग हर शहर में फिल्मों की शूटिंग की जा रही है। इनमें से महेश्वर भी फिल्म मेकर्स की पसंद बना हुआ है। ऐसे में प्रदेश सरकार ने यहां फिल्म की शूटिंग...

आवरण कथा 24, 25, 26, 27, 28

करीब एक साल बाद मप्र विधानसभा का सत्र चल रहा है। सत्ता गंवा चुकी कांग्रेस के सामने सत्तापक्ष यानी भाजपा को घेरने का बड़ा मौका है। लेकिन अभी तक सदन में कांग्रेस भाजपा को घेरने में असफल रही है। जबकि पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस की महंगाई, बेरोजगारी, अपराध सहित कई ऐसे मुद्दे हैं, जिस पर सरकार को घेरा जा सकता है। लेकिन कांग्रेस सरकार को घेरने में नाकाम हुई है। अभी तक कांग्रेस ने जो प्रयास किए हैं, वे भी असर कारक नहीं रहे हैं।

राजनीति

30–31 | विपक्ष कहां है?

लोकतंत्र में विपक्ष की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगर यह कहा जाए कि वह सत्तापक्ष को निरंकुश होने से रोकता है तो इसमें कोई अतिश्योक्ति नहीं होगी। लेकिन भारत में तो ऐसा लगता है जैसे यहां विपक्ष नाम की कोई चीज ही नहीं है। देश में महंगाई, बेरोजगारी चरम पर है।

छत्तीसगढ़

35 | आखिर किसका विकास हो रहा है?

छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से लगभग 120 किमी की दूरी पर पिथौरा नाम का ब्लॉक है। इस क्षेत्र का एक बहुत बड़ा इलाका घने जंगलों से आबाद है। यह जंगल न केवल वनस्पति और जीवों से समृद्ध हैं, बल्कि यहां पर पिछले 70-80 साल से कई छोटे-बड़े गांव भी बसे हैं।

बिहार

39 | दो पाटन के बीच भाजपा

बिहार में जनता दल-यूनाइटेड और लोक जनशक्ति पार्टी के बीच घमासान दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। यह घमासान अब और बढ़ गया है, क्योंकि विगत दिनों लोजपा से पहले ही बागी हो चुके प्रदेश महासचिव केशव सिंह के नेतृत्व में लोजपा...

6 -7 अंदर की बात
41 महिला जगत
42 अध्यात्म
43 कहानी
44 खेल
45 फिल्म
46 व्यंग्य

अपनी बात

क्लास आधी–अधूरी, फीस की मांग पूरी

शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए किसी कवि ने लिखा है...

अंधकार को दूर कर जो प्रकाश फैला दे, बुझी हुई आस में जो विश्वास जगा दे।।
जब लगे नामुमकिन कोई भी चीज, उसे मुमकिन बनाने की राह जो दिखा दे वो है शिक्षा।।

अगर वर्तमान समय में देखें तो शिक्षा मात्र व्यवसाय बनकर रह गई है। हैरानी की बात तो यह है कि कोरोना संक्रमण के इस दौर में जहां लोगों की नौकरी चली गई है, कमाई घटी है, महंगाई बढ़ी है ऐसे में भी स्कूल संचालक अभिभावकों पर फीस के लिए दबाव बना रहे हैं। करीब एक साल से आधी-अधूरी ऑनलाइन क्लास चल रही हैं, फिर भी स्कूल संचालक मोटी फीस वसूलने से पीछे नहीं हट रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अभिभावक फीस नहीं देना चाहते, लेकिन स्कूल वाले ट्यूशन फीस के अलावा अन्य तरह की फीस के लिए भी दबाव बना रहे हैं। हैरानी की बात तो यह है कि खुद स्कूल संचालकों ने अपने स्टाफ, शिक्षक आदि की या तो छंटनी कर दी है या उनका वेतन कम कर दिया है, या वेतन नहीं दिया है। इसके बाद भी वे अभिभावकों पर फीस के लिए दबाव बना रहे हैं। निजी स्कूल संचालकों के फीस वसूली को लेकर दबाव बनाने के मामले में अभिभावकों में भी आक्रोश बढ़ता जा रहा है। कोरोनाकाल की वजह से प्रदेश के 25 फीसदी लोग तो ऐसे हैं जो मकान, वाहन सहित अन्य की मासिक किश्त भी नहीं चुका पा रहे हैं। अभिभावकों का कहना है कि ऐसे दौर में वह निजी स्कूलों को मोटी फीस कहां से चुकाएं। अभिभावकों ने निजी स्कूलों की ओर से ऑनलाइन पढ़ाई को लेकर किए जा रहे दावों पर भी सवाल उठाए हैं। अभिभावकों का कहना है कि स्कूलों की ओर से ऑनलाइन क्लास तो लगाई जा रही है, लेकिन नेट कनेक्टीविटी सहित अन्य कारणों से सभी विद्यार्थियों को पूरा फायदा नहीं मिल पा रहा है। इसके अलावा बच्चों की विभिन्न शंकाओं का ऑनलाइन क्लासेज में समाधान नहीं हो रहा है। अभिभावकों का कहना है कि कोरोनाकाल में असंगठित क्षेत्र के कामगारों से लेकर व्यापारियों के आय के साधन कम हुए हैं। ऐसे में सरकार को अभिभावकों के दर्द को समझते हुए फीस वसूली के मामले में निर्णय लेना चाहिए। अभिभावकों का कहना है कि पहले निजी स्कूल संचालकों को फीस की मांग करने से पहले सभी विद्यार्थियों तक ऑनलाइन क्लास की पहुंच भी सुनिश्चित करनी चाहिए। कई निजी स्कूलों में आधे से भी कम स्टाफ को ऑनलाइन कक्षाओं के लिए बुलाया जा रहा है, जबकि विद्यार्थियों का नामांकन उतना ही है। ऐसे में फिर बच्चों की मॉनिटरिंग, होमवर्क सहित अन्य कार्य पूरी गुणवत्ता के साथ कैसे हो रहे हैं। अभिभावकों का यह भी तर्क है कि जब स्कूलों के खर्चे कम हुए हैं तो फीस में राहत दी जानी चाहिए। गौरतलब है कि अधिकांश निजी स्कूल सरकार की कृपा के पात्र हैं। इन्होंने राज्य सरकार से शिक्षण के नाम पर जमीन का आवंटन कराया। आज इन भूखंडों की कीमत अरबों रुपए में है। कोई ट्रस्ट तो कोई सेवा के नाम पर स्कूल संचालन का दावा करता है, लेकिन हकीकत यह है कि इन नामी निजी स्कूलों की ओर से अन्य स्कूलों की तुलना में सबसे महंगी फीस वसूली जाती है। अगर कोई शिकायत भी आती है तो रसूख के दबाव में दबा दी जाती है। उधर, निजी स्कूल संचालकों का कहना है कि कोरोनाकाल के कारण उनकी भी हालत खराब हो चुकी है। पिछले कुछ माह से स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि पूरा स्टाफ रखना भी मुश्किल है। ऊपर से सरकार ने अभी तक फीस को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं की है। सरकार को चाहिए कि पुर्नभरण राशि का समय पर भुगतान किया जाए, ताकि जल्द ही स्टाफ को वेतन दिया जा सके।

– राजेन्द्र आगाल

पाक्षिक अक्स

वर्ष 19, अंक 11, पृष्ठ-48, 1 से 15 मार्च, 2021

प्रकाशक एवं संपादक : राजेन्द्र आगाल

सम्पादकीय कार्यालय :
प्लाट नम्बर 150, जोन-1 मनोरमा कॉम्पलेक्स,
एफ-03, 04, प्रथम तल, एम.पी. नगर
भोपाल- 462011 (म.प्र.),
फोन नं. 0755-2557777, टेलीफेक्स - 0755-4017788
email : akshmagazine@gmail.com
Website : www.akshnews.com
RNI NO. HIN/2002/8718 MPBPL/642/2021-23

ब्यूरो
मुंबई :- ऋतेन्द्र माथुर, **कोलकाता:**- इंद्रकुमार,
जयपुर:- आर.के. बिन्नानी, **छत्तीसगढ़:**- संजय शुक्ला, मार्केण्डेय तिवारी, टी.पी. सिंह, **लखनऊ :**- मधु आलोक निगम।

प्रदेश संवाददाता
094251 25096 (इंदौर) विकास दुबे
098276 18400 (जबलपुर) धर्मेन्द्र कथूरिया
094259 85070, (उज्जैन) श्यामसिंह सिकरवार
098934 77156, (विदिशा) ज्योत्सना अनूप यादव

क्षेत्रीय कार्यालय
नई दिल्ली : ईसी 294 माया इंक्लेव मायापुरी-फोन : 9811017939
जयपुर : सी-37, शांतिपथ, श्याम नगर (राजस्थान) मोबाइल-09829 010331
रायपुर : एमआईजी 1 सेक्टर-3 शंकर नगर, फोन : 0771 2282517
भिलाई : नेहरू भवन के सामने, सुपेला, रामनगर, भिलाई, मोबाइल 094241 08015
इंदौर : 39 श्रुत्रि सिलटर निपानिया, इंदौर मोबाइल - 7000123977

स्वत्वाधिकारी, मुद्रक व प्रकाशक, राजेन्द्र आगाल द्वारा आगाल प्रिंटर्स, प्लाट नं. 150, जोन-1, प्रथम तल, एफ-03, मनोरमा काम्पलेक्स, एम.पी. नगर भोपाल 462011 (म.प्र.), से मुद्रित एवं प्रकाशित

इस अंक में प्रकाशित सामग्री लेखकों के अपने विचार हैं इनसे सम्पादक का सहमत होना अनिवार्य नहीं हैं समस्त विवादों के लिए न्याय क्षेत्र भोपाल होगा।

पत्र–संपादक के नाम

akshnews.com

मनरेगा बनी सहारा

कोरोनाकाल के दौरान शहरों से पलायन करके गांवों में पहुंचे लोगों को मनरेगा के तहत रोजगार मिल रहा है। गांवों में बेरोजगारों की बढ़ती संख्या को देखते हुए मप्र सरकार ने मनरेगा के तहत हर श्रमिक को काम देने की घोषणा कर दी है, लेकिन उन्हें काम भी मिले तो बात बनेगी।

● **अभिषेक नारंग,** भोपाल (म.प्र.)

क्या करेगी भाजपा?

प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव सामने हैं। भाजपा संगठन में नए चेहरों के आने से उनसे पुरानी सियासी अदावतें नहीं भुला पाना कार्यकर्ताओं के लिए आसान नहीं है। कांग्रेस या निर्दलीय विधायक रहे नेताओं का भाजपा में आना उनकी कार्यप्रणाली में बदलाव नहीं ला सका है।

● **विनोद खत्री,** इंदौर (म.प्र.)

किसानों की सरकार

मप्र सरकार देश की ऐसी पहली सरकार है, जिसकी प्राथमिकता में हमेशा से ही किसान कल्याण रहा है। यही वजह है कि सरकार उनके हित में लगातार न केवल योजनाएं बनाती रहती है बल्कि उनके क्रियान्वयन पर भी पूरा फोकस करती है। कोरोनाकाल में भी सरकार ने किसानों को प्राथमिकता दी है।

● **मीनाक्षी मकोड़िया,** सीहोर (म.प्र.)

कैसी रुकेंगी आपदा की घटनाएं

धरती के 75 प्रतिशत हिस्से पर जल है और सिर्फ 25 प्रतिशत हिस्से पर ही मानव की गतिविधियां जारी थी। आज से 200-300 साल पहले मानव की आकाश और समुद्र में पकड़ नहीं थी, लेकिन जबसे मानव ने आकाश और समुद्र में दखलअंदाजी की है, धरती को पहले की अपेक्षा बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। मानव ही है प्रलय का सृजनकार, क्योंकि उसने धरती पर जो जुल्म किया है, धरती उसका बदला लेने के लिए अब पूरी तरह तैयार है। मानव ने अपनी सुख, सुविधा और अर्थ के विकास के लिए धरती का हद से ज्यादा दोहन कर दिया है। उत्तराखंड के चमोली में ग्लेशियर टूटने के बाद आई भयावह बाढ़ भी मानव द्वारा प्रकृति पर किए गए जुल्मों की एक देन है।

● **प्रीति शिवहरे,** राजगढ़ (म.प्र.)

किसान आंदोलन का निष्कर्ष क्या?

किसान नेताओं को यह समझना चाहिए कि पुरानी व्यवस्था और खेती के तौर-तरीकों से चिपके रहने से किसानों को कुछ हासिल नहीं होने वाला। किसानों को भी यह समझना चाहिए कि वे संकीर्ण राजनीति का मोहरा बनाए जा रहे हैं। किसान नेताओं की तरह कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दल भी किसान आंदोलन की आड़ में मोदी सरकार को नीचा दिखाने की रणनीति पर चल रहे हैं। विपक्षी दल यह जानते हैं कि किसानों की हालत में सुधार लाने की जरूरत है और यह सुधार खेती को बाजार आधारित अर्थव्यवस्था से जोड़ने से होगा।

● **अरविंद मिश्रा,** जबलपुर (म.प्र.)

फिर टाइगर स्टेट बनेगा मप्र

देश में सबसे ज्यादा 526 बाघ होने का तमगा हासिल कर टाइगर स्टेट बने मप्र में बाघों की मौत का आंकड़ा कम करने के जतन शुरू हो गए हैं। बाघों की मौत की मुख्य वजह उनका संरक्षित क्षेत्रों से बाहर निकलकर आना ही है। इस पर तभी रोक लग सकती है, जब संरक्षित क्षेत्रों के बीच सुरक्षित कॉरिडोर हो और राज्य सरकार इसी पर काम कर रही है। सरकार का इस ओर ध्यान देना यह बता रहा है कि एक बार फिर प्रदेश को टाइगर स्टेट का दर्जा मिलेगा।

● **वर्षित शर्मा,** ग्वालियर (म.प्र.)

पाठकों से निवेदन

कृपया अपनी प्रतिक्रियाएं पक्ष या विपक्ष जो भी संभव हो इस पते पर भेजें

अक्स

150 जोन-1, मनोरमा काम्पलेक्स,
एफ-02, 03, एमपी नगर, भोपाल

चिराग तले अंधेरा

राजनीति में जिस तेजी से चिराग पासवान का सूर्य उदय हुआ था, लगता है उसी तेजी से उनका अस्त भी हो जाएगा। चिराग पासवान तय नहीं कर पा रहे कि भविष्य में कौन सी रणनीति अपनाई जाए। भाजपा तो नीतीश कुमार की नाराजगी के डर से अब लोजपा को राजग की बैठकों में भी नहीं बुला रही। लोजपा की इकलौती विधान परिषद् सदस्य नूतन सिंह को भी तोड़ लिया। पिछले दिनों कुल 208 नेताओं ने लोजपा छोड़ जद(एकी) का झंडा थाम लिया था। इस पर चिराग ने कहा था कि केशव सिंह तो पार्टी से निकाले जा चुके थे। चर्चा तो चिराग और उनके सांसद चाचा पशुपति कुमार पारस के बीच मतभेद बढ़ जाने की भी है। जो शुरू से नीतीश विरोध की रणनीति के समर्थक नहीं थे। पार्टी के कई नेता अब मान रहे हैं कि 37 वर्षीय चिराग ने पिता जैसी सियासी परिपक्वता नहीं दिखाई और उनके अति आत्मविश्वास के कारण पार्टी की लुटिया डूब गई। तो भी चिराग ने अब दलित और सवर्ण वोट बैंक की सियासत में हाथ आजमाने का खाका खींचा है। पूर्व विधायक राजू तिवारी को बिहार प्रदेश लोजपा का कार्यकारी अध्यक्ष इसी रणनीति के हिसाब से बनाया है। फिलहाल तो उनकी सबसे बड़ी चुनौती अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को पार्टी में बनाए रखने की है।

बेचैन बहनजी

मायावती अचानक सक्रिय हो गई हैं। पिछले हफ्ते लगातार लखनऊ रहीं। सूबे के हर जिले और मंडल की सांगठनिक स्थिति की समीक्षा की। पदाधिकारियों को ताश के पत्तों की तरह फेंट दिया। सूबे की चार बार मुख्यमंत्री रह चुकी और सबसे कद्दावर दलित नेता मानी जाने वाली मायावती को भाजपा ने सियासी हैसियत के हिसाब से इतना बौना बना दिया कि सूबे की विधानसभा में उनकी हैसियत एक राज्यसभा सीट जीतने लायक भी नहीं बची। ज्यादातर कद्दावर नेता पहले ही पार्टी छोड़ चुके हैं। माना कि अभी भी 18-20 फीसदी के अपने दलित वोट बैंक पर भरोसा कायम है पर एक तो केवल इतने भर से सत्ता हासिल नहीं की जा सकती। ऊपर से भीम आर्मी के चंद्रशेखर आजाद ने उनकी नींद उड़ा रखी है। अब तो अमेरिकी पत्रिका टाइम ने दुनिया के 100 उभरते लोगों की सूची में उन्हें शामिल कर उनका कद और बढ़ा दिया है। देखना है कि मायावती चंद्रशेखर आजाद के इस उभार को किस तरह लेती हैं। इस अति सक्रिय राजनीतिक समय में जब हर तरफ आंदोलनों की गूंज है, उनकी निष्क्रियता ही उनकी स्थिति का आंकलन करने के लिए काफी है।

त्रिवेंद्र के सामने चुनौतियां

चुनौतियों का पहाड़ खड़ा होने से पहले ही सजग हो जाना अच्छे राजनेता की पहचान है। विधानसभा चुनाव में अब बस एक वर्ष बचा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के सामने पार्टी आलाकमान का विश्वास बनाए रखने की बड़ी चुनौती है। कांग्रेस से भाजपा में आए नेता ही नहीं, भाजपा की रावत विरोधी लाबी भी अंदरखाने सूबे में नेतृत्व परिवर्तन के लिए लाबिंग कर रही है। विरोधियों ने उनके बारे में हवा बनाई है कि वे अगला चुनाव नहीं जिता पाएंगे। महाराष्ट्र के राज्यपाल और पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी को चुनाव से पहले सरकार की कमान सौंपने का सुझाव देने वालों की भी कमी नहीं। हालांकि वे अब 80 के होने को हैं। लेकिन भाई लोग अब कर्नाटक के येदियुरप्पा का उदाहरण दे उम्र सीमा का कोई घोषित फॉर्मूला न होने की दुहाई दे रहे हैं। चमोली की प्राकृतिक आपदा से निपटने में त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार ने कोई ढिलाई नहीं बरती। पिछले दिनों दिल्ली के दौरे में प्रधानमंत्री से भी मिले। आलाकमान और उनके बीच क्या बातचीत हुई, इसका कोई खुलासा करने के बजाय वापस देहरादून पहुंचकर उन्होंने आत्मविश्वास के साथ कहा कि वे अपने मंत्रिमंडल का जल्द विस्तार करेंगे।

बदलते रिश्ते-संतों की सियासत

अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी का कभी सियासी लोगों में खासा जलवा था। अब उत्तराखंड में सरकार भाजपा की है तो बेचारे अलग-थलग पड़ते जा रहे हैं। सूबे के मुख्य सचिव ने कुंभ की अवधि घटाकर एक महीने करने का ऐलान किया तो इसे लेकर भी साधु-संतों में मतभेद बढ़ गए। सामान्य परिस्थितियों में तो कुंभ एक जनवरी से तीस अप्रैल तक आयोजित होता है। पर एक तो कोरोना संक्रमण की दहशत, दूसरे श्रद्धालुओं के सैलाब के लिए लंबी अवधि तक जरूरी बंदोबस्त कर पाने की अड़चन ने राज्य सरकार को अवधि सीमित करने के लिए बाध्य किया। महंत नरेंद्र गिरी को अखरा तो इस फैसले का विरोध भी किया और भाजपा सरकार को धर्म विरोधी भी ठहराया। लेकिन उन्हीं की संस्था के महासचिव महंत हरि गिरी ने इस फैसले का स्वागत किया। इतना ही नहीं मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की तारीफ भी कर डाली। लगता है महंत की मंशा बदल रही है। लोगों को लगता है कि कहीं वह भी राजनीति में हाथ न आजमाएं।

बदलते रिश्ते

वसुंधरा राजे की सक्रियता ने राजस्थान भाजपा की सियासत को अचानक गरमा दिया है। वे जयपुर में हुई प्रदेश भाजपा की कोर समिति की बैठक में शिरकत के लिए दिल्ली से पहुंची। हवाई या रेल मार्ग से नहीं। वे जानबूझकर सड़क मार्ग से गई। रास्ते में जगह-जगह समर्थकों ने स्वागत किया। परोक्ष रूप से शक्ति प्रदर्शन और लोकप्रियता की जांच मकसद होगा। वसुंधरा को 2018 की हार के बाद आलाकमान ने हाशिए पर पहुंचा दिया था। सतीश पूनिया को सूबेदार उनकी इच्छा के विपरीत बनाया गया था। गनीमत रही कि विधायक दल के नेता गुलाबचंद कटारिया पार्टी के पुराने नेता और वसुंधरा से तालमेल रखने वाले इंसान हैं। पर वसुंधरा जान चुकी हैं कि अब आलाकमान 76 वर्ष के कटारिया को उनकी बुजुर्ग अवस्था का वास्ता देकर पद से हटा सकता है। लिहाजा वे और उनके समर्थक मुखर हुए हैं। इस दौरान सूबे में भाजपा के भीतर कई घटनाएं घटी। जिससे महारानी को उम्मीद की किरण दिखने लगी है।

हर पल कमाई पर नजर

सत्ता और लक्ष्मी का संबंध नकारा नहीं जा सकता। जो भी सत्ता में आता है, उस पर लक्ष्मी पाने का भूत मंडराने लगता है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से यह देखने को मिल रहा है कि मंत्री के साथ ही उनके नाते-रिश्तेदार भी लक्ष्मी बटोरने में जुट जाते हैं। उन पर कमाई का ऐसा भूत सवार होता है कि वे नैतिक-अनैतिक भी भूल जाते हैं। ऐसा ही इन दिनों प्रदेश में एक मंत्री के रिश्तेदार करने में जुटे हुए हैं। आलम यह है कि मंत्रीजी के नाम पर उनके दामाद सभी मामलों में डील कर रहे हैं। दामाद का एजुकेशन-क्वालिफिकेशन क्या है, यह तो किसी को नहीं मालूम, लेकिन वे कमाई के लिए जिस तरह काम कर रहे हैं, उससे लगता है जैसे वे अनपढ़ हों। विगत दिनों ससुर के विभाग में एक कैंसर पीड़ित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के तबादले का मामला आया, तो दामाद साहब नैतिकता और सहानुभूति भूल गए और उस पीड़ित से भी तबादला कराने की फीस वसूल करने की कोशिश की। यही नहीं पैसा कमाने में उनकी आंखें इस कदर बंद हैं कि एक बार तो उन्होंने सैलरी की फाइल पर भी पैसा मांग लिया। बताया जाता है कि विभागीय अधिकारियों की सैलरी की फाइल मंत्रीजी के पास पहुंची तो दामाद साहब ने कहा कि इस फाइल का चढ़ावा कहां है। दामाद की बात सुन एक अफसर ने झल्लाकर कहा कि माननीय मुंह खोलने से पहले फाइल को पढ़ तो लीजिए। दरअसल, दामाद फाइल खोलने से पहले चढ़ावा मांगने के आदी हो गए हैं।

कमाई की तिकड़ी

प्रदेश के सबसे कमाऊ विभागों में से एक विभाग में इन दिनों मनमर्जी की व्यवस्था चल रही है। विभागीय मंत्री और उनके चहेतों ने विभाग को दुधारू गाय समझकर दुहना शुरू कर दिया है। इस संदर्भ में कई बार संघ और संगठन में शिकायतें पहुंच चुकी हैं। लेकिन मंत्रीजी की मनमर्जी रुक नहीं रही है। विभागीय सूत्रों का कहना है कि इस समय तो विभाग में तिकड़ी काम कर रही है। यह तिकड़ी केवल माल बटोरने के काम में जुटी हुई है। जब इसकी पड़ताल की गई तो यह तथ्य सामने आया कि विभाग में मंत्री, विभाग के कर्ताधर्ता और इंस्पेक्टरों का राज चल रहा है। आलम यह है कि ये तीनों सरकारी व्यवस्था को दरकिनार कर विभाग में अपनी व्यवस्था चला रहे हैं। इनका मकसद यह है कि जैसे भी हो रोजाना मोटी कमाई होनी चाहिए। अब इस तिकड़ी की शिकायत मुख्यमंत्री तक पहुंच गई है। लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि क्या इस तिकड़ी को सरकार तोड़ पाएगी। दरअसल, विभाग के मंत्रीजी पर भाजपा के नए-नवेले दमदार नेताजी का हाथ है। सूत्र तो यह भी बताते हैं कि अपने आका के इशारे पर ही मंत्रीजी और उनके चहेते विभाग का दोहन कर रहे हैं।

मैम साहब का दम

मप्र वाकई अजब है, गजब है। यहां हर दिन कोई न कोई अनोखा किस्सा या काम होता ही है। ताजा मामला काफी दिलचस्प है। महिला उत्थान के लिए समर्पित सरकार में जहां एक तरफ महिलाओं को सशक्त किया जा रहा है, वहीं महिला अधिकारियों को किस तरह प्रताड़ित किया जा रहा है, यह तथ्य सामने आया है। दरअसल, विगत दिनों प्रदेश के एक जिले में पदस्थ एक महिला पुलिस अधिकारी का तबादला कर दिया गया। लोगों को समझ में नहीं आया कि आखिर यह तबादला क्यों किया गया। जब इस मामले की पड़ताल की गई तो पता चला कि इस तबादले के पीछे एक मैम साहब का हाथ है। इसका जब गहराई से परीक्षण किया गया तो यह तथ्य सामने आया कि उक्त मैम साहब प्रदेश सरकार के एक मंत्री की पत्नी हैं। मंत्री की पत्नी को उक्त सीएसपी पसंद नहीं थीं। इसलिए उन्होंने उन्हें हटाने के लिए प्रण ले लिया और कुछ दिन में उन्हें चलता करवा दिया। गौरतलब है कि देवास में भी इसी तरह एक नवागत महिला आईपीएस को अचानक हटा दिया गया। फिर उन्हें महिला सेल में अच्छे कार्य के लिए पुरस्कृत किया गया, जबकि उक्त महिला अधिकारी को उक्त सेल में आए जुम्मा-जुम्मा दो-तीन माह ही हुए हैं। ऐसे में लोगों के मन में सवाल उठ रहा है कि आखिरकार उक्त महिला अधिकारी ने ऐसा कौन-सा कार्य कर डाला है कि उन्हें इस तरह पुरस्कृत किया गया। लोग अब इसकी खोजबीन में जुट गए हैं।

ऊर्जाधानी में मंत्रीपुत्र का जलवा

प्रदेश के बड़े विभाग के मंत्री और दमदार तथा दबंग छवि के नेता का तो जलवा है ही, अब उनके पुत्र ने अपना जलवा जमाना शुरू कर दिया है। राजनीति में अपनी पारी का इंतजार कर रहे नेतापुत्र अपने पिता के विधानसभा क्षेत्र में तो सक्रिय हैं ही, साथ ही इन दिनों वे ऊर्जाधानी यानी सिंगरौली में जलवा बिखेर रहे हैं। आलम यह है कि मंत्रीपुत्र आए दिन ऊर्जाधानी का दौरा कर रहे हैं। इसको लेकर प्रदेश की राजनीतिक और प्रशासनिक वीथिका में तरह-तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। गौरतलब है कि सिंगरौली में कई औद्योगिक संस्थान हैं, तथा वहां निवेश की अपार संभावनाएं हैं। ऐसे में कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद मंत्रीपुत्र पिता की कमाई को निवेश करने जा रहे हैं। वहीं कुछ लोगों का अनुमान है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि पुत्र भी पिता की तरह रंग मिजाज हो गया है। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि प्रदेश में अपनी राजनीति चमकाने के लिए मंत्रीपुत्र ऊर्जाधानी का चक्कर लगा रहे हैं। यहां बता दें कि मंत्रीपुत्र आगामी विधानसभा चुनाव में विधायकी लड़ने की मंशा पाले हुए है और मंत्री इसके लिए फील्डिंग कर रहे हैं।

मनमाने नियम की बलि

प्रदेश की प्रशासनिक वीथिका में अपनी कड़क मिजाजी के लिए ख्यात एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी का तबादला सुर्खियों में बना हुआ है। दरअसल, साहब के पास वह विभाग था जहां कड़कमिजाजी नहीं समझदारी से काम करना होता है। लेकिन साहब हैं कि वे जहां भी होते हैं, मनमानी के नियम बना देते हैं। इस बार उनके मनमाने नियम ने उनकी बलि ले ली। दरअसल, कोरोनाकाल में स्कूलों का संचालन नहीं हो पाने के कारण साहब ने सरकार से बिना चर्चा किए परीक्षा की नई व्यवस्था लागू कर दी। प्रश्नपत्र से लेकर परीक्षा व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन कर दिया। जबकि ऐसी कोई भी व्यवस्था अगले सत्र के लिए बनाई जाती है, लेकिन साहब ने इसे वर्तमान सत्र में ही लागू करने का ऐलान कर दिया। इसमें यह व्यवस्था भी थी कि परीक्षा देने आने वाले हर बच्चे को स्कूल विभाग भोजन कराएगा। साहब की यह व्यवस्था सरकार को कतई पसंद नहीं आई। पहले तो उसने साहब की व्यवस्था को निरस्त किया, फिर कुछ दिन बाद साहब को भी चलता कर दिया।

किसान सरकार के सामने किसी भी कीमत पर नहीं झुकेगा। जब तक कृषि कानून वापस नहीं हो जाते किसानों का आंदोलन जारी रहेगा। फसलें पकने के दौरान किसान बारी-बारी से फसल काटने जाएंगे और फिर आंदोलन में शामिल हो जाएंगे।

● **राकेश टिकैत**

कांग्रेस इस समय कमजोर स्थिति में है। हमारी कोशिश है कि कांग्रेस को मजबूत आधार मिले। इसके लिए हम लगातार कोशिश करते रहेंगे। हमारी कोशिशों को अलग-अलग नाम दिया जा रहा है, लेकिन इससे हम घबराने वाले नहीं हैं। उम्मीद है एक दिन कांग्रेस नए नेतृत्व के साथ दमदारी से उभरेगी। इसलिए हम कांग्रेस के सभी नेताओं को एकजुट करने में लगे हुए हैं।

● **गुलाम नबी आजाद**

क्रिकेट मैदान पर लंबी पारी खेलने के बाद अब राजनीति में नई पारी खेलना चाहता हूं। इसलिए मैंने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की है। देश में राष्ट्रवाद को मजबूत करना है। यह कार्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के नेतृत्व में चल रहा है। इसलिए मैं भी इस में सहयोग करना चाहता हूं।

● **अशोक डिंडा**

पाकिस्तान की कोशिश है कि पड़ोसी राज्यों से हमारे बेहतर संबंध बने रहें। इसके लिए भारत के साथ वार्ता का एक और दौर शुरू हुआ है। हमें उम्मीद है कि दोनों देशों की सकारात्मक पहल से दोस्ती का नया रास्ता निकलेगा।

● **इमरान खान**

मैं किसी धर्म के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन लव जिहाद बेस्ड मेरा म्यूजिक एल्बम देखकर लोगों को लगता है कि मैं मुस्लिम धर्म के खिलाफ हूं। दरअसल मैं एल्बम के जरिए लड़कियों को आगाह करना चाहती हूं कि वे गलत रिश्ते में न फंसे। मैंने ऐसे कई केस देखे हैं, जहां एक मुस्लिम लड़का हिंदू बनकर लड़की के साथ अफेयर करता है और पता चलने के बाद लड़की को टॉर्चर करता है। लव जिहाद के बारे में मैंने काफी रिसर्च किया और तब मुझे एहसास हुआ कि ये इंटरकास्ट शादी या अफेयर के बारे में नहीं है, बल्कि जो फ्रॉड हो रहे हैं, ये एक्ट उसके बारे में है। हम अपनी एल्बम के जरिए लोगों को यही दिखाना चाहते हैं और उन्हें आगाह करना चाहते हैं।

● **पायल घोष**

वाक्युद्ध

पश्चिम बंगाल को ममता दीदी ने अपने अक्खड़पन से बीमारू राज्य बना दिया है। भाजपा इस राज्य को प्रगति के पथ पर दौड़ाना चाह रही है। यह तभी संभव है, जब राज्य से दीदी की सरकार की विदाई हो। इस बात का एहसास पश्चिम बंगाल की जनता को भी हो गया है, इसलिए वहां टीएमसी के खिलाफ माहौल है।

● **जेपी नड्डा**

भाजपा वाले सपना देख रहे हैं। वे राज्य की जनता को धर्म के आधार पर बांटने में लगे हुए हैं। लेकिन उनका यह षड्यंत्र पश्चिम बंगाल में नहीं चलने वाला। छल-कपट की राजनीति का सहारा लेकर जिस तरह भाजपाई पश्चिम बंगाल को बदनाम कर रहे हैं, उसका जवाब यहां की जनता विधानसभा चुनाव में देगी।

● **ममता बनर्जी**

जैविक खाद के नाम पर घपला

एक तरफ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य पर काम कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अफसर उनकी मंशा पर पानी फेर रहे हैं। प्रदेश में किसानों को न तो अच्छी खाद मिल पा रही है, और न ही बीज। इसके बावजूद प्रदेश में अनाज का रिकार्ड उत्पादन हो रहा है। अगर सरकार की योजनाओं और मंशानुसार किसानों को अच्छी किस्म का बीज और खाद मिलता तो अनाज का और उत्पादन होता। आलम यह है कि किसानों को सरकारी योजना के तहत मिलने वाली खाद और बीज घटिया किस्म की होती हैं। परंपरागत कृषि योजना के नाम पर प्रदेश में करीब 100 करोड़ से ज्यादा का घोटाला सामने आया है। इसमें अधिकांश किसानों को न तो खाद मिली और न ही कोई अन्य सामग्री। जिन्हें खाद मिली थी तो उसमें राख, मिट्टी और तरल पदार्थ के नाम पर पानी टिका दिया गया।

कांग्रेस के विधायक फुंदेलाल सिंह मार्को ने पिछली विधानसभा में इसे आदिवासियों के नाम पर बड़ा घोटाला करार देते हुए जांच की बात उठाई थी। आदिम जाति कल्याण मंत्री ओमकार सिंह मरकाम ने विधायकों के आरोपों का साथ देते हुए पूरी योजना को कागजी करार दिया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए अब कृषि विभाग ने सात विधायक और कृषि व आदिम जाति कल्याण के अधिकारियों की **कमेटी बनाकर जांच कराने का फैसला** किया है। सूत्रों के मुताबिक आदिम जाति कल्याण विभाग ने **20 जिलों के आदिवासी और विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा, सहरिया व भारिया किसानों को कोदो, कुटकी, ज्वार, बाजरा के उत्पादन में सहयोग और प्रोसेसिंग, पैकेजिंग व मार्केटिंग के लिए 100 करोड़ रुपए कृषि विभाग को वर्ष 2017-18 में दिए थे। विभाग का मकसद साफ था कि जैविक खेती करने वाले आदिवासी** किसानों को उन्नत खेती के लिए प्रोत्साहित किया जाए और उनके लिए खेती लाभ का सौदा बने, इसके प्रयास हों।

कृषि विभाग ने इस राशि का इस्तेमाल बायोलॉजिकल नाइट्रोजन, हरी खाद के प्रयोग के लिए सहायता, तरल जैव उर्वरक सहायता, जैव पेस्टीसाइड, फॉस्फेट रिच ऑर्गेनिक मेन्योर प्रयोग के लिए सहायता एवं प्रोसेसिंग, पैकिंग मटेरियल विथ पीजीएस लोगो में करने को मिलाकर कार्ययोजना बनाई थी। 3 जुलाई 2017 को आदिम जाति कल्याण विभाग ने **बायोपेस्टीसाइड को छोड़कर वर्मीकंपोस्टिंग को** शामिल करते हुए योजना को मंजूरी दे दी। परियोजना संचालक (आत्मा) ने प्रोसेसिंग, पैकेजिंग और हर जिले के ब्रांडनेम उत्पाद के क्षेत्र में कोई काम नहीं किया और न ही राशि खर्च की। सितंबर 2018 में जैविक कृषि आदान सहायता अनुदान कार्यक्रम के लिए मिले 100 करोड़ रुपए से 14 जिले के लिए लक्ष्य तय किए गए, लेकिन जमीन पर कोई ठोस काम नहीं हुआ। विधानसभा में फुंदेलाल सिंह मार्को ने ध्यानाकर्षण के जरिए इस मुद्दे को उठाते हुए आरोप लगाया कि राशि की बंदरबांट की गई। कागजों में लीपापोती कर आदिवासियों के नाम पर भ्रष्टाचार को अंजाम दिया गया। अन्य विधायकों ने भी आरोपों का समर्थन करते हुए जांच की बात उठाई।

सूत्रों का कहना है कि जब कृषि मंत्री सचिन यादव सदन में जवाब देने की तैयारी कर रहे थे, तब आदिम जाति कल्याण मंत्री ओमकार सिंह मरकाम दस्तावेज का पुलिंदा लेकर बैठक में आए थे और **उन्होंने इसे बड़ा भ्रष्टाचार का मामला करार देते हुए जांच कराने की बात कही थी।** कृषि विभाग से ज्यादा तैयारी आदिम जाति कल्याण विभाग की थी, क्योंकि राशि उन्होंने ही दी थी। सूत्रों का कहना है कि मप्र एग्रो को खाद सहित अन्य सामग्री की आपूर्ति का जिम्मा सौंपा गया था। एग्रो ने निजी कंपनियों को ठेका दिया। आरोप है कि जो सामग्री वितरित की गई वो बेहद घटिया थी। खाद में राख व मिट्टी की मात्रा अधिक होने और तरल पदार्थ में खाद की जगह पानी पाया गया, जो बेअसर रहा।

इस योजना के तहत केंद्र सरकार ने 2015 में किसानों को बीज के जरिए जैविक खाद मुहैया कराने के लिए प्रदेश को फंड के साथ गाइडलाइन भी जारी की गई थीं। गाइडलाइन में स्पष्ट तौर पर कहा गया था **किसानों को सेसबानिया बीज** दिया जाए। सेसबानिया बीज हरी खाद का स्त्रोत होता है जिससे किसान को फसल के लिए अलग से खाद नहीं डालनी पड़ती। **सेसबानिया नाइट्रोजन** का विकल्प माना जाता है।

इस गाइडलाइन को प्रदेश के कृषि विभाग के अधिकारियों ने बदल दिया। प्रदेश से जो आदेश जारी हुए उनमें लिखा था कि परंपरागत कृषि के लिए किसानों को **सेसबानिया रोष्ट्रेटा** मुहैया कराया जाए। इसमें हैरानी की बात ये है कि रोष्ट्रेटा बीज की प्रदेश में पैदावार ही नहीं है। यही खेल 2015 से 2018-19 तक चलता रहा।

● **लोकेंद्र शर्मा**

ऐसे हुआ घोटाला

जैविक खेती के नाम पर किया गया ये घोटाला 2017-18 का है। आदिम जाति कल्याण विभाग ने 20 जिलों के आदिवासी और विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा, सहरिया के साथ भारिया किसानों को कोदो, कुटकी, ज्वार, बाजरा के उत्पादन में सहयोग, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग और मार्केटिंग के लिए करीब 100 करोड़ रुपए कृषि विभाग को दिए थे। विभाग का मकसद जैविक खेती करने वाले आदिवासी किसानों को बढ़ावा दिया जाना था। यह पैसा आदिवासी किसानों के लिए केंद्र से मिला था। विभाग को इससे खाद-बीज खरीदने थे और फिर प्रोसेसिंग और मार्केटिंग के लिए किसानों को देने थे। प्लान ये था कि रासायनिक खाद के बजाय जैविक खेती को बढ़ावा दिया जाए। सरकार ने पैसा तो दे दिया, लेकिन अफसरों ने उसका फायदा किसानों को नहीं पहुंचाया। सितंबर 2018 में जैविक खेती के लिए 100 करोड़ रुपए का बजट रखा गया। मप्र एग्रो को खाद सहित बाकी सामान उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी दी गई थी। एग्रो ने निजी कंपनियों को ठेका दिया। आरोप है कि जो सामग्री दी गई वो बेहद घटिया थी। खाद में राख और मिट्टी मिली थी और तरल पदार्थ में पानी भरा था। इस योजना को मंडला, बालाघाट, डिंडौरी, अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, ग्वालियर, दतिया, श्योपुर, मुरैना, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर और छिंदवाड़ा में लागू किया जाना था।

मौत के बाद जागा विभाग

मुरैना में जहरीली शराब से 27 लोगों की मौत के मामले में एसआईटी की जांच में खुलासा हुआ था कि मुरैना कांड में जहरीली शराब बनाने वालों तक ओवर प्रूफ अल्कोहल डिस्टलरी से पहुंचा था। इस बीच में आनन-फानन में आबकारी विभाग 13 जनवरी को हरकत में आया। भोपाल से एक दल प्लांट का निरीक्षण करने गया, जिसने रिपोर्ट में कहा कि प्लांट में 20 स्प्रिट व रिसीवर टैंक नियम विरूद्ध बनाए गए हैं। नियम है कि ऐसे टैंक को कवर्ड कैंपस के अंदर ही स्थापित किया जाए। स्प्रिट का रखरखाव सुरक्षित तरीके से हो, इसके लिए टैंक बनाए जाते हैं। टैंक के चारों तरफ 30 से 33 फीट की ईंट, कांक्रीट और सीमेंट की पक्की दीवार बनाई जाती है। जब सोम के टैंक की जांच की गई तो वहां कोई पक्की दीवार नहीं मिली। सोम डिस्टलरीज के प्लांट में स्प्रिट का स्टॉक खुले एरिया में बने टैंकों में किया गया था। यानी स्प्रिट की कालाबाजारी आसानी से होने की आशंका है। निरीक्षण की रिपोर्ट मिलने के बाद आबकारी आयुक्त ने 19 जनवरी को एक नोटिस सोम डिस्टलरी को भेजा। जिसमें कहा गया कि नियम विरूद्ध बनाए गए प्लांट से स्प्रिट का उपयोग प्रतिबंधित किए जाने की कार्रवाई 22 जनवरी को की जाएगी। इसके बाद देर रात 11 स्प्रिट व 9 रिसीवर टैंक को सील करने की कार्रवाई की गई और उन्हें सील कर दिया गया।

जानकारी के अनुसार प्लांट में नियम विरूद्ध टैंक बनाकर स्प्रिट उपयोग 2011 में शुरू हो गया था। **सोम डिस्टलरीज** ने सेहतगंज स्थित प्लांट में 21 अप्रैल को 2011 में प्लांट का अपग्रेडेशन करने की अनुमति मांगी थी, लेकिन आबकारी विभाग के रिकॉर्ड में यह आवेदन 8 अगस्त 2015 को संभागीय उड़नदस्ता भोपाल और 20 अगस्त 2015 को आबकारी आयुक्त कार्यालय ग्वालियर को मिलना दर्ज है। यानी पूरे 4 साल बाद। अब तक प्लांट में पुराने के स्थान पर नए 19 टैंक बिना अनुमति के केवल बनकर तैयार ही नहीं हुए, बल्कि उसमें स्प्रिट का स्टॉक भी किया जाने लगा। इसके बाद तत्कालीन आबकारी आयुक्त राकेश श्रीवास्तव ने सोम डिस्टलरी के आवेदन पर 14 सितंबर 2015 को संभागीय उड़नदस्ता भोपाल के उपायुक्त से अभिमत मांगा। इस अफसर ने प्लांट का निरीक्षण किए बिना ही बता दिया कि निर्माण **गुणवत्तापूर्ण और पर्यावरण** सुरक्षा के अनुरूप हुआ है। इसलिए अनुमति दी जा सकती है। इसके बाद आबकारी आयुक्त ने 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाकर सशर्त अनुमति प्रदान कर दी। यह अपने बचाव में किया गया फैसला था। शर्त यह रख दी कि जो टैंक बिना अनुमति के बनाए गए हैं, इन्हें खाली किया जाए और फिर इसमें स्प्रिट भरा जाए। यह अनुमति 28 दिसंबर 2015 को दी गई थी। सोम डिस्टलरीज ने इस शर्त का खुलेआम उल्लंघन किया। जिस पर अफसरों ने आंखें बंद कर ली। प्लांट में पुराने प्लांट के स्थान पर सुरक्षा को ताक पर रखकर खुले में नया प्लांट स्थापित कर दिया। यह सब आबकारी अधिकारियों की आंखों के सामने हुआ, क्योंकि प्लांट में बनने वाली शराब केवल सरकार ही खरीदती है, इसलिए यहां 24 घंटे आबकारी अफसर की ड्यूटी रहती है। आबकारी विभाग ने 5 साल तक कोई कार्रवाई नहीं की। आबकारी आयुक्त ने 16 दिसंबर 2020 को नोटिस देकर नियमों के अनुरूप निर्माण किया जाने पर कंपनी से जवाब मांगा। कंपनी की तरफ से जवाब देने के बजाय सुझाव दे दिया कि नियमों में संशोधन कर कवर्ड एरिया के बजाय खुले में बनाने का प्रावधान किया जाए। बावजूद इसके अफसर 5 साल तक आंख मूंदे रहे। यदि मुरैना शराब कांड नहीं होता तो शायद नींद से जागते भी नहीं।

यह मामला विधानसभा के बजट सत्र में भी उठा। कांग्रेस विधायक एवं पूर्व मंत्री डॉ. गोविंद सिंह ने सदन में सभी का ध्यान इस बात पर खींचा। वित्त एवं वाणिज्य कर मंत्री जगदीश देवड़ा ने सदन में स्वीकारा कि अवैध रूप से स्प्रिट टैंक बनाए गए थे। वित मंत्री ने सदन में यह स्वीकार किया कि सोम डिस्टलरीज ने 20 स्प्रिट टैंक अवैध रूप से बनाए। वर्ष 2004-05 में सोम डिस्टलरीज को धार के आबकारी आयुक्त ने ब्लैक लिस्ट किया था। इसके बाद भी यह डिस्टलरीज चलती रही। बिना अनुमति के सैनिटाइजर बनाया गया। टैक्स भी नहीं दिया गया। ऐसे में सवाल यह उठता है कि यह डिस्टलरीज लगातार कैसे चलती रही।

1990 के बाद से प्रदेश में चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो या फिर भाजपा की, तमाम अनियमितताओं के बाद भी कोई सोम का बाल बांका नहीं कर पाया। कई मामलों में विवादित शराब निर्माता समूह सोम की मनमानी और उस पर मप्र सरकार की मेहरबानी का एक और ताजा मामला सामने आया है। कहने को तो यह एक मसला है, लेकिन उसमें ऐसी गड़बड़ियों के अनेक वो पहलू छिपे हुए हैं, जो किसी बड़ी मिलीभगत होने की तरफ साफ इशारा करते हैं। ताजा घटनाक्रम सोम डिस्टलरी में स्प्रिट के टैंकों से जुड़ा है। आबकारी विभाग ने बरसों बाद पिछले साल नवंबर के दूसरे पखवाड़े में सोम डिस्टलरी का निरीक्षण किया। इस दौरान पाया गया कि फैक्ट्री परिसर में **स्प्रिट के स्टोरेज** के नाम पर गंभीर किस्म की जानलेवा लापरवाही बरती जा रही थी। स्प्रिट के टैंक को खुले आसमान के नीचे बनाया गया है और उसकी हिफाजत के भी कोई प्रबंध नहीं किए गए हैं। स्प्रिट के इन टैंकों पर आबकारी विभाग का नियंत्रण होता है। लेकिन सोम ने जिस तरह इन टैंकों को डिजाइन किया है, उसमें आबकारी

स्प्रिट वाले वाहनों में ई-लॉक

स्प्रिट के परिवहन के दौरान होने वाले फर्जीवाड़े को रोकने के लिए आबकारी विभाग ने कुछ ऐसे प्रावधान किए हैं, जिससे उन पर नजर रखी जा सके। पेट्रोलियम कंपनी की तर्ज पर आबकारी विभाग ने यह ई-लॉक सिस्टम लागू किया है। गंतव्य स्थल के 20 से 25 किमी की रेंज में आने के बाद संबंधित ऑफिसर-इन चार्ज के मोबाइल पर ओटीपी से ही यह ई-लॉक खुलता है। टैंकर को खोलने के प्रयास पर इसका अलर्ट सर्वर पर आ जाएगा। इससे रास्ते में स्प्रिट चोरी किए जाने की घटनाओं पर ब्रेक लगेगा। इसके अलावा ऑनलाइन परमिट की व्यवस्था की गई है। पहले परमिट की 4 कॉपी हाथ से लिखकर दी जाती थी, अब मैनुअल काम नहीं होगा, बल्कि ऑनलाइन परमिट जारी होंगे। इससे परमिट में फेरबदल नहीं हो सकेगी। इसके अलावा स्प्रिट का परिवहन करने वाले ट्रक में जीपीएस सिस्टम भी लगाया जा चुका है। जीपीएस लगने से विभाग को यह जानकारी मिलती रहेगी कि वाहन किस मार्ग से कहां तक गया है। इससे अवैध शराब के धंधे पर नकेल कसी जाएगी।

विभाग की स्प्रिट पर नियंत्रण में कोई खास भूमिका नहीं बचती है। सोम की फैक्ट्री में इन स्प्रिट टैंकों की सुरक्षा के नाम पर उसके आसपास केवल ढाई से तीन फिट की पैराफिट वॉल बनाकर ही खानापूर्ति कर दी गई थी।

यह राज्य आबकारी विभाग के नियमों का सीधा उल्लंघन था, **जिसका जिक्र विभाग** की जांच रिपोर्ट में भी साफ किया गया है। यहां से ही मनमानी और उसके संरक्षण की नई श्रंखला शुरू होती है। निरीक्षण बीते साल यानी 20 नवंबर, 2020 को किया गया था। गड़बड़ियां मिलीं तो विभाग ने सोम प्रबंधन से कहा कि वह एक महीने में इनमें सुधार कर इसकी सूचना दे। सोम समूह ने इस निर्देश को ताक पर रख दिया। सुधार करने की बजाय उसने आबकारी विभाग को एक खत लिखकर संबंधित नियमों में ही बदलाव का सुझाव दे डाला। विभाग ने इस पर सख्ती दिखाने के नाम पर भी रोचक कदम उठाया। उसने सोम के मालिक को 7 दिन में यह जवाब देने का निर्देश दिया कि स्प्रिट टैंक के मामले में क्यों न उसका लाइसेंस निरस्त कर दिया जाए। एक सप्ताह के नोटिस के खिलाफ सोम समूह जबलपुर हाईकोर्ट पहुंच गया। कोर्ट ने राज्य में वाणिज्यिक कर विभाग की प्रमुख सचिव को आदेश दिया कि वह इस मामले में हस्तक्षेप कर सुनवाई करें। अब आगे मामला और रोचक हो जाता है। सोम के प्रतिनिधि ने चालू साल की 28 जनवरी को प्रमुख सचिव दीपाली रस्तोगी से आधिकारिक रूप से मुलाकात की। इससे संबंधित सरकारी प्रोसीडिंग की एक लाइन गौरतलब है। प्रमुख सचिव के हवाले से लिखा गया है, इकाई (सोम की फैक्ट्री) के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल और रेक्टिफायड स्प्रिट उसी श्रेणी के हैजर्डस मटेरियल (घातक पदार्थ) की श्रेणी में आते हैं, जिस श्रेणी में पेट्रोल को रखा गया है। यानी यूनिट ने भी प्रमुख सचिव के सामने यह माना कि उसके यहां जिस स्प्रिट को असुरक्षित तरीके से रखना पाया गया था, वह पेट्रोल की तरह भयानक ज्वलनशील और विस्फोटक फितरत वाली होती है। सोम ने **इसके विपरीत दलील दी कि यह एमएसआईएचसी नियम डिस्टलरियों पर लागू होता है।** जब खुद डिस्टलरी का प्रबंधन ही यह दलील दे रहा है कि टैंकों में संग्रहित स्प्रिट पेट्रोलियम पदार्थ की तरह ही ज्वलनशील है तो फिर उससे पेट्रोलियम पदार्थों के संग्रहण के लिए लगने वाला लाइसेंस भी तो मांगा जाना चाहिए।

मप्र सहित देश की किसी भी अन्य डिस्टलरी में स्प्रिट को खुले टैंकों में संग्रहित नहीं किया जाता है। सभी जगह कवर्ड स्टोरेज हैं और हर जगह यह आबकारी विभाग के अधीन होते हैं। इस मामले में यह भी गौर किया जाना चाहिए कि मुरैना में **जहरीली शराब कांड में स्प्रिट** की तस्करी ही एक खास वजह थी। उसी से शराब का निर्माण कर सस्ते में बेचा जा रहा था। ऐसे में यह उम्मीद की जा रही थी कि प्रमुख सचिव घोषित रूप से ज्वलनशील और विस्फोटक स्प्रिट के रखरखाव को लेकर वे सख्त कार्रवाई करेंगी। लेकिन प्रमुख सचिव ने मामले के निपटारे के लिए केंद्र सरकार को पत्र भेजने का सुझाव दिया है, जिसमें कहा जाएगा कि केंद्र मप्र की आसवनियों पर भी एमएसआईएचसी नियम लागू करे।

सोम डिस्टलरी के असली डायरेक्टर कौन?

सोम डिस्टलरी का असली मालिक या असली डायरेक्टर कौन है, यह भी सवालों के घेरे में है। क्योंकि 30 करोड़ के जीएसटी चोरी के मामले में जब सोम डिस्टिलरीज के सीईओ जगदीश अरोरा और उनके भाई

अजय अरोरा को गिरफ्तार किया गया था, तो उन्होंने हाईकोर्ट में कहा कि वे कंपनी के डायरेक्टर नहीं हैं। उनके इस कथन के आधार पर उन्हें जमानत दी गई थी। लेकिन हैरानी की बात यह है कि सोम डिस्टलरी का डायरेक्टर नहीं होने के बाद भी जगदीश अरोरा वाणिज्यिक कर विभाग की प्रमुख सचिव के साथ बैठक में शामिल हुए थे। गौरतलब है कि हाईकोर्ट ने निर्देश दिया था कि सोम डिस्टलरी इस मामले में वाणिज्यिक कर विभाग के साथ चर्चा करे। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद जगदीश अरोरा बैठक में शामिल हुए थे। ऐसे में सवाल उठता है कि जब अरोरा सोम डिस्टलरी के डायरेक्टर नहीं हैं, तो फिर वे किस हैसियत से बैठक में शामिल होने गए थे।

अब बिल देने पर विचार

सरकार जहरीली शराब से होने वाली मौतों पर अंकुश लगाने के लिए तरह-तरह के जतन कर रही है। लेकिन आबकारी एक्ट में सबसे बड़ी विसंगति यह है कि **शराब खरीदी पर बिल देने का कोई प्रावधान ही नहीं है।** ऐसे में अगर किसी की शराब पीने से मौत होती है तो इसका कोई प्रमाण नहीं होता है कि उक्त व्यक्ति ने शराब कहां से खरीदी थी। सवाल उठता है कि आखिरकार बिल देने में क्या दिक्कत है? दरअसल, बिल का प्रावधान नहीं होने के कारण **ठेकेदार एमआरपी से भी अधिक दाम पर शराब** धड़ल्ले से बेचता है। यही नहीं अगर बिल देना पड़ेगा तो उसे **स्टॉक भी मेंटेन करना पड़ेगा।** सूत्रों का कहना है कि सरकार इस कोशिश में है कि अब शराब के भी बिल दिए जाएं। आबकारी विभाग के अधिकारियों की शासन स्तर पर 3 मीटिंग हो चुकी है। साथ ही मुरैना जहरीली शराबकांड की जांच के लिए गठित एसआईटी की रिपोर्ट में भी इस बात को हाईलाइट किया गया है कि ग्राहक को बिल देना चाहिए। विदेशों में शराब की खरीदी पर बिल दिया जाता है।

● **कुमार राजेंद्र**

बीयर बनाने वाली ब्रांडेड कंपनियों की बोतल का दोबारा उपयोग

प्रदेश में शराब के कारोबार में किस तरह की भर्राशाही है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि प्रदेश में बीयर निर्माण करने वाली तीनों कंपनियां किसी भी ब्रांड की बीयर बना देती हैं। वेंडर की मांग पर वे वेंडर द्वारा तय ब्रांड की बीयर बना देती हैं। यही नहीं प्रदेश में बीयर बनाने वाली कंपनियां ब्रांडेड कंपनियों की बोतल का दोबारा उपयोग कर उसमें बीयर भरकर बेचती हैं। इस मामले में **इंदौर हाईकोर्ट में एक पीआईएल लगाई गई थी।** उस पर 7 नवंबर 2020 को सुनवाई करते हुए कोर्ट ने निर्देश दिया था कि ट्रेडमार्क एक्ट, 1999/कॉपीराइट एक्ट, 1975/ डिजाइंस एक्ट, 2000 के अंतर्गत रजिस्टर्ड बोतल/ किसी विनिर्माणी इकाई द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली कांच की बोतल जिस पर उसका लोगो उक्त अधिनियमों के अंतर्गत उत्कीर्ण/इमवोस है, ऐसी कांच की बोतल का उपयोग किसी अन्य विनिर्माण इकाई द्वारा अपने ब्रांड या लेबल की बीयर की भराई हेतु नहीं किया जाए। न ही उन पर उत्कीर्ण/इमवोस को मिटाकर या स्क्रेच कर बीयर की भराई हेतु उपयोग में नहीं लिया जाए। कोर्ट के आदेश के बाद 25 नवंबर 2020 को जब आबकारी विभाग के उड़नदस्ते ने सोम डिस्टलरी एंड ब्रेवरीज **रोजराचक रायसेन** का निरीक्षण किया तो वहां ब्रांडेड कंपनियों की बीयर की बोतलें मिलीं। इन बोतलों पर अंकित कंपनियों के नाम और चिन्ह को स्क्रेच कर मिटा दिया गया था और इनमें बीयर भर दी गई थी। बी-3 इकाई में 2,18,723 पेटियां बीयर तथा **एफएल 9ए इकाई में 20141 पेटियां मिलीं,** जिन पर पावर, ब्लैकफोर्ट लिखा हुआ था, जिसे मिटाने की कोशिश की गई थी। इस तरह यहां **1,41,652 पेटियां पाई गईं जिसमें दूसरी कंपनियों की बोतल में भरी बीयर थी।** पिछले 3 माह से ये पेटियां वैसे ही सील करके रखी हुई हैं। मार्केट कीमत की करीब 30 करोड़ की यह बीयर पड़ी हुई है, जो कुछ समय बाद अमानक हो जाएंगी।

खंड-खंड हो रही कांग्रेस

मप्र में कांग्रेस के हाथ से प्रदेश की सत्ता की चाबी क्या गई मानो पार्टी की सुख शांति ही चली गई। कभी एक सुर में कमलनाथ के नेतृत्व में एकसाथ नजर आने वाले मप्र कांग्रेस के नेता अब अलग-थलग खड़े दिखाई देते हैं। सत्ता परिवर्तन के बाद से शुरू हुआ नेताओं की नाराजगी और गुटबाजी का सिलसिला उपचुनाव में मिली हार के बाद और भी बढ़ता दिखा और अब हालात ऐसे हैं कि नगरीय निकाय चुनाव से पहले गुटबाजी और तेज होने लगी है।

कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी खत्म होने का नाम नहीं ले रही। जब तक ज्योतिरादित्य सिंधिया थे तब तक कांग्रेस में खेमेबाजी का ठीकरा सिंधिया के सिर फोड़ा जाता रहा। अब सिंधिया भाजपा के राज्यसभा सदस्य हो गए हैं, लेकिन कांग्रेस की गुटबाजी खत्म होने की बजाय और ज्यादा बढ़ गई है। पूरे प्रदेश में कांग्रेस की सबसे मजबूत स्थिति ग्वालियर-चंबल संभाग में हैं। जल्द ही नगरीय निकाय चुनाव आ रहे है और ऐसे में भी मुरैना से लेकर श्योपुर, भिंड आदि जिलों में कांग्रेसी नेताओं की राजनीति अपनी डफली, अपना राग की तर्ज पर चल रही है, जिसने कांग्रेस को खंड-खंड का कर दिया है।

मुरैना में कांग्रेस के पास तीन अध्यक्ष है। सबसे आगे जिला अध्यक्ष व विधायक राकेश मावई हैं, फिर शहर जिला अध्यक्ष दीपक शर्मा और कार्यकारी जिला अध्यक्ष विष्णु अग्रवाल हैं। हालत यह है कि दीपक शर्मा कोई आंदोलन करते हैं तो उसमें विधायक राकेश मावई व कार्यकारी अध्यक्ष विष्णु अग्रवाल शामिल नहीं होते। जब विष्णु अग्रवाल का खेमा कोई आयोजन-प्रदर्शन करता है तो किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष व शहर अध्यक्ष दीपक शर्मा दूर-दूर तक नजर नहीं आते। अंदर खानों में इन दोनों गुटों में जमकर खींचतान चल रही है। पिछले दिनों पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने जहरीली शराब से मारे गए 27 मृतकों के स्वजनों को 50-50 हजार रुपए के चेक पूर्व मंत्री डॉ. गोविंद सिंह के हाथों वितरण को भिजवाए। इनके वितरण में विधायक राकेश मावई शरीक नहीं हुए, इसके बाद सीनियर नेताओं ने इस गुटबाजी की शिकायतें कमलनाथ व दिग्विजय सिंह तक भी पहुंचाई गई हैं।

श्योपुर जिला कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष रामनिवास रावत का गृह जिला है। पहले यहां सिंधिया व दिग्गी गुट में खींचतान थी। अब यहां सिंधिया समर्थक कोई बचा नहीं, फिर भी कांग्रेस की गुटबाजी पहले से ज्यादा खुलकर आ गई है। रामनिवास रावत व जिला अध्यक्ष अतुल चौहान का एक गुट है तो दूसरा गुट विधायक बाबू जंडेल व उनके समर्थकों का है। विरोध का आलम यह है कि रामनिवास व अतुल ने नपा प्रत्याशी के तौर पर सुजीत गर्ग की पत्नी का नाम आगे बढ़ाया तो विधायक जंडेल सुजीत गर्ग को नकली पिछड़ा वर्ग प्रत्याशी बताकर खुलकर विरोध में आ गए और इस दौरान किसी दूसरे प्रत्याशी का नाम भी वह सामने नहीं ला रहे। रावत के बेटे को युकां का जिला अध्यक्ष बनाया तो बाबू जंडेल व उनके समर्थकों ने खुलकर विरोध किया और इसे नियम विरूद्ध बताया। पिछले दिनों जंडेल समर्थक व जिला उपाध्यक्ष राहुल चौहान ने जिला अध्यक्ष अतुल चौहान को भाजपा समर्थित बताते हुए फेसबुक पर कई पोस्ट कर डालीं।

भिंड जिले में कांग्रेस के दो धड़े हैं, जिनमें एक गुट जिला अध्यक्ष जयश्री राम बघेल का है और दूसरा गुट लहार विधायक व पूर्व मंत्री डॉ. गोविंद सिंह समर्थकों का है। दोनों गुटों में आपसी संघर्ष का आलम यह है कि जिलाध्यक्ष बघेल ने करीब दो महीने पहले डॉ. गोविंद सिंह को पार्टी से निष्कासित करने का ठहराव प्रस्ताव ही पास कर दिया था। दतिया में कांग्रेस की अजीब हालत है। यहां एक गुट सेवढ़ा विधायक घनश्याम सिंह का और दूसरा धड़ा पूर्व विधायक राजेंद्र भारती का है। राजेंद्र भारती व उनके समर्थक, गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा के धुर विरोधी हैं जो हर स्तर पर मिश्रा का विरोध करते हैं, लेकिन सेवढ़ा विधायक घनश्याम सिंह का रुख नरोत्तम मिश्रा व भाजपा के प्रति हमेशा नरम रहता है। ऐसे में इस धड़े पर आरोप लगते रहते हैं कि यह भाजपा के हाथों की कठपुतली है। कार्यकारी अध्यक्ष, मप्र कांग्रेस रामनिवास रावत कहते हैं कि नगरीय निकाय चुनाव के टिकटों की दावेदारी के कारण ऐसा दिख रहा है। यह मनभेद हो सकते हैं, लेकिन जब टिकट फाइनल हो जाएगा तो सभी पदाधिकारी व कार्यकर्ता एक झंडे के नीचे काम करेंगे। पार्टी में गुटबाजी जैसी बात न तो पहले थी न अब है।

● **अरविंद नारद**

विचारधारा के संकट में उलझी कांग्रेस

मप्र कांग्रेस में खेमेबंदी नई बात नहीं है लेकिन नाथूराम गोडसे के समर्थक और हिंदू महासभा के सदस्य रहे बाबूलाल चौरसिया को सदस्यता देकर कांग्रेस नेतृत्व विचारधारा के संकट में उलझ गया है। गोडसे समर्थक का विरोध कर रहे नेता इसे पार्टी की विचारधारा से हटकर किया गया कार्य बता रहे हैं तो कमलनाथ खेमे के नेता इस कदम को सही ठहरा रहे हैं। भाजपा नेता इस स्थिति पर कटाक्ष कर रहे हैं। वे महात्मा गांधी के अहिंसावादी सिद्धांत का पालन करने में कांग्रेस की मंशा पर सवाल उठा रहे हैं। बाबूलाल चौरसिया को कांग्रेस में लाने को लेकर पार्टी में गतिरोध जारी है। चौरसिया के समर्थन और विरोध में एक पक्ष प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ के साथ है तो दूसरा पक्ष पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अरुण यादव के उस बयान का समर्थन कर रहा है, जिसमें उन्होंने चौरसिया का विरोध किया था। इसी कड़ी में होशंगाबाद जिला कांग्रेस अध्यक्ष सत्येंद्र फौजदार ने कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी, पार्टी के प्रदेश प्रभारी मुकुल वासनिक और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ को पत्र लिखकर प्रदेश कांग्रेस के मीडिया विभाग के पूर्व अध्यक्ष मानक अग्रवाल को पार्टी से निष्काषित करने की मांग की है। मालूम हो, अग्रवाल ने कमलनाथ पर गंभीर आरोप लगाए थे। पार्टी से जुड़े सूत्रों का कहना है कि इस मामले में भाजपा और कांग्रेस के सहयोगी दल भी पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व से जवाब मांगेंगे। इस स्थिति में जवाब देना आसान नहीं होगा, क्योंकि गोडसे की विचारधारा का विरोध और महात्मा गांधी के आदर्शों पर चलना ही कांग्रेस की राजनीति का आधार है। उधर, यह भी कहा जा रहा है कि नगरीय निकाय चुनाव से पूर्व पार्टी के भीतर उठे बवंडर को युवा और उम्रदराज नेताओं के बीच टकराव के तौर पर भी देखा जाना चाहिए।

अब ऐलान का इंतजार

मप्र में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव के लिए भाजपा, कांग्रेस सहित तमाम राजनीतिक दल ही नहीं, राज्य निर्वाचन आयोग भी पूरी ताकत से तैयारियों में जुटा हैं। हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ के निकाय चुनाव जल्द कराने के आदेश के बाद तो इस काम में युद्धस्तर पर तेजी आई है। भाजपा जहां जिताऊ उम्मीदवारों की तलाश के साथ बैठकों के जरिए कार्यकर्ताओं के कान में 'बूथ जीता तो चुनाव जीता' का मंत्र फूंकने में जुटी हैं, तो कांग्रेस में भी बैठकों का सिलसिला शुरू है। पार्टी को ईवीएम पर भरोसा नहीं है, लिहाजा वह मतपत्रों के माध्यम से निकाय चुनाव कराने की मांग कर रही है। उधर, राज्य निर्वाचन आयोग ने 3 मार्च को मतदाता सूचियां घोषित करने की बात कही है। इसके बाद आयोग कभी भी नगरीय निकाय चुनावों की तारीखों की घोषणा कर सकता है। यह चुनाव अप्रैल के आखिरी हफ्ते से शुरू होकर मई के पहले हफ्ते तक कराए जाने की संभावना है। अगर ऐसा होता है तो इन्हीं दिनों में कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक की परीक्षाएं भी चल रही होंगी, इसी दौरान चुनावी भोंपुओं का शोर छात्रों के भविष्य को बर्बाद कर सकता है। अगर आयोग इन परीक्षा तिथियों को संज्ञान में लेता है, तो संभावना है कि चुनाव की तारीखें दो महीने और टाल दी जाएं।

बता दें कि राज्य में करीब डेढ़ साल से नगरीय निकायों का कार्यकाल खत्म हो चुका है और एक साल से भी अधिक समय से प्रशासकीय व्यवस्थाओं के आधार पर निकायों का कामकाज संचालित किया जा रहा है। राज्य में कुल 407 नगरीय निकाय हैं, जहां चुनाव होने हैं। इनमें 16 नगर निगम, 99 नगर पालिकाएं और 292 नगर परिषद शामिल हैं। संविधान में स्पष्ट प्रावधान है कि नगरीय निकाय हों या पंचायत निकाय, कार्यकाल पूरा होते ही चुनाव कराए जाने चाहिए। कार्यकाल समाप्त होने की स्थिति में प्रशासक की नियुक्ति अधिकतम 6 माह के लिए हो सकती है, लेकिन मप्र में करीब डेढ़ साल से यह चुनाव कतिपय कारणों से टल रहे हैं। पहले कमलनाथ सरकार ने चुनाव की तारीख बढ़ाई और बाद में शिवराज सरकार भी इसे टालती रही। इसके बाद कोरोना महामारी के चलते चुनाव आगे बढ़ाने का फैसला लिया गया था। सरकार की मंशा छह महीने तक चुनाव टालने की थी, लेकिन अन्य राज्यों में निकाय चुनाव हो जाने का हवाला देते हुए लगाई गई याचिकाओं पर हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ का फैसला आ गया।

राज्य निर्वाचन आयोग की तैयारियों पर नजर डालें तो जिला निर्वाचन कार्यालयों में दावे-आपत्तियों का निराकरण कर वोटर लिस्ट को अंतिम रूप दिया जा रहा है। वोटर लिस्ट में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां सामने आई हैं। सूची में मृत लोगों के नाम तक बड़ी संख्या में जुड़े हैं। बता दें कि हाल ही प्रोटेम स्पीकर रहे रामेश्वर शर्मा ने कहा था कि घर-घर जाकर वोटर की पड़ताल किए बिना मतदाता सूचियों को ठीक नहीं किया जा सकता, इस बार राज्य में यह काम कहीं नहीं किया गया है। सूचियां वैसी बन रहीं, जैसे अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम की प्रेमिका मोनिका बेदी का भोपाल से पासपोर्ट बन गया था। आखिर वास्तविक वोटरों को मताधिकार से वंचित तो नहीं किया जा सकता।

तय समय के लगभग डेढ़ साल बाद अप्रैल-मई में प्रस्तावित नगरीय निकाय चुनाव एक बार फिर टाले जा सकते हैं। इसके पीछे दो वजहें बताई जा रही हैं। पहली तो अप्रैल-मई में 10वीं-12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के अलावा 9वीं और 11वीं की परीक्षाएं भी चल रही होंगी। ऐसे में चुनावी शोर तो छात्रों को डिस्टर्ब करेगा और दूसरे अप्रैल और मई के पहले सप्ताह में दो या तीन चरणों में चुनाव कराए जाते हैं, तो मतदान केंद्र कहां बनेंगे, क्योंकि ज्यादातर मतदान केंद्र तो स्कूल या कॉलेजों में बनाए जाते हैं और उनमें शिक्षकों की ड्यूटी लगाई जाती है। कहा यह भी जा रहा है कि चुनाव तारीखें टलने से राजनीतिक दलों को तैयारियों का और मौका मिल जाएगा। क्योंकि कांग्रेस निकाय चुनाव में पिछला प्रदर्शन सुधारने और भाजपा प्रदर्शन को दोहराने के लिए अतिरिक्त समय चाहती हैं, हालांकि ऐसा प्रदर्शित दोनों में से कोई भी दल नहीं कर रहा है। बता दें कि 2014-15 में जब प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव हुए थे, तो राज्य के सभी 14 नगर निगमों में भाजपा का कब्जा था, अधिकांश नगरपालिकाओं और नगर परिषदों में भी भाजपा बहुमत में थी। इस प्रदर्शन को दोहराने के लिए अतिरिक्त तैयारियों की जरूरत महसूस की जा रही है।

● **प्रवीण कुमार**

एक्शन मोड में पार्टियां

नगरीय निकाय चुनावों में कांग्रेस, भाजपा, सपा, बसपा, शिवसेना सहित तमाम दलों के उम्मीदवार और निर्दलीय प्रत्याशी मैदान में होंगे। हर दल ने एक सूत्रीय सिद्धांत अपनाया है कि जिताऊ छवि वाला ही उम्मीदवार बनकर मैदान में उतरेगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, वीडी शर्मा से लेकर तमाम वरिष्ठ नेता जिला, संभाग और बूथ स्तर तक लगातार बैठकें ले रहें हैं। कल तक केवल युवा चेहरों को ही संगठन और निकाय चुनाव में तरजीह देने की बात कहने वाले भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के सुर भी सतना में हुई बैठक में बदले नजर आए, उनका कहना था कि उन्हें 60 की उम्र वाले नेताओं से भी कोई परहेज नहीं है। महापौर, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पार्षद के लिए टिकट जिताऊ चेहरे को ही मिलेगा। बता दें कि भाजपा ने तीन चरणों की प्रक्रिया में उम्मीदवारों के चयन का फैसला किया है। सबसे पहले पार्टी की जिले की चुनाव समिति नगर परिषद के टिकट तय करेगी। दूसरा- संभाग स्तर पर नगर पालिका और पार्षदों के नामों को मंजूरी मिलेगी। तीसरा- महापौर का चुनाव राज्य स्तर की चुनाव समिति तय करेगी। निकाय चुनाव के लिए कांग्रेस की तैयारियों पर नजर डालें तो वह भाजपा के मुकाबले काफी पिछड़ी दिखती है। अपने-अपने स्तर पर दिग्विजय, कमलनाथ, अरुण यादव जैसे वरिष्ठ नेता जोर मारते दिखते हैं। लेकिन गुटबाजी से पार्टी उबर नहीं पा रही। पिछले दिनों भोपाल में हुई बैठक के दौरान कांग्रेस नेताओं की आपस में जूतम-पैजार जैसी घटनाओं से जनता में गलत संदेश गया है। संभवतः यही वजह है कि कांग्रेस को इस चुनाव में ईवीएम पर भरोसा नहीं रह गया है। दिग्विजय सिंह ने राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त बीपी सिंह को ज्ञापन सौंपकर नगरीय निकाय चुनाव ईवीएम की जगह मतपत्रों से कराने की मांग की है, जिसे उन्होंने अस्वीकार कर दिया।

बिजली की बिगड़ी चाल

मप्र में अपनी आवश्यकता से अधिक बिजली का उत्पादन किया जाता है। प्रदेश में अधिकतर बिजली निजी क्षेत्रों के संयंत्रों में उत्पादित हो रही है। इसका असर यह हो रहा है कि प्रदेश में सरकारी बिजली संयंत्रों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इससे प्रदेश में बिजली उत्पादन के लिए दो साल पहले शुरू हुई इकाईयों (प्लांट) में तकनीकी खराबी आई। सुधार कार्य पर मप्र पॉवर जनरेशन कंपनी ने 6 हजार 600 करोड़ रुपए खर्च भी कर दिए। बावजूद इसके प्रदेश को बिजली नहीं मिल पा रही है। क्योंकि दोनों ही इकाईयों में बिजली का उत्पादन फिलहाल ठप है। तकनीकी खराबी की वजह से 1320 मेगावाट बिजली का उत्पादन प्रभावित हो रहा है। इकाईयों के टरबाइन में तकनीकी खराबी बताई जा रही है।

हैरानी की बात ये है कि कंपनी के अफसरों ने इकाईयों को गारंटी अवधि में जांच ही नहीं करवाया। अब इकाईयों में आई खराबी को सुधारने के लिए करीब 115 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय बताया जा रहा है। इस संबंध में राजेंद्र अग्रवाल ने नियामक आयोग को पत्र लिखा है। जिसमें आरोप लगाया कि सिंगाजी ताप विद्युत गृह परियोजना गृह चरण-2 की इकाईयां अत्यंत तेज गति से निर्धारित समय पर स्थापित किया गया है। इन इकाईयों में तीन नंबर की इकाई को 47 माह और चार नंबर को 51 माह में क्रियाशील किया गया है। मौजूदा दौर में प्लांट की दो इकाइयों में एचपी टरबाइन की तकनीकी खराबी है। इस वजह से अगस्त और सितंबर 2020 से प्लांट में उत्पादन बंद है। इससे ऐसा लग रहा है कि इकाइयां जल्द क्रियाशील करने की वजह से तकनीकी मापदंड, सुरक्षा मानकों की अनदेखी की गई है।

सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना की दो इकाइयों में तकनीकी खराबी आने के कारण उत्पादन बंद है। मप्र पॉवर जनरेटिंग कंपनी का खराबी की वजह से 1320 मेगावाट बिजली का उत्पादन प्रभावित हो रहा है। पॉवर जनरेशन कंपनी का दावा है कि सुधार होने पर मार्च और अप्रैल माह से बिजली का उत्पादन दोनों इकाईयों से दोबारा प्रारंभ हो जाएगा। प्रबंध संचालक मप्र पॉवर जनरेशन कंपनी मनतीज सिंह कहते हैं कि श्रीसिंगाजी पॉवर प्लांट की तीन और चार नंबर यूनिट का परमानेंट गारंटी टेस्ट किन्हीं कारणों से कंपनी नहीं करवा पाई। खराबी की वजह जानने के लिए टीम का गठन किया गया है। जल्द सुधार होकर बिजली उत्पादन होगा।

मप्र में बिजली का खेल कुछ इस तरह चल रहा है कि अफसरों की भर्राशाही का खामियाजा जनता को उठाना पड़ रहा है। बिजली बिलों पर सब्सिडी अब बिजली कंपनी को भारी पड़ रही है। सब्सिडी का ये पैसा सरकार से मिलता है जो अभी 14 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा हो चुका है। यदि जल्द कंपनियों को ये रकम नहीं मिली तो वित्तीय स्थिति चिंताजनक हो सकती है। यूनाइटेड फोरम फॉर पॉवर एम्पलाइज एंड इंजीनियर्स के इंजीनियर वीकेएस परिहार ने इस संबंध में मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी है। जिसमें वित्तीय स्थिति मजबूत बनाने को कहा गया है। उनके अनुसार राज्य सरकार मौजूदा वित्तीय वर्ष में बिजली कंपनियों को 14,338 करोड़ रुपए की कर्जदार हो गई है। यह राशि उपभोक्ताओं को दी जाने वाली सब्सिडी की है, जो सरकार बिजली कंपनियों को हर तीसरे महीने भुगतान करती है। कोरोना संक्रमण की वजह से राज्य सरकार ने ये राशि बिजली कंपनियों को भुगतान नहीं की जिस वजह से लेनदारी बढ़ गई। लगातार कंपनियां वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए राजस्व वसूली पर जोर दे रही है। इसके लिए जगह-जगह बिजली की सप्लाई काटी जा रही है। हर तरफ अधिकारियों को सख्ती के साथ वसूली के निर्देश दिए गए है। बताया जाता है कि मप्र पॉवर मैनेजमेंट कंपनी को अकेले मप्र पॉवर जनरेशन कंपनी को 6 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा देना शेष है। इधर पैसे नहीं मिलने की वजह से जनरेशन कंपनी को कोल कंपनियों का भुगतान रोकना पड़ रहा है। सरकार हर माह 1100 करोड़ यानी हर साल लगभग 13 हजार करोड़ रुपए की सब्सिड़ी बाटती है। बिजली कंपनियां सरकार की घोषणा पर उपभोक्ताओं को सीधे सब्सिडी का लाभ देती है।

पिछले वित्तीय वर्षों का राज्य सरकार पर 3,016 करोड़ की सब्सिडी बकाया है। वहीं साल 2019 में सरकार को 17,506 करोड़ रुपए की सब्सिडी देनी थी, जिसमें से 13,870 करोड़ की देनदारी देने के बाद 3,636 करोड़ रुपए की सब्सिडी देना बाकी है। वर्ष 2020-21 में नवंबर 20 तक 7,685 करोड़ की राशि बकाया है। इस तरह राज्य सरकार पर अब तक बिजली कंपनियों का सब्सिडी का 14,338 करोड़ रुपए बकाया है। राज्य सरकार ऊर्जा विभाग द्वारा इंदिरा गृह ज्योति योजना, इंदिरा किसान ज्योति योजना के अलावा निशुल्क विद्युत प्रदाय योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना में सब्सिडी दे रही है। इसमें किसानों को अकेले करीब 90 फीसदी सब्सिडी मिलती है।

● **नवीन रघुवंशी**

बकाए का बोझ बढ़ा

बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) पर बकाए का बोझ काफी बढ़ गया है। दिसंबर 2020 इन कंपनियों पर बिजली उत्पादक कंपनियों का बकाया साल-दर-साल आधार पर करीब 24 प्रतिशत बढ़कर 1,36,966 करोड़ रुपए हो गया। इससे पॉवर सेक्टर की खराब होती स्थिति का पता चलता है। एक साल पहले यानी, दिसंबर 2019 में डिस्कॉम पर पावर जनरेशन कंपनियों का कुल बकाया 1,10,660 करोड़ रुपए था। दिसंबर का बकाया हालांकि नवंबर के मुकाबले घट गया है। नवंबर 2020 में डिस्कॉम पर जनरेशन कंपनियों का कुल 1,40,741 करोड़ रुपए का बकाया था। बकाए के ये आंकड़े पेमेंट रेटिफिकेशन एंड एनालिसिस इन पॉवर प्रॉक्योरमेंट फॉर ब्रिंगिंग ट्रांसपेरेंसी इन इनवॉयसिंग ऑफ जनरेटर्स के पोर्टल से लिए गए हैं। प्राप्ति पोर्टल मई 2018 में लांच किया गया था। उत्पादन और वितरण कंपनियों के पावर पर्चेज ट्रांजेक्शन में पारदर्शिता लाने के लिए यह पोर्टल बनाया गया है।

देश के हृदय प्रदेश मप्र के सौंदर्य को राष्ट्रीय ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिल रही है। मप्र के प्राकृतिक सौंदर्य से भरे क्षेत्र इन दिनों बॉलीवुड को खूब भा रहे हैं। राजधानी भोपाल सहित प्रदेशभर के मनोरम दृश्य वाले क्षेत्रों में इन दिनों फिल्मों, सीरियल्स, वेब सीरीज की शूटिंग चल रही है। ऐसे में सरकार ने प्रदेश का राजस्व बढ़ाने के लिए फिल्म शूटिंग का शुल्क लेना शुरु कर दिया है।

फिल्म शूटिंग से राजस्व

मप्र देश के सबसे सुंदर राज्यों में से एक है। यहां का प्राकृतिक सौंदर्य इन दिनों बॉलीवुड के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। प्रदेश के लगभग हर शहर में फिल्मों की शूटिंग की जा रही है। इनमें से महेश्वर भी फिल्म मेकर्स की पसंद बना हुआ है। ऐसे में प्रदेश सरकार ने यहां फिल्म की शूटिंग से राजस्व कमाने का रास्ता निकाला है। निमाड़ के महेश्वर में शूटिंग करने के लिए अब शुल्क चुकाना होगा। प्रीवेडिंग शूट के साथ ही ड्रोन से या फिर अन्य कोई भी शूटिंग के लिए प्रशासन ने शुल्क तय कर दिया हैं। महेश्वर के अलावा आसपास के भी कुछ मनोहारी स्थानों पर शुल्क चुकाकर अनुमति मिलने के बाद ही शूटिंग की जा सकेगी। एक तथ्य यह भी है कि निमाड़ में नर्मदा किनारे घाटों पर शूटिंग के लिए कुछ सुविधाएं मुहैया कराकर सरकार अच्छा खासा राजस्व अर्जित कर सकती है।

जिला पर्यटन, पुरातत्व एवं संस्कृति समिति ने महेश्वर को कैमरे की नजर से देखने के लिए और विश्व पटल पर दिखाने के लिए शुल्क निर्धारित कर दिया है। अब महेश्वर स्थित किला एवं घाट स्थलों को शूट कर उसका उपयोग अन्य उद्देश्य के साथ करने के लिए शूटिंग दर निर्धारित कर ली है। वैसे भी महेश्वर अब मात्र एक घाट और किले का द्वार नहीं है, बल्कि कई बड़ी फिल्मों के निर्माता एवं निर्देशक अपनी फिल्मों में महेश्वर व मां नर्मदा की सुंदरता दिखाने के लिए शूटिंग करने लगे है। पिछले वर्षों से महेश्वर में शूटिंग करने का एक रिवाज सा बन गया है। यहां न सिर्फ प्रीवेडिंग, टीवी सीरियल, वेब सीरीज बल्कि बड़े-बड़े बैनरों की फिल्में शूट की जाने लगी है।

वैसे तो महेश्वर के दृश्यों की शूटिंग करने का सिलसिला आज से 50 वर्ष पूर्व 1970 में महाशिवरात्रि नामक फिल्म से शुरू हुआ था, जिसके बाद तुलसी, गौतमी पुत्र शतकर्णी, अशोका द ग्रेट, यमला पगला दीवाना, यमला पगला दीवाना-2, मणिकर्णिका, तेवर, जिनियस, पेडमेन, दबंग-3, कलंक सहित अन्य फिल्में व धारावाहिक सीरियलों की शूटिंग की जा चुकी है। जिला स्तरीय समिति की बैठक में महेश्वर किला व घाट के साथ ही मंडलेश्वर अनुभाग के अन्य स्थानों के लिए फोटो शूट व शूटिंग के लिए शुल्क निर्धारित किया गया है।

निमाड़ में महेश्वर के अलावा ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर और इसके आसपास का इलाका भी मनोहारी है। ओंकारेश्वर में ही बिजली कारखाना और पर्वत श्रेणी किसी भी फिल्म की शूटिंग के लिए बेहतर स्थान हो सकते है। इसके पास ही एशिया का सबसे बड़ा इंदिरा सागर जलाशय और हनुवंतिया भी मौजूद है। इंदिरा सागर बांध के बैकवॉटर में विकसित कई टापू भी फिल्मों की शूटिंग के लिए उपयुक्त हो सकते है। इनमें से कुछ स्थानों को विकसित किया जा चुका है। ऐसे में सरकार फिल्म इंड्रस्टी को पहले से ही आकर्षित करने का प्रयास कर रही है और आने वाले समय में यहां भी सकारात्मक परिणाम देखने को मिल सकते है।

समिति द्वारा प्रीवेडिंग शूट ड्रोन कैमरे के साथ, फिल्म शूटिंग, बड़ी फिल्मों की शूटिंग, महेश्वर किला एवं घाट स्थलों तथा किला व घाट के अतिरिक्त अनुभाग के लिए भी शुल्क निर्धारित किया गया है। अब प्रीवेडिंग शूटिंग ड्रोन कैमरे के साथ महेश्वर निवासी के लिए 4 हजार रुपए प्रतिदिन व महेश्वर से बाहरी क्षेत्र के निवासी के लिए 6 हजार रुपए (प्रतिदिन) शुल्क अदा करना होगा। वहीं फिल्म शूटिंग के लिए एक दिन की अवधि तक के लिए 20 हजार, 2-3 दिवस की अवधि के लिए 35 हजार, तीन दिवस से अधिक अवधि के लिए (प्रतिदिन) 10 हजार रुपए और ड्रोन कैमरे से शूट करने के लिए मात्र एक बार के लिए 10 हजार रुपए देना होंगे। इसके अलावा बड़े बैनर की फिल्मों के लिए प्रथम 5 दिवस के लिए (प्रतिदिन) 50 हजार, 5 से 15 दिन (प्रतिदिन) 30 हजार, 15 दिनों से अधिक (प्रतिदिन) के लिए 10 हजार और ड्रोन से एक बार के लिए 10 हजार रुपए देना होंगे। गौरतलब है कि राजधानी भोपाल, ग्वालियर, बालाघाट के साथ ही प्रदेश के लगभग सभी शहरों में अलग-अलग स्थानों पर फिल्म की शूटिंग चलती रहती है। प्रदेश की ऐतिहासिक, धार्मिक इमारतों के अलावा यहां के वनक्षेत्र आकर्षण का केंद्र हैं।

● **रजनीकांत पारे**

महेश्वर किला व घाट के अतिरिक्त अनुभाग के लिए निर्धारित दर

समिति ने महेश्वर किला व घाट के अलावा मंडलेश्वर अनुभाग के अन्य स्थलों के लिए भी शुल्क निर्धारित किया है। यहां फिल्म शूटिंग एक दिन तक की अवधि के लिए 10 हजार, 2 से 3 दिनों की अवधि के लिए 15 हजार, 3 दिवस से अधिक (प्रतिदिन) के लिए 10 हजार और ड्रोन से मात्र एक बार के लिए 5 हजार रुपए शुल्क देना होगा। साथ ही बड़े बैनरों की फिल्मों के लिए 1 से 15 दिनों तक (प्रतिदिन) 20 हजार रुपए, 15 दिनों से अधिक (प्रतिदिन) के लिए 10 हजार और ड्रोन कैमरे से मात्र एक बार के लिए 10 हजार रुपए का शुल्क निर्धारित किया गया है। मप्र शासन द्वारा मप्र फिल्म पर्यटन नीति 2020 जारी की गई है, जिसमें प्रत्येक जिले में अपर कलेक्टर स्तर के अधिकारी को नोडल नियुक्त किया गया है। जिले में जिला पर्यटन, पुरातत्व एवं संस्कृति समिति ने नोडल अधिकारी अपर कलेक्टर को बीएस सोलंकी को नियुक्त किया गया है। नोडल अधिकारी इन स्थानों की वीडियो शूटिंग के लिए अनुमतियां प्रदान करेंगे।

मप्र में इन दिनों सत्ता, संगठन और संघ का समन्वय दिख रहा है। इसकी वजह यह है कि तीनों जगह उन नेताओं को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है, जो परिश्रम, नेतृत्व कौशल और समर्पण के बूते यहां तक पहुंचे हैं। इससे भाजपा संगठित नजर आ रही है। इसका असर यह हो रहा है कि उथल-पुथल के दौर में भी भाजपा के नेता एक नजर आ रहे हैं। इससे प्रदेश में भाजपा और मजबूत हो गई है।

सत्ता, संगठन और संघ का समन्वय

राजनीति में चुनौतियां आम बात है। जो नेता, जो पार्टी और जो संगठन चुनौतियों को पार पा लेता है, वह सत्ता पा लेता है। मप्र में भाजपा संगठन, सत्ता और संघ आपसी समन्वय से सारी चुनौतियों का न केवल सामना करते हैं, बल्कि उसे मात भी देते हैं। अपनी इसी समन्वयकारी राजनीति से भाजपा प्रदेश में सरकार को मजबूत बनाने में जुटी हुई है, ताकि वर्तमान दशक में उसका कोई बाल भी बांका न कर पाए। राजनीति के फर्श से सत्ता-संगठन के अर्श पर पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा अब मप्र में भाजपा को और मजबूत बनाने में जुट गए हैं। सत्ता और संगठन के प्रमुख इन दोनों नेताओं ने संघ के साथ समन्वय बनाकर मप्र में अगले एक दशक तक सरकार को निर्विघ्न चलते रहने का खाका तैयार किया है।

मप्र में शिवराज-वीडी की जोड़ी भाजपा को नए युग में ले जा रही है, जो नए दशक में प्रवेश कर चुकी है। ऐसे में मप्र में भाजपा का ग्राफ और बढ़ने की प्रबल संभावना है। यानी ये दशक मप्र में भाजपा के नाम होने वाला है, जिसकी कई वजहें भी हैं। सबसे बड़ी वजह है शिवराज की समन्वयकारी राजनीति। कभी प्रदेश की पगडंडियों पर पैदल घूमने वाले शिवराज वर्तमान में मुख्यमंत्री के तौर पर अपनी चौथी पारी खेल रहे हैं। लेकिन आज तक उन पर सत्ता का अहंकार नहीं चढ़ा है। वे आज भी अपने आप को भाजपा के कार्यकर्ता और जनता के सेवक के रूप में दर्शाते हैं। उनकी यही सादगी उनकी लोकप्रियता को बढ़ाती है। भाजपा के एक पदाधिकारी कहते हैं कि पार्टी में युवाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है। यह पार्टी के भविष्य के लिए अच्छी बात है। लेकिन युवाओं को मार्गदर्शन देने के लिए शिवराज जैसे नेतृत्व अतिआवश्यक हैं। इसलिए राजनीति में अपना कौशल दिखाने के लिए शिवराज सिंह चौहान के पास अभी पूरा एक दशक है।

संघ के एक स्वयंसेवक कहते हैं कि शिवराज ने अपने **अब तक के शासनकाल में** जिस तरह भाजपा को मजबूत आधार दिया है और अब चौथी पीढ़ी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य कर रहे हैं उससे मप्र को कम से कम एक दशक तक उनकी सरकार की जरूरत है। वह कहते हैं कि शिवराज ने मप्र के विकास का जो खाका खींचा है, उसे अमलीजामा पहनाना है। यह शिवराज के बिना संभव नहीं है। इसलिए भाजपा संगठन और संघ इस लक्ष्य के साथ काम कर रहे हैं कि कम से कम यह दशक शिव 'राज' का ही रहे। दरअसल, शिवराज ने अपने साथियों और खासतौर से भाजपा नेताओं का कद बढ़ाने का खुद ही हरसंभव प्रयास किया है। पिछले 15 सालों में पार्टी संगठन और सरकार में अपेक्षाकृत युवा लोगों को आगे बढ़ाया गया है। इसकी वजह यह है कि वे असुरक्षा की भावना से ग्रस्त नेता नहीं हैं। वे संघर्ष से निकलकर यहां तक पहुंचे हैं। उनकी ताकत लोगों का विश्वास और समर्थन है।

देश में पिछले डेढ़ दशक के राजनीतिक इतिहास पर नजर डालें तो हम यह पाते हैं कि देश में सत्ता, संगठन और संघ का जो समन्वय मप्र में देखने को मिलता है, वह किसी और राज्य में नहीं। भाजपा देश में 18 करोड़ सदस्यों का मजबूत नेटवर्क होने का दावा करती है। संघ के स्वयंसेवक के रूप में निस्वार्थ कार्यकर्ताओं की फौज है, जो विचारधारा के लिए लगातार सक्रिय

सभी को साधते शिवराज

शिवराज की एक बड़ी विशेषता यह है कि वे विरोध को भी अवसर में बदल देते हैं। विपक्ष ही नहीं, अपने दल में उभरे बागी सुरों को भी अवसर बनाने में माहिर। इसलिए भाजपा आलाकमान भी शिवराज सिंह चौहान को तवज्जो देना नहीं भूलता। वर्तमान में पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती शराबबंदी का मुद्दा उठाती हैं, तो चौहान मप्र को एक और सामाजिक अभियान के लिए तैयार करते हैं। शराबबंदी की दिशा वह नशामुक्ति में मोड़ते हैं। अब पूरे प्रदेश में नशामुक्ति के नारे बुलंद होंगे, संकल्प लिए जाएंगे। ठीक उसी तरह जैसे शिवराज ने पहले कार्यकाल में बेटी पढ़ाओ-बेटी बढ़ाओ अभियान का आगाज किया था। मप्र के मुरैना में शराब से हुई मौतों से गरमाई सियासत के बीच उमा अचानक पुराने तेवर में आ गईं। उन्होंने अपनी ही सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश की और कहा कि देश के अन्य एनडीए शासित राज्यों की तरह ही मप्र में भी शराबबंदी हो। कांग्रेस भी उनके साथ आने को आतुर हो गई। इससे भाजपा सरकार उलझती दिखी, लेकिन ऐसे ही मौके शिवराज को मास्टर स्ट्रोक का मौका देते रहे हैं।

है। यही भाजपा की सबसे बड़ी पूंजी है। भाजपा की इस पूंजी को मप्र से उर्वरा मिलती रहती है। यही कारण है कि संघ का मुख्यालय भले ही नागपुर में है, लेकिन पिछले डेढ़ दशक से मप्र उसकी गतिविधियों का केंद्र रहा है। संघ के एक पदाधिकारी कहते हैं कि शिवराज समन्वयकारी राजनीति करते हैं। समन्वय बनाकर कार्य करने की उनकी शैली की वजह से ही संघ ने मप्र को अपनी नीतियों और रणनीतियों की प्रयोगशाला बनाया है। वह कहते हैं कि संघ हमेशा जातिविहीन समाज के लिए काम करते हुए बड़ी संख्या में लोगों को पार्टी की विचारधारा से जोड़ती रही है। इसका नतीजा है कि देश का बड़ा हिंदू वर्ग भाजपा की ओर आकर्षित है। वह कहते हैं कि भाजपा के आगे बढ़ने में कांग्रेस के सिमटने की भी भूमिका रही है।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपनी चौथी पारी में मप्र को देश में नंबर वन राज्य बनाने का संकल्प लिया है। नई सदी के पहले साल में ही प्रदेश के विकास एवं जनता के कल्याण सहित सभी क्षेत्रों में मप्र को देश का नंबर वन राज्य बनाने के लिए खुद तो समर्पण भाव से जुट ही गए हैं, साथ ही शासन-प्रशासन और संगठन को भी सक्रिय कर दिया है। इसके लिए मुख्यमंत्री ने 12 सूत्र तैयार किया है। उनका पहला सूत्र है कि जनता ही अपनी भगवान है। कोई भी अहंकार में न रहे तथा जनता की सेवा एवं बेहतरी के लिए कार्य करें। दूसरा सूत्र है मप्र के खजाने पर सबसे पहले गरीबों का हक है। गरीबों के कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। किसान एवं कृषि का विकास हमारा तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है। किसानों की फसल की उत्पादन लागत घटाने तथा उन्हें फसलों का बेहतर मूल्य दिलवाने के लिए निरंतर कार्य करना है। प्रदेश में फूड प्रोसेसिंग तथा कृषि अधोसंरचना विकास के क्षेत्र में विशेष प्रयास किए जाने हैं। चौथा सूत्र है महिला सशक्तीकरण। महिला स्व-सहायता समूहों को सशक्त बनाना है। बेटियों की सुरक्षा के लिए हम धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2020 लाए हैं। पांचवा सूत्र है प्रदेश में सुशासन देना, जिसके अंतर्गत जनता को निश्चित समय-सीमा में सेवाएं बिना कार्यालयों के चक्कर लगाए तथा बिना कुछ

लिए-दिए प्राप्त हो जाएं। छठवां सूत्र है प्रदेश को माफिया मुक्त करना। प्रदेश में ड्रग माफिया, मिलावट माफिया, भू-माफिया, रेत माफिया आदि के विरूद्ध सघन अभियान जारी रहेगा। साथ ही इस बात का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा कि आमजन को कोई दिक्कत न हो। किसी निर्दोष व्यक्ति को झूठे मामले में न फंसाया जाए। सातवां सूत्र है परियोजनाओं को निश्चित समय पर पूरा करना। इसके लिए मैं स्वयं हर हफ्ते बड़ी **योजनाओं की समीक्षा करूंगा,** मंत्रीगण भी नियमित समीक्षा करें। अधिकारीगण कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करें। परियोजनाएं बिना लागत बढ़े समय से पूरी हो जाएं। आठवां सूत्र है केंद्र की हर योजना में नंबर वन रहना। इसके लिए सभी निरंतर प्रयास करें। मंत्रीगण केंद्र से निरंतर समन्वय रखें तथा दिल्ली के दौरे करें। विभिन्न योजनाओं में केंद्र से अधिक से अधिक राशि प्राप्त करने के प्रयास किए जाएं। नौवां सूत्र है आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर मप्र का गठन। दसवां सूत्र है अधिक से अधिक रोजगार सृजन। इसके लिए हर विभाग प्रयास करे। शासकीय व अशासकीय दोनों क्षेत्रों में नए रोजगार सृजित किए जाएं। कौशल विकास पर पूरा ध्यान दिया जाए। ग्यारहवां सूत्र है जन स्वास्थ्य। बारहवां सूत्र है अच्छी शिक्षा। इसके लिए हमें शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने पर विशेष ध्यान देना होगा।

मप्र को नंबर वन राज्य बनाने के लिए मुख्यमंत्री ने वे प्रमुख कार्य भी बताए हैं जिन पर इस साल में फोकस रहेगा। इनमें सिंगल सिटीजन डाटाबेस का सभी हितग्राहीमूलक योजनाओं में उपयोग प्रारंभ करना, शासकीय सेवाओं के लिए इलेक्ट्रानिक सिंगल विंडो की व्यवस्था, विभिन्न योजनाओं में स्वीकृति उपरांत बिना विलंब के हितग्राहियों को राशि उपलब्ध कराना, मंडी एवं श्रम सुधारों को प्रभावी ढंग से लागू करना, आउट ऑफ बॉक्स सोचकर रोजगार के नए अवसर पैदा करना, रोजगार सेतु पोर्टल का प्रभावी क्रियान्वयन, आत्मनिर्भर मप्र के रोडमैप के लक्ष्यों को समय-सीमा में पूरा करना, जिलास्तर के कार्यों की मॉनीटरिंग के लिए डैशबोर्ड का प्रयोग, महिला स्व-सहायता समूह, कृषि उत्पादक संगठन, सहकारिता को जनआंदोलन बनाना, पब्लिक हेल्थ केयर तथा इन्फ्रास्ट्रक्चर को उच्च कोटि का बनाना, मुख्यमंत्री राइज स्कूल की अवधारणा को धरातल पर लाना आदि कार्य शामिल हैं। अब देखना यह है कि वर्तमान दशक अपने नाम करने के लिए भाजपा जिस तरह से संगठित होकर काम कर रही है, उसका क्या प्रतिफल मिलता है।

● **विकास दुबे**

शिवराज की ताकत लोगों का विश्वास और समर्थन

मप्र के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सबसे बड़ी ताकत उनके प्रति लोगों का विश्वास और समर्थन है। यह विश्वास और समर्थन उन्हें ऐसे ही नहीं मिला है, बल्कि इसके लिए उन्होंने जनता के प्रति अपना सर्वस्व न्यौछावर कर रखा है। यानी उनका शासन और जीवन जनता के प्रति पूरी तरह समर्पित है। भाजपा सरकार के महिलाओं के बीच ज्यादा लोकप्रिय होने की मुख्य वजह मुख्यमंत्री की सरल-सहज छवि है। खासतौर से मुख्यमंत्री ने महिलाओं से भाई यानी उनके बच्चों के मामा का जो रिश्ता बनाया है, उसने ग्रामीण महिलाओं में मुख्यमंत्री की छवि की अमिट छाप बनाई है। महिलाएं मुख्यमंत्री को आम जनता के बीच का आदमी मानती हैं। मुख्यमंत्री की छवि बनाने में राज्य सरकार की महिलाओं के लिए बनाई गई कल्याणकारी योजनाओं का भी अहम रोल है। महिलाओं के बीच कन्यादान, लाडली लक्ष्मी, जननी योजना, महिला मजदूरों को प्रसव पर आर्थिक सहायता, छात्राओं को मुफ्त साइकिल और स्कूल ड्रेस, छात्रवृत्ति, मेधावी छात्र योजना, तीर्थदर्शन बेहद लोकप्रिय हैं। इस कारण मुख्यमंत्री की छवि को महिलाओं ने मामा के रूप में पहचान दी।

इनामी डकैत मनरेगा में कर रहा मजदूरी!

मप्र वाकई अजब है, गजब है। यहां कब क्या हो जाए, कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। ताजा चौंकाने वाला मामला मनरेगा से संबंधित है। पुलिस रिकॉर्ड में फरार एक इनामी डकैत द्वारा मनरेगा योजना में मजदूरी किए जाने का मामला सामने आया है। मप्र-उप्र की सीमा में आतंक का पर्याय बन चुके डेढ़ लाख के इनामी डकैत गौरी यादव गैंग का भारीकोर मेंबर भालचंद्र मनरेगा में मजदूरी करते पकड़ा गया है। भालचंद्र उर्फ भल्ला यादव को सतना पुलिस ने गिरफ्तार किया है।

दरअसल, कुछ दिन पहले सोशल मीडिया में डकैत के मनरेगा में मजदूरी करने की जानकारी वायरल हुई, इसके बाद जिला प्रशासन व पुलिस के आला अधिकारी सक्रिय हुए। यह विवरण दस्यु उन्मूलन का दम भरने वाली मप्र पुलिस के दावों पर बड़ा सवाल है। आरोपी भालचंद्र और डकैत गौरी यादव आपस में चचेरे साला-बहनोई हैं। इसी रिश्तेदारी के कारण आरोपी कई वर्षों से डकैत गौरी यादव के संपर्क में रहता आया है। पडमनिया, साडा, उंचमार, थरपद, मलगोसा आदि गांवों में ठेकेदारों का काम, बीड़ी पत्ती, सड़क निर्माण, जंगल विभागों के काम आदि का तो यह डकैत गौरी यादव को सूचना देता था। इसके बाद गौरी ने ठेकेदारों को डरा-धमकाकर काम बंद कर दिया और फिर काम चालू कराने के नाम पर रंगदारी वसूलता। गौरी यादव की बहन मझगवां जनपद पंचायत के अंतर्गत पडमनिया जागीर पंचायत की सरपंच है। इसलिए भालचंद्र को पंचायत की योजना के सभी लाभ मिले हैं।

पता चला है कि इस बदमाश की तलाश मप्र के सतना जिले की पुलिस के अलावा उप्र की चित्रकूट पुलिस को भी थी। यह कोई सामान्य अपराधी नहीं है बल्कि मौजूदा समय में उप्र और मप्र के इलाकों में सक्रिय डेढ़ लाख के इनामी डकैत गौरी यादव गिरोह का खास सदस्य है। 9 महीने पहले 16 मई 2020 को जिले के मझगवां थाना में ग्राम जिल्लहा निवासी सौखी लाल कोरी पुत्र बेला कोरी ने रंगदारी वसूली के संबंध में शिकायत दर्ज कराई थी। जिसमें कुख्यात इनामी डकैत गौरी यादव समेत अवधेश यादव, मोनू गुप्ता, हीरालाल यादव, रामजी यादव, रामभवन मवासी उर्फ उरमलिया एवं भालचंद्र यादव के खिलाफ अपराध क्रमांक 38/2020 में आईपीसी की धारा 386, 387 एवं 11/13 एडी एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया था। इस अपराध के आरोपी गौरी यादव, रामजी यादव एवं भालचंद्र यादव का फरारी में 5 अक्टूबर 2020 को न्यायालय में चालान पेश किया गया था।

सूत्र बताते हैं कि रंगदारी वसूली के अपराध का आरोपी भालचंद्र यादव पुत्र रामअवतार यादव मझगवां थाना क्षेत्र के ग्राम पड़मनिया जागीर का रहने वाला है। डकैत गौरी यादव गिरोह के इस सदस्य पर 5 हजार रुपए का इनाम सतना पुलिस ने घोषित किया था। भालचंद्र यादव को उप्र पुलिस ने भी डकैतों की सूची में शामिल कर लिया है। इसे उप्र के इलाके में पांडेय के नाम से ही जाना जाता है।

एक तरफ जहां बीते लगभग 9 माह से पुलिस भालचंद्र यादव को तलाश रही थी वहीं दूसरी ओर मझगवां विकासखंड की ग्राम पंचायत पड़मनिया जागीर से सामने आए दस्तावेज इस बात की गवाही दे रहे हैं कि भालचंद्र यादव मनरेगा योजना के तहत ग्राम पंचायत में मजदूरी कर रहा था, इस मजदूरी का उसे पारिश्रमिक भी दिया जा रहा था।

ग्राम पंचायत में भालचंद्र का जॉब कार्ड बना हुआ है जिसका नंबर एमपी 12-001-096-004/63ए तथा फैमिली आईडी 63ए है। 16 मई 2020 की वारदात से फरार जिस भालचंद्र यादव का फरारी में 5 अक्टूबर 2020 को चालान पेश किया गया उसने बीते साल 2020 में 9 से 22 अक्टूबर, 23 से 29 अक्टूबर, 31 अक्टूबर से 13 नवंबर एवं 6 दिसंबर से 19 दिसंबर तक मंदाकिनी नदी कंटूर ट्रेंच निर्माण काली दाई बगार क्रमांक 3 पड़मनिया जागीर में मनरेगा योजना के तहत काम किया है। इस काम के बदले उसे हर बार 2280 रुपए का भुगतान भी हुआ है। इन कामों की डिमांड आईडी 582433, 624934, 654570 एवं 785533 है।

सूत्रों की माने तो ग्राम पंचायत पड़मनिया के रोजगार सहायक हेमराज यादव की मेहरबानी से भालचंद्र यादव और उसकी पत्नी नथुनिया यादव को मनरेगा योजना में पिछले लंबे अरसे से लगातार काम मिल रहा था और उस काम का भुगतान भी हो रहा था। हेमराज यादव वही रोजगार सहायक हैं जिन्हें 7 अगस्त 2020 को तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत रिजु बाफना द्वारा हितग्राही सुदामा प्रसाद एवं मिठाई लाल को गलत तरीके से प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिए जाने के संबंध में कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब तलब किया गया था। हालांकि बताते हैं कि अब तक हेमराज यादव पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। यही वजह है कि भालचंद्र यादव के पुलिस रिकॉर्ड में फरार रहने के दौरान उसके नाम पर मजदूरी किए जाने का विषय सामने आने पर ग्राम रोजगार सहायक हेमराज यादव की भूमिका पर भी सवालिया निशान लग गया है।

● **राकेश ग्रोवर**

मांगी थी 50 हजार की रंगदारी

21 मई 2020 को आरोपी भालचंद्र यादव ने गौरी यादव गैंग के साथ मिलकर ग्राम जिल्लहा में रात करीब 12-01 बजे सौखीलाल कोरी व अन्य दो लोगों को पकड़कर जंगल तरफ तालाब में ले जाकर बंदूक के बट व लाठी-डंडे से मारपीट की थी। बीड़ी पत्ती तुड़वाने व ठेकेदारी करने के एवज में 50 हजार रुपए की मांग की थी। इस पर थाना मझगवां में केस दर्ज किया गया था। इस मामले में भालचंद्र यादव फरार था। उस पर पांच हजार रुपए का इनाम घोषित था। अन्य मामले में 3 जनवरी 2021 को इसने गौरी यादव गैंग के साथ मिलकर थाना बहिलपुरवा के दादरी जंगल मे वन विभाग के चलने वाले काम को बंद करवा कर वन कर्मचारी के साथ मारपीट कर पैसों की मांग की थी। इस मामले में भी आरोपी की तलाश बहिलपुरवा पुलिस कर रही थी।

परिवहन मंत्री गोविन्द सिंह राजपूत के सार्वजनिक भोज से सालभर दूरी के संकल्प को विश्लेषक 'इमोशनल कार्ड' के तौर पर देख रहे हैं, क्योंकि सीधी में बस हादसे और उसमें 54 लोगों की मौत के बाद मंत्री राजपूत घिर गए हैं। एक तरफ उनके सामने विधानसभा में कांग्रेस को जवाब देने की चुनौती है, तो दूसरी ओर उन अवैध बसों पर कार्रवाई न कर पाने की लाचारी है।

इमोशनल कार्ड

म प्र के परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने एक साल तक किसी सार्वजनिक भोज में शामिल नहीं होने का संकल्प लिया है। राजपूत ने यहां तक कहा है कि भोज पर चाहे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह बुलाएं या ज्योतिरादित्य सिंधिया, वह इसमें भी नहीं जाएंगे। राजपूत ने यह संकल्प राज्य विधानसभा के बजट सत्र के ऐन पहले लिया। उनके इस संकल्प को सियासी विश्लेषक अलग-अलग नजरिए से देख रहे हैं। कुछ मानते हैं कि वसंत पंचमी के दिन सीधी बस हादसे में हुई 54 मौतों को लेकर उनके पास कोई जवाब नहीं है, न ही भविष्य के लिए कोई एक्शन प्लान। बजट सत्र में सबसे ज्यादा हंगामा सीधी बस हादसे और परिवहन मंत्री की कथित संवेदनहीनता, लापरवाही को लेकर चल रहा है, इसलिए मंत्री ने यह संकल्प का 'इमोशनल कार्ड' खेला है, ताकि यह संदेश जाए कि वास्तव में मंत्री खुद कितने दुखी और एक्शन को लेकर संजीदा हैं।

बता दें कि वसंत पंचमी के दिन 16 फरवरी को सीधी के छुहिया घाट पर यात्रियों से भरी बस छुहिया घाट पर नहर में समा गई थी, जिसमें 54 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी। जिस दिन हृदय विदारक यह घटना हुई, उस दिन हादसे वाली जगह पर जाने की बजाय परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत अपने मंत्री मित्र अरविंद भदौरिया के घर पर दावत में थे। उनका ठहाके लगाता हुआ वीडियो वायरल हुआ था। पूरे एक हफ्ते बाद उन्हें दावत से हुई चौतरफा किरकिरी का अहसास हुआ और पश्चाताप स्वरूप उन्होंने सालभर तक सार्वजनिक भोज से दूरी बनाने का संकल्प ले लिया। राजपूत ने खुद बताया कि किसी भोज में शामिल न होने के संकल्प के चलते ही वह प्रोटेम स्पीकर के भोज में नहीं पहुंचे। आगे भी किसी सार्वजनिक भोज में नहीं जाएंगे।

सीधी हादसे के दूसरे दिन गोविंद सिंह राजपूत हरकत में आए और खुद सड़क पर उतरे और बस में सवार जांच करते हुए उनकी कई तस्वीरें भी मीडिया के सामने आईं, लेकिन उसके बाद सड़क पर कहीं नहीं दिखाई दिए। बताते हैं कि उनकी तत्परता और अवैध बसों के संचालन के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू हुई, वैसे ही राजपूत के पास भाजपा नेताओं के फोन बजने लगे। फोन करने वालों में कुछ ऐसे आला नेता भी थे, जिनके हुकुम को ना मानना नाफरमानी माना जा सकता था। वह शरण देने वाले भाजपा नेताओं पर कार्रवाई कैसे करें, यह उनकी सबसे बड़ी दुविधा है। प्रदेश में अवैध बसों के संचालन के खिलाफ की गई कार्रवाई में करीब 600 से ज्यादा कंडम बसें जब्त की गई हैं। इन बसों की जब्ती बताती है कि केंद्र सरकार की स्क्रैप पॉलिसी की मप्र में किस कदर धज्जियां उड़ रही हैं। इन बसों को कबाड़ में क्यों नहीं बदला जा सका, इसका सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है। भाजपा नेताओं की इन बसों पर कोई कैसे कार्रवाई करे, यह सबसे बड़ा सवाल है।

भाजपा में राजपूत की आमद बिल्कुल नई है, भाजपा की सियासत में उनकी शुरुआत हो रही है, अभी वह पार्टी की रीति-नीति सीखने के साथ ही यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कब-कैसी करवट लेना है। इसलिए राजपूत बहुत सावधानी से फूंक-फूंककर कदम रख रहे हैं। भाजपा नेताओं के दबाव और कार्रवाई न कर पाने की दुविधा से बचने के लिए उन्होंने दो काम किए, एक तो खुद सड़क पर नहीं उतरे, दूसरे विभाग के अधिकारियों को अपने स्तर पर हफ्तेभर का अभियान चलाने के लिए कह दिया। ऐसा करके उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के सामने यह विकल्प छोड़ दिया कि आगे वह कार्रवाई को लेकर खुद अपनी तरफ से टूर एंड ट्रेवल्स का कारोबार करने वाले भाजपा नेताओं को यह संदेश दें कि वह परिवहन नियमों के अनुसार चलें, वरना कार्रवाई होगी। ऐसा करने से राजपूत को भाजपा नेताओं की सीधे तौर पर नाराजगी नहीं झेलनी पड़ेगी।

● **धर्मेंद्र सिंह कथूरिया**

हादसे के बाद हंसी-ठिठोली और भोजन!

सीधी बस हादसे के बाद वायरस हुई एक फोटो में राजपूत हंसते हुए खाना खाते दिखाई दे रहे थे। कांग्रेस ने उनके इस कार्यक्रम में शामिल होने पर सवाल खड़े किए थे। कांग्रेस का आरोप था कि ऐसे भयानक हादसे के बाद मंत्री को घटनास्थल पर होना चाहिए था वहां राहत और बचाव कार्य देखने चाहिए थे लेकिन इन सबसे बेपरवाह मंत्री गोविंद राजपूत भोजन के लुत्फ ले रहे थे और हंसी-ठिठोली कर रहे थे। गोविंद राजपूत की फोटो वायरल होने के बाद अच्छी खासी फजीहत हो गई थी। इसलिए उन्होंने कहा 'मैंने फैसला लिया है कि मैं एक साल तक किसी भी सार्वजनिक भोज के कार्यक्रम में नहीं जाऊंगा और न ही भोज करूंगा। मैंने अपनी अंतरात्मा से फैसला लिया है। सिंधिया जी का हो शिवराज जी का हो या किसी और की तरफ भी भोज का आमंत्रण हो मैं वहां नहीं जाऊंगा। इसलिए मैं आज प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा के कार्यक्रम में भी नहीं गया।' उन्होंने कहा, विपक्ष ने मंत्री अरविंद भदौरिया के बंगले पर वसंत पंचमी के दिन कार्यक्रम में भोज करने का फोटो वायरल किया था। विपक्ष ने मुद्दा बनाया था। मेरा मजाक उड़ाया गया था इसलिए मैंने ये फैसला किया है। उधर, कांग्रेस नेताओं का कहना है कि मंत्रीजी केवल सहानुभूति पाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। अगर उनमें तनिक भी नैतिकता होती तो वे हादसे के बाद अपने पद से इस्तीफा दे देते। उन्होंने कुर्सी के लिए ही तो पार्टी बदली है। अब जनता को दिखाने के लिए नैतिकता का लबादा ओढ़ने की कोशिश कर रहे हैं।

'चौकीदार ही चोर है'

मप्र में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान किसानों की आमदनी को दोगुनी करने की रणनीति पर काम कर रहे हैं, वहीं अधिकारी-कर्मचारी, व्यापारी, ठेकेदार आदि मिलकर किसानों को चूना लगा रहे हैं। किसानों को मिलने वाले खाद-बीज को बाजारों में बेचा जा रहा है। ऐसा ही एक मामला मंदसौर में सामने आया है। जहां स्टेट वेयर हाउस के गोदाम कीपर ने अपने ठेकेदार बेटे के साथ मिलकर 4.63 करोड़ रुपए की खाद हेराफेरी की है। विपणन के माध्यम से सोसायटियों को खाद वितरण में कालाबाजारी सामने आई है। जब विपणन ने सहकारिता को भुगतान के लिए बिल थमाए तो मामला सामने आया। वेयर हाउस कॉर्पोरेशन के अधिकारियों ने गोदाम कीपर ठाकुर प्रसाद तिवारी को सस्पेंड कर दिया। वहीं मंदसौर विधायक द्वारा इस मामले को विधानसभा में उठाए जाने के बाद पिता-पुत्र के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया गया है।

प्रदेश में एक तरफ अन्नदाता खाद के लिए मारा मारा फिरता है। यहां तक कि एक-एक बोरी खाद के लिए भी उसे जद्दोजहद करनी पड़ती हैं। वहीं मंदसौर में किसानों के हक के हजारों क्विंटल खाद पर चौकीदार पिता और ठेकेदार बेटे ने डाका डाल दिया। बाप-बेटे ने मिलकर 1419 मीट्रिक टन खाद का घोटाला किया है। 4.63 करोड़ रुपए के इस खाद घोटाले का खुलासा तब हुआ जब कंपनी द्वारा भुगतान के लिए जिला सहकारी बैंक में बिल भेजे गए। जिला सहकारी बैंक के एमडी पीएन यादव ने फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए सोसाइटी से रिकॉर्ड मांगा। क्रॉस चेक करने पर पता चला कि खाद, गोदाम से तो निकला लेकिन सोसाइटी तक नहीं पहुंच पाया।

मई 2020 में खाद के अग्रिम भंडारण के लिए पिपलियामंडी क्षेत्र की 16 सहकारी समितियों ने चेक व आरओ ट्रांसपोर्टर कमल उर्फ टोनू तिवारी को दिए। उसने चेक व आरओ लेकर पिपलियामंडी स्थित वेयर हाउस कॉर्पोरेशन के गोदाम से 1400 मीट्रिक टन खाद सोसायटियों में भेजने के लिए उठाया। यह सोसायटियों में भेजने की बजाय बाजार में बेच दिया। 5 माह बाद डीएमओ ने 16 सहकारी समितियों को भेजे खाद की राशि के भुगतान के लिए आरओ व चेक सहकारिता विभाग को वापस किए। भुगतान से पहले सहकारिता विभाग ने समितियों से खाद की जानकारी ली तो पता चला कि एक भी सोसायटी में खाद नहीं पहुंचा।

डीएमओ ने कलेक्टर को अवगत कराया। कलेक्टर ने सहकारिता विभाग से जांच कमेटी गठित करने को कहा। इधर, कार्रवाई से बचने के लिए ट्रांसपोर्टर ने सहकारिता विभाग को 5 करोड़ रुपए का चेक देकर हिसाब चुकता कर लेने की बात कही। हालांकि पूरी हुई जांच में सामने आया कि ट्रांसपोर्टर ने सहकारी बैंक, सहकारिता विभाग, विपणन व स्टेट वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन को गुमराह किया है। जिला विपणन अधिकारी जेनिफर खान ने बताया कि सहकारिता विभाग को भुगतान के लिए बिल दिए तो उन्होंने ट्रांसपोर्टर से खाद मिलना नहीं बताया। ट्रांसपोर्टर ने सोसायटी का खाद बाजार में बेच दिया। कलेक्टर ने जांच टीम गठित की थी। जांच पूरी होने के बाद हम मामले में ट्रांसपोर्टर के विरुद्ध केस दर्ज करवाएंगे।

उधर, ठेकेदार कमल तिवारी ने शपथ पत्र देकर यह बात स्वीकार की है कि उसके पिता और उसने मिलकर खाद की हेराफेरी की है। बताया गया है कि घोटाला 4.63 करोड़ रुपए का है। घोटाले का अधिकतर खाद मई माह में उठाया गया था। जिसमें **एडवांस लिफ्टिंग प्रणाली** का उपयोग करते हुए एडवांस में आरओ और चेक देकर एनपीके और डीएपी खाद उठाया गया। लेकिन यह खाद सोसाइटी में नहीं पहुंचा। जिला सहकारी बैंक के एमडी पीएन यादव ने बताया कि कंपनी द्वारा भुगतान के लिए बिल भेजा गया था। जिसके बाद खाद के पहुंचने का फिजिकल वेरिफिकेशन करवाया गया। जांच में जानकारी सामने आई कि कंपनी जिस खाद का भुगतान मांग रही है वह खाद सोसाइटी में तो पहुंचा ही नहीं है। जानकारी मिलने के बाद कंपनी का भुगतान रोका गया।

चौकीदार के करोड़ों के बंगले को देखकर आप सहज ही अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह का गोरखधंधा पिपलिया मंडी में पिछले कुछ समय से चल रहा था। चौकीदार पिता के ठेकेदार बेटे के रसूख का अंदाजा भी इसी बात से लगाया जा सकता है कि उसके 3 करोड़ 28 लाख रुपए मंदसौर जिले के ट्रांसपोर्टेशन विभाग पर बकाया है। वहीं नीमच जिले में भी तकरीबन 1 करोड़ रुपए की देनदारी बताई जा रही है। रतलाम, आगर-मालवा, इंदौर और उज्जैन जिले में भी एक ट्रांसपोर्टर द्वारा माल परिवहन किए जाने की बात सामने आई है। इस मामले में मंदसौर से विधायक यशपाल सिंह सिसौदिया ने मामले की उच्चस्तरीय जांच किए जाने की मांग की है।

● **सुनील सिंह**

विधानसभा में उठा मुद्दा

बजट सत्र के दौरान 25 फरवरी को प्रश्नकाल के दौरान मंदसौर और नीमच में ट्रांसपोर्टर द्वारा गेहूं तथा खाद को सोसायटी तक पहुंचाने में हेराफेरी का मामला उठा। मामला मंदसौर से भाजपा विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि वेयरहाउस में चौकीदार का बेटा ही ठेकेदार है जिसने यह हेराफेरी की है। इसका जवाब देते हुए प्रदेश के सहकारिता मंत्री अरविंद सिंह भदौरिया ने कहा कि इस मामले में चौकीदार की संलिप्तता भी सामने आई है। ट्रांसपोर्टर और चौकीदार ने मिलकर 4 करोड़ 63 लाख की हेराफेरी की है। इस मामले में आरोपियों के खिलाफ एफआईआर हो चुकी है। को-ऑपरेटिव सोसायटी को इस संबंध में सहकारिता आयुक्त ने एफआईआर करने के लिए 15 फरवरी को एक पत्र भेज दिया था। मंत्री भदौरिया ने बताया कि आरोपियों से वसूली की कार्रवाई भी शुरू की जा रही है। इनके खिलाफ संपत्ति कुर्क करने की भी जानकारी की जाएगी। इसके लिए शासन स्तर पर एक जांच दल गठित किया जाएगा। यदि सोसायटी के महाप्रबंधक इसमें शामिल पाए जाते हैं तो उनको हटाकर 3 माह में जांच की जाएगी।

अन्यथा नहीं रुकेंगे हादसे

मप्र में हर चौथी बस अनफिट

खंबे पर लगे कैमरे के सामने बस खड़ी कर दी जाती है और परिवहन विभाग इन्हें जारी कर देता है फिटनेस सर्टिफिकेट। यही वजह है कि सड़कों पर दौड़ रही जर्जर बसों की संख्या में इजाफा हो रहा है और यात्रियों का सफर जोखिम भरा। कई बसों में न तो हेडलाइट थी और न इंडिकेटर। बसों की अंदर से यह स्थिति थी कि यात्रियों को बैठने के लिए तो टूटी, फटी सीट थी। ड्राइवर के लिए भी ऐसी सीट थी, जिस पर बैठकर बस चलाना काफी मुश्किल है। कुछ बसों में तो इमरजेंसी गेट भी नहीं था तो कुछ बसों के कांच फूटे हुए थे। अंदर से जगह-जगह से बॉडी टूटी हुई थी, जिससे यात्रियों को चोट लगने की संभावना है। बसों की इतनी जर्जर स्थिति के बाद भी इन बसों का संचालन हो रहा है। परिवहन विभाग के कार्रवाई न करने की वजह से बस संचालक बेखौफ हैं। सड़कों पर दौड़ रहीं अनफिट बसों के लिए पूरी तरह से परिवहन विभाग जिम्मेदार है।

सीधी बस हादसे के बाद सरकार, प्रशासन और परिवहन विभाग की सतर्कता देखने लायक है। अगर इतनी सतर्कता पहले दिखाई होती तो यह हादसा नहीं हुआ होता। सीधी-शहडोल राजमार्ग पर एक ट्रक 13 फरवरी को दिन में खराब हो जाता है। इसके बाद स्वाभाविक रूप से राजमार्ग पर जाम लग जाता है। वाहन रेंग-रेंगकर जाम से निकलने का सफल-विफल संघर्ष करते हैं। धीरे-धीरे चार दिन गुजर जाते हैं। खराब ट्रक अब भी उसी जगह खड़ा है। जाम भी जारी है। 16 फरवरी की सुबह सीधी से 32 सीटर निजी बस 61 यात्री भरकर सतना के लिए रवाना हुई। आगे बढ़ने पर जाम की जानकारी मिलने पर ड्राइवर ने वैकल्पिक मार्ग चुनकर बस बाणसागर डैम की 22 फीट गहराई वाली मुख्य नहर की पटरी पर उतार दी। ड्राइवर सीधी से ही बस बहुत तेज गति से दौड़ा रहा था। बस में ठूंस-ठूंसकर भरे यात्रियों की सांसें थमी जा रही थीं।

जब बस नहर की संकरी पटरी पर पहुंची तो भयभीत यात्रियों ने ड्राइवर से रफ्तार कम करने की विनती की, पर ड्राइवर ने इस पर ध्यान नहीं दिया। इस बीच एक ट्रक को पास करने के प्रयास में बस का पहिया नहर की ओर फिसला और देखते ही देखते बस नहर में गिरकर गहरे पानी में डूब गई। आसपास के ग्रामीणों ने किसी तरह 7 यात्रियों को बचाया, जबकि बाकी 54 यात्रियों की मौत हो गई। पूरे प्रदेश को शोक में डुबा देने वाले हादसे के बाद राजमार्ग पर चार दिन से खराब खड़ा ट्रक हटाने की कवायद शुरू हुई और रात तक उसे हटाकर जाम खुलवा दिया गया। इस गड़बड़ी के लिए जिम्मेदार मानते हुए ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया। जाहिर है प्रशासन ने खुद को क्लीनचिट दे दी।

यह उसी मप्र की कहानी है जिसके कुछ कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी-कर्मचारी अपने शहर इंदौर को देश का स्वच्छतम शहर बनाने के लिए जुनून की हद पार कर जाते हैं। इंदौर और भोपाल की स्वच्छता के प्रति ललक का डंका देशभर में बज रहा है। ऐसी कई अन्य उपलब्धियां हैं जिनसे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह का आत्मविश्वास इस हद तक बढ़ जाता है कि वह मप्र को देश का नंबर एक प्रदेश बनाने का सपना देखने लगते हैं। इसी बीच सीधी बस हादसा यह मुनादी कर देता है कि स्वच्छता की उपलब्धि मप्र की प्रतिनिधि तस्वीर नहीं है। यही तंत्र सीधी-शहडोल राजमार्ग पर खराब खड़े ट्रक को हटवाने के लिए 54 मौतों का चार दिन इंतजार करता रहा।

विडंबना यह कि इसके लिए सिर्फ ट्रक ड्राइवर को दोषी माना गया। यदि कोई राजमार्ग चार दिन से जाम है तो क्या जाम हटवाने में प्रशासन की कोई जिम्मेदारी नहीं? प्रशासन संवेदनशील होता तो जाम उसी दिन खुल सकता था, जैसे हादसे के बाद खुला, पर आम आदमी की कठिनाइयों का समाधान प्रशासन के लिए कोई उपलब्धि नहीं होता। इससे प्रशासन को कोई लाभ नहीं होता। कुछ दिन पहले स्वच्छतम शहर इंदौर में भी तंत्र की गंदगी का नमूना दिखा था, जब अधिकारियों ने रास्तों के किनारे पड़े लावारिस भिक्षुकों को कूड़ा-कचरा की तरह वाहन में लादकर शहर के बाहर फिंकवा दिया था।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की समाज के विभिन्न वर्गों के लिए संवेदनशीलता जगजाहिर है। अपने सरोकारों की पूर्ति के लिए वह अथक परिश्रम करते हैं। इसीलिए नारी सशक्तिकरण, बालिका संरक्षण, कृषि उन्नयन और सामाजिक सद्भाव की दृष्टि से मप्र को अग्रणी प्रदेश माना जाता है, पर देश का नंबर एक प्रदेश बनना अलग बात है। इसके लिए हर अधिकारी-कर्मचारी में स्वच्छता मुहिम जैसा जुनून पैदा करना होगा। उन्हें दंड मिले या न मिले, पर सीधी बस हादसा उन अधिकारियों के मस्तक पर कलंक का टीका है, जो राजमार्ग पर खराब खड़े ट्रक को चार दिन नहीं हटवा पाए। ये अधिकारी तंत्र की सड़न और दुर्गंध हैं। इनकी वजह से प्रदेश का पूरा वातावरण खराब हो रहा है, इसलिए इन पर झाड़ू चलना बहुत जरूरी है।

प्रदेश के सामने शिक्षा, स्वास्थ्य, जनजातियों का सम्मान, किसानों की खुशहाली और अधिकारों के प्रति जागरूकता जैसी चुनौतियां हैं, जिनका मुकाबला संवेदनशील, कर्मठ, ईमानदार और जन-सरोकारी नौकरशाही ही कर सकती है। जो अधिकारी जन समस्याओं पर आंखें मूंद लें, वे प्रदेश को सिर्फ पीछे ले जा सकते हैं। यह तय किया जाना चाहिए कि राजमार्ग पर खराब खड़े ट्रक को तुरंत हटवाना किस अधिकारी की जिम्मेदारी थी? उसके लिए कठोर दंड का निर्धारण किया जाना चाहिए। ऐसा न किया गया तो किसी दिन फिर किसी रास्ते पर कोई ट्रक खराब होगा, रास्ता जाम होगा, फिर कोई हादसा होगा, फिर आंसू बहेंगे, मुआवजा बंटेगा और फिर अगले हादसे का इंतजार शुरू हो जाएगा। बेहतर है कि शासन नींद से जागे और 54 जिंदगियों के असली गुनहगार की गर्दन पर हाथ डाले अन्यथा हादसे रोके नहीं जा सकेंगे। जो व्यवस्था इतिहास से सबक नहीं लेती, वह इतिहास दोहराने को अभिशप्त होती है।

● **श्याम सिंह सिकरवार**

मप्र में खूंखार हुए बाघ

मप्र में वन्य प्राणियों की बढ़ती संख्या के कारण जहां बाघों के लिए रहवासी क्षेत्र कम पड़ने लगे हैं, वहीं बाघ खूंखार होते जा रहे हैं। प्रदेश में वर्ष 2020 में बाघ ने 5 लोगों को अपना शिकार बनाया है। वहीं उप्र में 4 लोग बाघ का शिकार बने हैं। 2016 से 2020 के बीच पिछले 5 वर्षों में बाघ और हाथियों के हमले में 2,729 लोग मारे गए थे। इनमें 200 लोग बाघों के हमले में जबकि 2,529 हाथियों के हमले में मारे गए थे। यह जानकारी लोकसभा में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री बाबुल सुप्रियो द्वारा के प्रश्न के जवाब में सामने आई है। बाघों के हमले में मारे गए लोगों की बात करें तो पिछले 5 वर्षों में सबसे ज्यादा जानें महाराष्ट्र में गई हैं जहां इन सघर्षों के चलते 54 लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था। इसके बाद उप्र में 51, पश्चिम बंगाल में 44, मप्र में 23, राजस्थान में 7, उत्तराखंड में 6 और कर्नाटक में 5 लोगों की जान गई थी। यदि सिर्फ 2020 की बात करें तो सबसे ज्यादा जानें पश्चिम बंगाल में गई हैं जहां 5 लोग इन संघर्षों का शिकार बने थे। वहीं उप्र में 4 लोगों की जान गई थी। कुल मिलाकर पिछले साल 13 लोग बाघों के हमले में मारे गए थे, जबकि 2019 में 50, 2018 में 31, 2017 में 44 और 2016 में 62 लोगों की मृत्यु हुई थी।

हालांकि बाघों को सबसे ज्यादा आक्रामक माना जाता है, पर देश में सबसे ज्यादा जानें हाथियों से होने वाले संघर्षों में जाती हैं। पिछले 5 वर्षों में 2015 से 2020 के बीच हाथियों से हुए संघर्ष में सबसे ज्यादा जानें ओडिशा में गई हैं जहां 449 लोगों की मृत्यु हुई है। जबकि इसके बाद पश्चिम बंगाल में 430, झारखंड में 380, असम में 353, छत्तीसगढ़ में 335, तमिलनाडु में 246, कर्नाटक में 159, केरल में 93 और मेघालय में 25 लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था। वहीं यदि 2019-20 को देखें तो इस अवधि में 586 लोगों की जान हाथियों के साथ होने वाले संघर्षों में गई है, जो कि पिछले 5 वर्षों में सबसे ज्यादा है। वहीं 2018-19 में 452, 2017-18 में 506, 2016-17 में 516 और 2015-16 में 469 लोगों की मौत हुई थी।

आज जैसे-जैसे इंसानी आबादी बढ़ रही है और जीवों के प्राकृतिक आवास सिकुड़ते जा रहे हैं, उसका असर इंसान और जानवरों के संबंधों पर भी पड़ रहा है। इस वजह से इंसानों और जानवरों के बीच आवास और भोजन के लिए टकराव भी बढ़ता जा रहा है। इस संघर्ष की कीमत इंसानों को अपनी फसल, मवेशियों और संपत्ति के रूप में चुकानी पड़ती है। कभी-कभी इसका नतीजा उनकी मृत्यु का कारण भी बन रहा है। दूसरी तरह के जानवर भी इस संघर्ष की भेंट चढ़ रहे हैं। कभी-कभी इसका शिकार वो जानवर भी बनते हैं जिनकी आबादी पहले ही खतरे में है ऐसे में उनका अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाता है। ऐसे में यदि इस संघर्ष को कोई समाधान नहीं निकाला जाता तो इन जीवों के संरक्षण के लिए जो स्थानीय समर्थन प्राप्त होता है, वो भी कम होता जाता है। जिस पर ध्यान देने की जरूरत है।

पहली बार वैज्ञानिकों ने जानवरों की आवाजाही पर मानव गतिविधि के दुनियाभर में पड़ने वाले प्रभावों की गणना की है। जिसमें प्रजातियों के अस्तित्व और जैव विविधता को खतरा पैदा करने वाले व्यापक प्रभावों का खुलासा किया गया है। शहरीकरण जैसी गतिविधियों का वन्यजीवों पर बड़ा प्रभाव हो सकता है, ऑस्ट्रेलिया में सिडनी विश्वविद्यालय और डीकिन विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों द्वारा किए गए अध्ययन से पता चलता है कि शिकार, सैन्य गतिविधि और मनोरंजन जैसी लगातार चलने वाली गतिविधियों से भी जानवरों के व्यवहार में बड़े बदलाव हो सकते हैं। सिडनी विश्वविद्यालय में वन्यजीव पारिस्थितिकीविद् और प्रमुख अध्ययनकर्ता डॉ. टिम डोहर्टी ने कहा कि यह महत्वपूर्ण है कि हम उस प्रभाव के पैमाने को समझते हैं जो मनुष्यों की अन्य जानवर प्रजातियों पर पड़ती है। जानवरों की बदली हुई गतिविधि के परिणाम गहरे हो सकते हैं और जानवरों का स्वस्थ रहना कम हो सकता है। उनके जीवित रहने की संभावना कम हो सकती है, प्रजनन दर कम हो सकती है, अनुवांशिक से अलग और यहां तक कि स्थानीय विलुप्ति भी हो सकती है।

अध्ययन में कहा गया है कि लोगों की गतिविधि के द्वारा अशांति से होने वाले पशु आवाजाही पर प्रभाव न पड़े इसके लिए दुनियाभर में पुनर्गठन की आवश्यकता है, जिसके कारण जानवरों की आबादी, प्रजातियों और पारिस्थितिकी तंत्र प्रक्रियाओं पर गहरा प्रभाव पड़ता है। डॉ. डोहर्टी ने कहा कि जानवरों के अस्तित्व के लिए उनकी आवाजाही महत्वपूर्ण है, लेकिन यह मानवीय गड़बड़ी से बाधित हो सकती है। जानवर मानव गतिविधियों को समायोजित करने के लिए व्यवहार में इसे अपनाते हैं, जैसे कि मनुष्यों का भागना या बचना, भोजन या साथी को खोजने के लिए आगे की यात्रा करना, मनुष्यों या शिकारियों से बचने के लिए नए आश्रय की खोज करना। कुछ मामलों में मानव गतिविधियों ने जानवरों की आवाजाही में कमी लाने के लिए मजबूर किया है। अध्ययन में पाया गया कि लोगों के रहने वाले स्थानों तक भोजन की बढ़ती पहुंच के कारण, बदले गए निवास स्थान से दूसरी जगह जाने की क्षमता कम हो गई या शारीरिक बाधाओं से उनकी आवाजाही पर रोक लग रही है।

● **जितेंद्र तिवारी**

नीतियों को लागू करना

अध्ययन में 39 वर्षों में 167 पशु प्रजातियों पर 208 अलग-अलग अध्ययनों का संकलन और विश्लेषण किया, ताकि यह पता लगाया जा सके कि मानव गतिविधि से होने वाली अशांति से जानवरों की आवाजाही कैसे प्रभावित होती है। एक तिहाई से अधिक मामलों में, जानवरों को उन परिवर्तनों के लिए मजबूर किया गया, जिनमें उनकी आवाजाही में 50 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि देखी गई। अध्ययन में 0.05 ग्राम स्लीपी नारंगी तितली से लेकर 2000 किलोग्राम से अधिक ग्रेट वाइट शार्क शामिल हैं। इसमें 37 पक्षी प्रजातियां, 77 स्तनपायी प्रजातियां, 17 सरीसृप प्रजातियां, 11 उभयचर प्रजातियां, 13 मछली प्रजातियां और 12 आर्थ्रोपॉड (कीट) प्रजातियां शामिल थीं। डॉ. डोहर्टी ने कहा है कि निष्कर्षों में जानवरों की जैव विविधता के प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण नीतियों को लागू करने की आवश्यकता है। समुद्री वातावरण और परिदृश्य मानव प्रभाव से उतना प्रभावित नहीं है, यह महत्वपूर्ण है कि आवास में बदलाव से बचा जाना चाहिए। यह मौजूदा संरक्षित क्षेत्रों को मजबूत बनाने और कानूनी सुरक्षा के लिए जंगल के अधिक क्षेत्रों को सुरक्षित करना इसमें शामिल हो सकता है।

मॉडल गांव ही पड़े बेहाल

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2022 तक किसानों की आमदनी को दोगुनी करने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए कृषि विज्ञान केंद्र ने पायलट प्रोजेक्ट के रूप में हर जिले के दो गांवों को गोद लिया है। इन मॉडल गांवों को डबलिंग फार्मर्स इनकम विलेज नाम दिया गया है। मप्र के 53 कृषि विज्ञान केंद्रों सहित देश के 651 केंद्रों ने गांव गोद लिए हैं। लेकिन गोद लिए गांवों में खेती-किसानी की स्थिति देखकर ऐसा नहीं लगता है कि 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी हो जाएगी। दरअसल, कृषि विज्ञान केंद्रों द्वारा गोद लिए गए अधिकांश गांवों में न तो मिट्टी परीक्षण हो पाया है, न ही किसानों को उन्नत खेती का प्रशिक्षण मिला है। जिन गांवों में मिट्टी का परीक्षण करने वैज्ञानिक पहुंचे वहां दोबारा वे लौटकर नहीं गए। आज स्थिति यह है कि कृषि विज्ञान केंद्रों द्वारा गोद लिए गए गांवों में खेती-किसानी पुराने ढर्रे पर ही चल रही है।

मप्र में एक तरफ किसानों की आमदनी दोगुनी करने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खजाना खोल रखा है। पिछले 11 माह में मप्र सरकार ने किसानों को 83,000 करोड़ रुपए (जैसा की राज्यपाल ने अभिभाषण में कहा) विभिन्न योजनाओं के तहत आवंटित किए हैं। वहीं दूसरी तरफ स्थिति यह है कि प्रदेश के 53 कृषि विज्ञान केंद्रों ने जिन गांवों को गोद लिया है उनमें से अधिकांश की स्थिति जस की तस है। कृषि विभाग के अधिकारियों का कहना है कि सतत निगरानी नहीं होने और फंड की कमी के कारण योजना परिणामदायी नहीं बन पाई है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि आय बढ़ाने में केवीके के प्रयास अभी जमीन पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। गांवों में जिन चुनिंदा किसानों की आय बढ़ी है, वह उनकी दूरदर्शिता और मेहनत का नतीजा है। केवीके के पास फंडिंग की कमी है। ऐसी स्थिति में किसानों की आय बढ़ाना, अंधेरे में तीर मारने जैसा है।

मप्र की राजधानी भोपाल से 53 किमी की दूरी पर बसा गांव है बनखेड़ी। यहां 246 परिवारों में 1,116 लोग रहते हैं। अमरावद बांध से निकली नहर गांव को दो हिस्सों में बांटती है। यहां प्रवेश करते ही पंचायत, स्कूल, आंगनवाड़ी भवन नजर आते हैं। ज्यादातर ग्रामीणों की आजीविका किसानी है। गांव से 5 किमी दूर कृषि विज्ञान केंद्र है। यह केंद्र यहां मार्च 2004 से काम कर रहा है। 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के मकसद से केंद्र ने बनखेड़ी को मॉडल विलेज के रूप में चुना है। किसानों को केंद्र की गतिविधियों के बारे में तो जानकारी है, लेकिन आय दोगुनी करने के बारे में उन्हें जानकारी नहीं है। ऐसी कोई बड़ी बैठक या कार्यक्रम भी नहीं हुआ। गांव में ऐसा कोई बोर्ड भी नजर नहीं आता है, जिससे यह समझा जा सके कि दो साल बाद यह गांव आय को दोगुनी करके दिखा देगा। किसानों को भी इस बात का भरोसा कम है। किसान रघुवीर सिंह भदौरिया कहते हैं कि जब उन्होंने 2016 में अपने 9 एकड़ के खेत में 21 क्विंटल धान पैदा की थी तब उन्हें 4500 रुपए का रेट मिला था, इस साल उन्होंने 51 क्विंटल धान पैदा की है और रेट 2100 से ज्यादा नहीं चल रहा। इससे वह खासे दुखी हैं। नंदलाल लोधी को लॉकडाउन के कारण टमाटर खेत में सड़ाना पड़ा। उनका 100 क्विंटल टमाटर खेत में ही सड़ गया। कुछ माल बिका तो 300 रुपए कैरेट का रेट मिला, और अब जब किसान के पास टमाटर नहीं है तो वह 1100 रुपए प्रति कैरेट बिक रहा हैं उनका मानना है कि किसानों को फायदा नहीं होता, केवल व्यापारियों को ही फायदा मिलता है।

गांव के युवा दीपक लोधी का कहते हैं कि जिस मकसद से किसी गांव को गोद लिया जाता है, पर वह इस तरह से लागू नहीं हो पाता कि मकसद पूरा हो सके। जैसे कृषि विज्ञान केंद्र ने बनखेड़ी को गोद तो ले लिया, लेकिन इसके लिए योजनाबद्ध काम नहीं हुआ है। केंद्र कभी-कभार महिला समूह की मीटिंग आंगनवाड़ी में करता है। महिलाओं को मिर्ची, टमाटर, बैंगन के पौधे भी दिए जाते हैं, लेकिन इस साल कोरोना में कोई भी मीटिंग नहीं हो पाई है। हमीर सिंह लोधी ने 25 डिस्मिल रकबे में लहसुन और टमाटर लगाया है। वह कृषि विज्ञान केंद्र में नियमित जाते हैं और वहां की जानकारी को जरूरी भी मानते हैं। हालांकि उनके पास अपनी जमीन नहीं है, पर वह बटाई लेकर 30 एकड़ में खेती कर रहे हैं। उनका कहना है कि उनकी आय में डयोढ़ा का इजाफा हुआ है और यह दोगुनी भी हो जाएगी।

● **सिद्धार्थ पांडे**

नमूने लेकर गए लौटे नहीं

मप्र के रायसेन जिले के कृषि विज्ञान केंद्र ने दो गांव बनखेड़ी और घाना को गोद लिया है। बनखेड़ी के अधिकांश किसानों को जानकारी नहीं है कि उनके गांव को गोद लिया गया है। 6 एकड़ जमीन पर खेती कर रहे किसान नंदलाल लोधी कहते हैं कि पहले की तुलना में उत्पादन तो बढ़ा है, लेकिन डीजल, खाद-बीज और दवाई का खर्चा इतना बढ़ गया है कि लाभ तो वहीं का वहीं है। सरपंच कल्याण सिंह लोधी कहते हैं कि केवीके वाले बुलाते हैं, नाश्ता कराते हैं और किसान भी सोचते हैं कि आय दोगुनी हो जाए पर यह कैसे होगी? वह उल्टे हमसे सवाल करते हैं कि आप ही बताओ प्रधानमंत्री ने 6 हजार रुपए दिए और लगे हाथ डीजल के दाम भी बढ़ा दिए, ऐसे में किसान की आय दोगुनी कैसे हो जाएगी। वह कहते हैं कि कई बार सिर्फ फोटो खिंचाने के लिए कार्यक्रम होते हैं। यहां से 40 किमी दूर गैरतगंज के पास घाना गांव को कृषि विज्ञान केंद्र ने न्यूट्री विलेज के रूप में चुना है। यहां की पानबाई ने बताया कि कुछ समय खेत से मिट्टी के नमूने लेकर गए थे, लेकिन लौटकर नहीं आए, न कोई जवाब दिया। मनबाई अहिरवार ने बताया कि एक बार टमाटर और पपीते के चार-चार पौधे देकर गए थे, जो सूख गए। उसके बाद उन्हें कुछ नहीं मिला। उन्हें नहीं पता कि उनके गांव में किसानों की आय दोगुनी करने के लिए कुछ खास किया जा रहा है। कृषि विज्ञान केंद्र, रतलाम ने जामथून और नवाबगंज गांव को गोद लिया है। नवाबगंज के किसानों का कहना है कि केवीके के अधिकारी 3 साल से लगातार संपर्क में हैं और डेढ़ से दो माह के बीच उनके खेतों में भी आते हैं।

करीब एक साल बाद मप्र विधानसभा का सत्र चल रहा है। सत्ता गंवा चुकी कांग्रेस के सामने सत्तापक्ष यानी भाजपा को घेरने का बड़ा मौका है। लेकिन अभी तक सदन में कांग्रेस भाजपा को घेरने में असफल रही है। जबकि पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस की महंगाई, बेरोजगारी, अपराध सहित कई ऐसे मुद्दे हैं, जिस पर सरकार को घेरा जा सकता है। लेकिन कांग्रेस सरकार को घेरने में नाकाम हुई है। अभी तक कांग्रेस ने जो प्रयास किए हैं, वे भी असर कारक नहीं रहे हैं।

● राजेंद्र आगाल

लोकतंत्र में सक्रिय विपक्ष का बड़ा महत्व होता है। विपक्ष जहां सरकार को निरंकुश होने से रोकता है, वहीं जनता के मुद्दों की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करता है। लेकिन मप्र में चल रहे विधानसभा के बजट सत्र के दौरान मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस पूरी तरह निष्क्रिय नजर आ रही है। अभी तक हुई विधानसभा की कार्यवाही पर नजर डालें तो भाजपा ही सत्तापक्ष और विपक्ष दोनों की भूमिका निभा रही है। विपक्षी पूरी तरह पस्त नजर आ रहा है, इसलिए सत्तापक्ष भी मस्त है। सदन में कांग्रेस गंभीर मुद्दों को उठाने के साथ ही उन पर चर्चा करने में भी कमजोर साबित हो रही है। सदन में कांग्रेस के विधायकों की उपस्थिति भी कम रहती है। ऐसे में सत्तारूढ़ भाजपा जैसा चाहती है, वह सदन को वैसा ही चलाती है। नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ की भूमिका भी न के बराबर दिख रही है। ऐसे में कांग्रेस के विधायक भी सरकार को घेरने में रूचि नहीं दिखा रहे हैं।

विधानसभा में लोक जीवन को अधिकता से प्रभावित करने वाले मुद्दों पर जद्दोजहद होना एक आम चलन है। राजनीतिक लोकतंत्र में जन विश्वास और मोह बनाए रखने के लिए यह बेहद जरूरी है। लेकिन मप्र के वर्तमान विधानसभा सत्र में ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। करीब एक साल बाद मप्र का विधिवत विधानसभा सत्र 22 मार्च से शुरू हुआ है। सत्र 33 दिनों के लिए आयोजित किया गया है और इसमें 23 बैठकें प्रस्तावित हैं। आगामी वित्तीय वर्ष 2021-22 का बजट 2 मार्च को पेश किया जाएगा। विधानसभा सचिवालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार, इस सत्र के लिए अब तक 5,391 प्रश्नों को अधिसूचित किया गया है, जबकि 157 कॉलिंग ध्यान गतियों, स्थगित करने के लिए 18 नोटिस और शून्य घंटे के लिए 52 नोटिस प्राप्त हुए हैं। इसलिए यह सत्र काफी महत्वपूर्ण है। लेकिन ऐसा लगता है, जैसे कांग्रेस ने सरकार के सामने हाथ खड़े कर दिए हैं।

अभिभाषण पर चर्चा नीरस

विधानसभा का बजट सत्र अध्यक्ष के चुनाव के साथ शुरू हुआ। भाजपा विधायक गिरीश गौतम विधानसभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। अध्यक्ष का चुनाव होने के बाद विधानसभा का बजट सत्र राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के अभिभाषण से औपचारिक रूप से शुरू हुआ। उन्होंने कहा कि कार्यभार संभालते समय सरकार के सामने दो चुनौतियां थीं। पहली कोरोना महामारी, जो तेजी से पैर पसार रही थी और दूसरी सरकार की वित्तीय स्थिति। प्रदेश में चारों ओर अविश्वास, असमंजस, आशंका और अव्यवस्था का वातावरण था। सरकार ने युद्ध स्तर पर दोनों मोर्चों पर काम शुरू किया और उसके सुखद परिणाम सामने आए। उसके अगले दिन से अभिभाषण पर चर्चा शुरू हुई। अभिभाषण में कई ऐसे मुद्दे थे, जिन पर विपक्ष दमदारी से सरकार को घेर सकता था। लेकिन विपक्ष का कोई भी नेता सरकार को कटघरे में खड़ा करने में विफल रहा। नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ के आरोप भी नीरस और बेअसर रहे। हालांकि कांग्रेस ने सरकार पर भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और महंगाई को लेकर आरोप लगाए, लेकिन उसका सरकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा।

उधर, मप्र के बजट सत्र के 5वें दिन राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के अभिभाषण पर मुख्यमंत्री शिवराज ने संबोधन दिया। उन्होंने विपक्ष को ऐसा करारा जवाब दिया कि उसकी बोलती बंद हो गई। उन्होंने कहा, विपक्ष बार-बार कह रहा है कि 2018 में कचरा साफ हो गया। लेकिन मैं बता दूं, **मेरे मन में एक भी बार यह नहीं आया कि मुझे मुख्यमंत्री बनना है।** शिवराज ने कहा- जब कमलनाथ की सरकार बनी तब मैंने सोच लिया था कि मुझे मुख्यमंत्री निवास खाली करना है। हम चाहते तो उस समय भी जोड़-तोड़ कर सकते थे। हम सोच सकते थे। उन्होंने कहा- उस समय भी कई मित्र हमारे साथ आना चाहते थे। लेकिन, सुबह होते ही मैंने कमलनाथ को बधाई दी। इतना वोट परसेंट कांग्रेस को मिला। उसकी वजह कर्जमाफी का ऐलान था। इस बात को मैं मानता हूं।

विधानसभा अध्यक्ष का पद 17 साल बाद विंध्य के हिस्से में

रीवा जिले की देवतालाब विधानसभा से भाजपा विधायक गिरीश गौतम मप्र विधानसभा के निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित अन्य ने गिरीश गौतम को अध्यक्ष चुनने का प्रस्ताव रखा। नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ ने इन प्रस्तावों का समर्थन किया। इस अवसर पर गौतम ने आश्वस्त किया कि वे परंपराओं को खरोंच नहीं आने देंगे। अध्यक्ष का पद 17 साल बाद विंध्य के हिस्से में आया है। इसके पहले श्रीनिवास तिवारी 24 दिसंबर 1993 से 11 दिसंबर 2003 तक विधानसभा अध्यक्ष रह चुके हैं। सूत्रों के मुताबिक सरकार पर विंध्य को पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने को लेकर काफी समय से दबाव बनाया जा रहा था। मंत्रिमंडल विस्तार में मौका नहीं मिलने से नाराजगी भी बढ़ रही थी। इसे थामने और क्षेत्रीय समीकरणों को देखते हुए गिरीश गौतम का नाम तय किया गया। हालांकि, यह आसान नहीं था क्योंकि पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ल और वरिष्ठ विधायक केदारनाथ शुक्ला भी प्रबल दावेदार थे। बताया जा रहा है कि विंध्य और महाकौशल से अभी कुछ विधायकों को निकाय चुनाव के बाद समायोजित किया जाएगा।

न सदन में घेर पाए और न बाहर

करीब एक साल पहले सत्ता गंवाने के बाद कांग्रेस ने दम भरा था कि वह भाजपा को चैन से नहीं बैठने देगी। लेकिन कांग्रेस सरकार को न तो सदन में घेर पा रही है और न ही बाहर। जब केंद्र में मनमोहन सिंह की सरकार थी और पेट्रोल-डीजल के दाम में 50 पैसे की भी बढ़ोत्तरी होती थी, तो भाजपा सड़क पर उतर जाती थी। खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने साइकिल चलाकर बढ़ी कीमतों का विरोध किया है। लेकिन कांग्रेस का हर आंदोलन प्रहसन नजर आता है। पेट्रोल-डीजल और रसोई गैस के बढ़ते दामों को लेकर सड़कों पर हल्ला बोल रही कांग्रेस ने अब आंदोलनों से हाथ पीछे खींच लिए है। यूथ कांग्रेस का 3 मार्च और उसके बाद 8 मार्च को महिला कांग्रेस का होने वाला विधानसभा का घेराव स्थगित हो गया है। कांग्रेस पार्टी ने कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों पर सरकार के जारी आदेश के कारण अपने आंदोलन फिलहाल स्थगित कर दिए हैं। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा कहते हैं कि सरकार सड़क पर महंगाई का विरोध करने की अनुमति से विपक्ष को रोक रही है। लेकिन, विधानसभा के अंदर कांग्रेस के विधायक पेट्रोल और डीजल के मुद्दे को लेकर एक बार फिर सरकार को घेरेंगे। दरअसल बीते दिनों महिला कांग्रेस की बैठक में पीसीसी चीफ कमलनाथ ने सरकार के खिलाफ महिलाओं को सड़क पर उतरने की सलाह दी थी। इसी के चलते महिला दिवस पर महिला

कमलनाथ और शिवराज के बीच तीखी नोक-झोंक

- कमलनाथ- आपने फसल बीमा का प्रीमियम जमा नहीं किया।
- शिवराज - हमने फसल बीमा की राशि किसानों को दी। मैं ओलावृष्टि के समय किसानों के पास जाता था लेकिन आप नहीं जाते थे। आप विधायकों से मिलते नहीं थे।
- कमलनाथ- मैं विधायकों को मिलने के लिए समय देता था ना कि टीवी पर सीरियल देखता था।
- शिवराज - आप खजाना खाली छोड़ गए। लेकिन हमने इसकी कमी महसूस होने नहीं दी।
- कमलनाथ - आपसे आंकड़ों के खेल में जीतना मुश्किल है।
- शिवराज - आज हिसाब-किताब पूरा हो जाए। कर्जा लेकर किसानों के खाते में पैसे डाले हैं तो आपको तकलीफ क्यों हो रही है। कोरोनाकाल में किसानों के खाते में पैसे डाले। उनकी फसल खरीदी।
- इस बीच गोपाल भार्गव ने विधानसभा में डिवीजन करने को लेकर कहा- खेल आपने शुरू किया है और हमने कहा था खत्म हम करेंगे।
- कमलनाथ- अकेला आपने शुरू किया था। जब आपने अध्यक्ष के चुनाव में कैंडिडेट खड़ा किया। आपने परंपरा तोड़ी।
- शिवराज- आपने सरकार में आते ही भाजपा नेताओं को निशाना बनाना शुरू कर दिया था। बदले की कार्रवाई आपने की। कुचलने वाली मानसिकता आप लोगों की थी। उच्च अधिकारियों की बोली लगी।
- कमलनाथ- आपके इस तरह के आरोप गलत हैं। आप मुझे सदन में नहीं बल्कि अकेले बता गए कि किन उच्च अधिकारियों की बोली लगी। यहां पर सदन को बताना चाहता हूं कि मैंने माननीय के कहने पर कई कार्रवाई को रुकवाया।
- शिवराज- कमलनाथ भी कहते हैं कि 2018 में कचरा साफ हो गया। लेकिन कांग्रेस से आए नेताओं के साथ में काम कर रहा हूं। यह सब बहुत अच्छा काम करते हैं। यह सब हीरे हैं।
- कमलनाथ- आप सभी हीरों को बचाकर रखिए। हम इन्हें पहले से जानते हैं।
- विधायक लक्ष्मण सिंह- (शिवराज के बार-बार बंटाधार की बात पर) आप सिर्फ बंटाधार की योजनाओं को अभी तक क्यों चला रहे हैं।
- शिवराज- मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पर फिर कभी चर्चा करेंगे।
- कमलनाथ - मेरा मुख्यमंत्री से निवेदन है कि बीती बातों को छोड़ें और आगे की बातें सदन को बताएं।
- शिवराज- मैं उसी का जवाब दे रहा हूं। हमने लाडली लक्ष्मी योजना से लेकर महिलाओं के लिए कई योजनाएं बनाईं। उनको सरकारी नौकरी में प्राथमिकता दी। लेकिन आपकी सरकार ने हमारी संबल योजना को बंद कर दिया। उसका नाम नया सवेरा कर दिया। लोगों को उसका फायदा नहीं मिला। आपने दीनदयाल रसोई योजना, मेधावी छात्र योजना को बंद कर दी।
- कमलनाथ- जब हमने मेधावी छात्रों को लैपटॉप योजना की जांच की तो पता चला कि उन्हें लैपटॉप मिल नहीं रहे थे।

कांग्रेस ने विधानसभा घेराव का ऐलान किया था। लेकिन, अब इसे स्थगित कर दिया गया है। वहीं भाजपा ने कांग्रेस के आंदोलन से स्थगित करने पर तंज कसा है। भाजपा के प्रदेश मंत्री रजनीश अग्रवाल कहते हैं कि सरकार के खिलाफ विपक्ष का विरोध प्रदर्शन अब तक फेल साबित हुआ है। आम लोगों का समर्थन कांग्रेस पार्टी को नहीं मिल रहा है और अब कांग्रेस पार्टी खुद संगठन में गुटबाजी से जूझ रही है। ऐसे में सरकार के जन हितैषी फैसलों पर सवाल उठाने की बजाय कांग्रेस को अंदरूनी गुटबाजी पर ध्यान देना चाहिए।

सदन में हंगामा भी नीरस

अभी तक सदन में जितने दिन भी कार्यवाही चली है, कांग्रेस ने जिन-जिन मुद्दों को लेकर हंगामा किया है, वे नीरस रहे हैं। किसानों को मिल रहे बिजली के बढ़े बिलों पर सदन में हंगामा हुआ। विधानसभा अध्यक्ष ने भी कहा- मेरे क्षेत्र के किसान भी बिजली बिलों से परेशान हैं। अध्यक्ष ने ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न तोमर को पूरे मामले की जांच करवाने को कहा। किसानों को अधिकृत कंपनियों के कृषि पंप दिए जाने के निर्देश दिए गए। भाजपा विधायक विजयपाल सिंह ने यह मामला उठाया था। इस दौरान हंगामा होने लगा। इस पर ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा कि इस मामले की जांच कराई जाएगी। वहीं भाजपा के ही विधायकों ने नगरीय प्रशासन विभाग के मंत्री को घेर लिया। रामपाल सिंह ने रायसेन जिले में आवास योजना में विसंगति का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि रायसेन में प्रधानमंत्री आवास योजना में अभी भी कई लोगों को आवास नहीं मिले हैं। उन्होंने इसमें गड़बड़ी का आरोप लगाया। इस दौरान प्रोटेम स्पीकर रहे रामेश्वर शर्मा ने भी इसी मुद्दे पर बात की। इसके बाद मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि इसका सर्वे कराया जाएगा और हर गरीब को आवास दिया जाएगा। सदन में विधायक महेंद्र हार्डिया ने इंदौर की कृषि विहार कॉलोनी का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि इस कॉलोनी में मोबाइल टॉवर स्थापित किया गया। इससे कैंसर के रोगियों की संख्या बढ़ने की आशंका है और कई जगह कैंसर के मामले देखे भी जा रहे हैं। इस पर नगरीय प्रशासन मंत्री ने कहा- इस मामले की जांच कराई जाएगी। शहर में उन कॉलोनियों की भी जांच की जाएगी, जहां इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। विधानसभा में जिन मुद्दों को विपक्ष को उठाना चाहिए, उन्हें सत्तापक्ष के विधायकों ने उठाया।

हालांकि पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमत और महंगाई के मुद्दे पर कांग्रेस ने सदन में कुछ दमदारी दिखाई। उसने इन मुद्दों को लेकर सदन से वॉकआउट भी किया। कुछ विधायक महंगाई के स्लोगन लिखे एप्रिन पहनकर पहुंचे। शून्यकाल में सज्जन सिंह वर्मा ने महंगाई का मामला उठाया तो कांग्रेस के अन्य विधायकों ने भी हल्ला मचाया। इसके बाद वे वॉकआउट कर गए। बाहर आकर उन्होंने गांधी प्रतिमा के सामने धरना देकर नारेबाजी की। लेकिन इसके बाद कांग्रेस का दम और कहीं नजर नहीं आया। विधानसभा में सत्तापक्ष हर समय कांग्रेस पर हावी दिखा। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने अपने अकाट्य जवाबों से विपक्ष को मुंह बंद रखने के लिए मजबूर किया। दरअसल, विपक्ष पूरी तैयारी के साथ सदन में कभी नहीं पहुंचा।

माननीयों की फिजूलखर्ची

बजट सत्र के दौरान माननीयों की फिजूलखर्ची भी चर्चा में रही। विधानसभा सत्र के दौरान ही एक रिपोर्ट सामने आई, जिसमें यह बताया गया कि किस तरह माननीयों पर पैसा खर्च किया जा रहा है। दरअसल, प्रदेश सरकार हजारों करोड़ रुपए के कर्ज में डूबी है। बैठकों और भाषणों में सरकारी खर्चों में कटौती की बात की जाती है, लेकिन फिजूलखर्ची के मामले में सरकार अभी भी पुराने ढर्रे पर ही चल रही है। विधायकों को हर महीने टेलीफोन भत्ते के नाम पर 10 हजार रुपए दिए जा रहे हैं। यह हास्यास्पद है कि मोबाइल कंपनियां इसके लिए महज 2399 रुपए चार्ज करती हैं, जबकि इसमें इंटरनेट का फ्री अनलिमिटेड डाटा भी मिलता है। बता दें, पहले विधायक बसों से यात्रा करते थे तो उन्हें इसका भी भत्ता मिलता था। लेकिन, बस यात्रा भत्ते को अप्रैल 2016 में खत्म कर दिया। क्योंकि विधायकों ने बस को छोड़कर निजी वाहनों से घूमना शुरू कर दिया था। इसके लिए उन्हें राज्य के अंदर हर 15 किमी पर 1500 रुपए दिए जाने लगे। इसे बाद में बढ़ाकर 2500 रुपए कर दिया गया। जानकारी के मुताबिक, 2016 में विधायकों की लॉटरी लग गई। इस साल में विधायकों का वेतन तीन गुना बढ़ाया (10 से 30 हजार रुपए) कर दिया गया। निर्वाचन क्षेत्र का भत्ता भी 25 हजार से बढ़ाकर 35 हजार रुपए किया गया। ये भी गौर करने वाली बात है कि राज्य में विधायकों का वाहन लोन और हाउस लोन बढ़ाए जाने की फाइल दो साल से रुकी पड़ी हैं।

जानकार बताते हैं कि वर्तमान में कुछ भत्तों की विधायकों की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जैसे, 2012 में कंप्यूटर भत्ता दस हजार था, उसे 2016 में बढ़ाकर 15 हजार करना। विधायक को एक कार्यकाल में 50 हजार रुपए लैपटॉप के लिए मिलना। विधायक को यात्रा भत्ता 15 किमी तक 1500 रुपए राज्य के भीतर और 2500 रुपए राज्य के बाहर मिलना। हर महीने स्टेशनरी एलाउंस 10 हजार रुपए मिलना। इनके अलावा विधायकों को जो अतिरिक्त सुविधाएं मिलती हैं उनमें अनलिमिटेड रेल कूपन, हर महीने राज्य के बाहर अधिकतम 30 हजार रुपए प्रतिमाह मिलना और राज्य के बाहर 15 रुपए। प्रतिकिमी की दर से वाहन भत्ता मिलना शामिल हैं। विधानसभा के पूर्व अधिकारियों का कहना है कि इस पूरे मामले पर रिव्यू की जरूरत है। सरकार चाहे तो ये पैसा बचा सकती है। ये भत्ते तब दिए जाते थे जब मंत्रियों और विधायकों का वेतन बहुत कम था। अब सरकार को इस पर गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। यहां से पैसा बचेगा तो राज्य सरकार बाकी जगह बढ़ रहे टैक्स को कम कर सकती है। सिर्फ टेलीफोन भत्ता ही नहीं, बिजली मद और कैंटीन में मिल रहा सब्सिडाइज भोजन भी खत्म होना चाहिए।

साइकिल से विधानसभा पहुंचने में विधायकों का दम फूला

आज से मप्र विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत हो गई है। तेल की बढ़ती कीमतों को देखते हुए कई कांग्रेसी नेता साइकिल चलाकर विधानसभा पहुंचे, लेकिन आधे रास्ते में ही उनकी हालत खस्ता हो गई। ज्यादातर विधायक बीच रास्ते में व्यापमं के पास साइकिल से उतर गए और अपनी कार से विधानसभा पहुंचे। बीच रास्ते में चढ़ाई आने की वजह से विधायकों ने साइकिल आधे रास्ते छोड़ दी थी। इसके बाद पूर्व मंत्री और विधायक पीसी शर्मा, जीतू पटवारी साइकिल से उतरकर अपने वाहन से विधानसभा पहुंचे। इसके अलावा विधायक आरिफ मसूद, कुणाल चौधरी विधानसभा तक साइकिल से पहुंचे। इसके पहले पुलिस ने पीईबी के सामने बैरिकेड्स लगाकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रोक दिया था और विधायकों को ही विधानसभा जाने दिया। पीसी शर्मा, जीतू पटवारी, संजय यादव, कुणाल चौधरी समेत अन्य विधायक शिवाजी नगर 6 नंबर बस स्टॉप पर पहुंच गए थे। इससे पहले कांग्रेस ने पेट्रोल-डीजल और महंगाई बढ़ने के विरोध में आधे दिन का बंद बुलाया था। विधायक पीसी शर्मा ने बताया कि पेट्रोल-डीजल की कीमत करीब 100 रुपए है और रसोई गैस का सिलेंडर 800 रुपए के पार चला गया है। शर्मा ने कहा कि साल 2014 में अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत 112 डॉलर प्रति बैरल थी। उस समय कांग्रेस सरकार थी और पेट्रोल के दाम 60 और डीजल 55 रुपए प्रति लीटर पर बिकता था। वहीं घरेलू गैस की कीमत 400 रुपए थी। शर्मा ने आगे कहा कि उस समय भाजपा के नेता कहते थे कि हमारी सरकार बनेगी तो पेट्रोल-डीजल सस्ता करेंगे।

कांग्रेस में अंदरूनी लड़ाई

विधानसभा में कांग्रेस की कमजोर परफॉर्मेंस की सबसे बड़ी वजह है पार्टी में अंदरूनी लड़ाई। जानकारों का कहना है कि कांग्रेस पार्टी एक बार फिर अपने भीतर उठते सवालों से जूझ रही है। असंतुष्ट आवाजें उसे परेशान कर रही हैं। ऐसे समय में जब 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों का बिगुल बज चुका है, राजनीतिक दल अपना जनाधार बटोरने में जुटे हैं, कांग्रेस के कुछ वरिष्ठ नेता जम्मू में इकट्ठा होकर अपनी अंतरात्मा की आवाज सुना रहे हों, तो इसे क्या कहेंगे। राजनीतिक दलों के अच्छे और बुरे दिन आते रहते हैं, पर बुरे दिनों में जो नई रणनीति के साथ उठने का साहस रखते हैं, वही दोबारा कामयाबी हासिल कर पाते हैं।

इस दृष्टि से कांग्रेस में लगातार हताशा नजर आ रही है। फिलहाल उसके केवल दो नेता जमीन पर उतरकर संघर्ष करते देखे जा रहे हैं और वे दोनों बिल्कुल नए हैं। राहुल गांधी चुनावी राज्य तमिलनाडु के दौरे पर हैं, तो प्रियंका गांधी उप्र में किसानों, मजदूरों, दलितों के मुद्दे उठाती रैलियां कर रही हैं। मगर मप्र के एक-दो वरिष्ठ नेताओं को छोड़कर केंद्रीय कमान संभालने वालों में से एक में भी ऊर्जा नजर नहीं आ रही। हालांकि यह पहली बार नहीं है। कांग्रेस में तो फिलहाल यह परंपरा ही बन गई है। शायद कांग्रेस के नेताओं को यह नहीं मालूम कि उन्हें जमीन पर उतरने की जरूरत है। हकीकत यह है कि पार्टी वातानुकूलित कमरों में बैठकर नहीं चलाई जाती, उसके लिए जमीन पर उतरकर पसीना बहाना पड़ता है। सिर्फ सैद्धांतिक बातों से जनाधार जोड़कर रखना संभव नहीं हो पाता।

मगर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता इस हकीकत को जानते हुए भी पसीना बहाने को तैयार नजर नहीं

आते। जबसे वह सत्ता से बाहर हुई है, केंद्र में लोग उसी से विपक्ष की भूमिका निभाने की उम्मीद करते हैं, पर अनेक अनुकूल अवसर आने के बावजूद उसके नेता हाथ पर हाथ धरे बैठे नजर आए। दरअसल, कांग्रेस नेताओं को आदत पड़ चुकी है कि जब सत्ता हाथ में आ जाती है, तो उसमें हिस्सेदारी के लिए तो फौरन लपक लेते हैं, पर जमीन पर उतरने से बचते रहते हैं।

भाजपा को सामंजस्य की चुनौती

वर्तमान दशक में शिव 'राज' को और मजबूत बनाने के लिए शिवराज और वीडी के सामने कई चुनौतियां आएंगी। वर्तमान में नगरीय निकाय चुनावों के साथ ही सत्ता, संगठन और संघ के बीच सामंजस्य की चुनौती है। इसे संयोग कहें या सियासी घटनाक्रम प्रदेश में शिवराज और वीडी की जोड़ी बनते ही कमलनाथ सरकार की स्थिति डांवाडोल होने लगी। करीब एक पखवाड़े के घटनाक्रम के बाद कमलनाथ सत्ता से बाहर हो गए। डेढ़ साल के अंतराल के बाद मप्र में भाजपा सत्ता में लौटी। दोनों के लिए चुनौती भी यहीं से शुरू हुई, क्योंकि सत्ता वापसी कांग्रेस के उन 22 विधायकों की बगावत से हुई थी, जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ भाजपा में आए थे। इनका सरकार व संगठन में समायोजन और पार्टी के पुराने साथियों की असहजता शिवराज और वीडी के लिए कठिन दौर रहा। इस बीच पूरा विश्व कोरोना की चपेट में था, तो मप्र में भी स्थितियां असामान्य हुईं। संगठन में समरसता बनाए रखना, 22 पूर्व विधायकों पर कांग्रेस के **सियासी हमले, आरोप-प्रत्यारोप** और अपने पुराने साथियों की असंतुष्टि शिवराज और वीडी के लिए कठिन हालात बना रहे थे। इस बीच अक्टूबर-नवंबर में 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए, तो एक दौर ऐसा भी आया जब भाजपा को कांग्रेस से ज्यादा खतरा अपने असंतुष्ट नेताओं से दिखने लगा। कांग्रेस संकेत देती रही कि वह 'कांटे से कांटा' निकालेगी यानी भाजपा उनके बागी विधायकों को टिकट देती है, तो कांग्रेस भी भाजपा के असंतुष्टों को मौका देगी। सांगठनिक कौशल देखिए कि 28 सीटों में कहीं भी भाजपा को विद्रोह का सामना नहीं करना पड़ा। एक भी नेता पाला बदलकर कांग्रेस में नहीं गया। भाजपा सत्ता बचाने के लिए एकजुट रही, कांग्रेस विपक्ष में होकर भी खेमों में बंटती नजर आई। इस हालात ने चुनाव परिणाम भी तय किए, जिसमें 19 सीट भाजपा और 8 सीट पर कांग्रेस जीती।

सिंधिया को भाजपा ने मप्र से राज्यसभा भेजा, तो क्षेत्रीय और जातिगत समीकरणों को एक तरफ रखकर उनके समर्थकों को कैबिनेट में भरपूर जगह दी। उपचुनाव में भी टिकट सिंधिया समर्थकों को ही दिए गए। सिंधिया से कमिटमेंट के चलते इन निर्णयों का संगठन में विरोध तो नहीं हुआ, लेकिन माना गया कि पार्टी असंतोष के बारूद के ढेर पर आ चुकी है। कहा जाने लगा कि इन हालातों से निपटना शिवराज-वीडी के लिए मुश्किल होगा। शिवराज-वीडी के नेतृत्व कौशल की परीक्षा का यह लंबा दौर चला। लेकिन दोनों ने न केवल उस परीक्षा को अव्वल दर्जे से पास किया। बल्कि मप्र में भाजपा के लिए एक ऐसी नींव रख दी है, जिसे उखाड़ पाना अब कांग्रेस के बस की बात नहीं है। अब आने वाला समय अलग तरह की चुनौतियों का होना तय है। स्थानीय निकायों के चुनाव सामने हैं और इसके बाद पंचायत चुनाव में भी अप्रत्यक्ष रूप से पार्टियां दमखम लगाएंगी। इन चुनावों को कांग्रेस विधानसभा चुनाव की जमीनी तैयारी मानकर चल रही है। यदि निकाय और पंचायत चुनाव में कांग्रेस कड़ी टक्कर देने में सफल रही, तो 2023 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को खासी मुश्किलें हो सकती हैं। शिवराज और वीडी ये अच्छी तरह समझते हैं, इसलिए इन चुनाव को जीतना बेहद जरूरी हो गया है। यही उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी।

बजट से काफी उम्मीद

मप्र के 2 मार्च को आने वाले बजट में आम जनता को राहत मिलने की उम्मीद कम है। वैसे सरकार भले ही नया टैक्स नहीं लगाने पर विचार कर रही हो, लेकिन पेट्रोल-डीजल पर वैट भी घटने के संकेत नहीं मिल रहे हैं। हालांकि इस दौरान कर्मचारियों, किसानों और महिलाओं के अलावा कई अन्य क्षेत्रों पर फोकस रहने की उम्मीद है। इन सबके बीच चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग दावा कर रहे हैं कि यह आम लोगों का बजट है और कल्याणकारी बजट है। इस बार मप्र का बजट 2 लाख 40 हजार करोड़ रुपए तक का हो सकता है। यह पिछले साल की तुलना में सात से दस फीसदी तक बढ़ने वाला है। बजट में पेट्रोल-डीजल पर वैट घटाने की संभावना कम है। सरकार न ही कोई नया टैक्स लगाएगी। शराब पर भी यही स्थिति रहेगी। जबकि गैस पीड़ित विधवा महिला की पेंशन फिर शुरू करने का प्रावधान होगा। इसके अलावा बजट में नर्मदा एक्सप्रेस-वे, अटल प्रोग्रेस-वे के रास्ते में इकोनॉमिक कॉरिडोर और इंडस्ट्रियल निवेश को बढ़ाने के लिए नए प्रावधान किए जा रहे हैं। इस बजट में सरकार का फोकस प्रदेश के साढ़े सात लाख कर्मचारियों और चार लाख पेंशनर्स पर रहेगा। 7.50 लाख कर्मचारियों को दो वेतन वृद्धि एक साथ मिलने की उम्मीद है। 2020 और 2021 की वेतन वृद्धि देने की घोषणा सरकार कर सकती है। इसके अलावा 25 फीसदी तक डीए की भी व्यवस्था होने की उम्मीद है। हालांकि इस व्यवस्था से 4 से 5 हजार करोड़ का खर्च आएगा। बजट में किसानों को राज्य की ओर से 4 हजार रुपए सम्मान निधि अब बराबर मिलेगी। साथ ही बजट में मप्र में 9 नए मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा होगी। 6 केंद्र सरकार की मदद से और 3 मप्र खोलेगा। मेडिकल कॉलेज शिवपुरी, राजगढ़, मंडला, सिंगरौली, नीमच, मंदसौर, छतरपुर, दमोह और सिवनी में खुल सकते है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने बजट को कल्याणकारी बताया है। उन्होंने कहा कि यह बजट विकास करने वाला और जन कल्याणकारी होगा। बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर विश्वास सारंग ने कहा, 'यह बात सही है कि कोविड का संक्रमण बढ़ा है लेकिन हमारी सरकार पूरी तरह सतर्क है, क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठकें हुई हैं, वैक्सीनेशन के साथ गाइडलाइंस का पालन सख्ती से कराया जाएगा।' उद्योग जगत उम्मीद कर रहा है कि बीते साल जो बजट में कटौती की गई थी सरकार उसकी भरपाई करेगी। खासकर सब्सिडी वाले मद में अधिक राशि आवंटित की जाएगी। इससे सूक्ष्म, लघु व मध्यम श्रेणी के उद्योगों की रुकी हुई करोड़ों की सब्सिडी एक बार फिर उद्योगों को मिलना शुरू हो सकेगी।

लंगड़ा लोकतंत्र

अब जब 'द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट' के ताजा लोकतंत्र सूचकांक में देश के लोकतंत्र को 'लंगड़ा' करार दिया गया है, तब गत 24 दिसंबर को किसान आंदोलन के समर्थन में मार्च निकालने और राष्ट्रपति से मुलाकात करने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा संवाददाताओं से कही यह बात याद आती है कि देश में लोकतंत्र कल्पना भर में रह गया है। यह भी याद आता है कि तब सत्तारूढ़ भाजपा के प्रवक्ताओं ने किस कदर उनकी खिल्ली उड़ाई थी। लेकिन अब उनके पास ताजा लोकतंत्र सूचकांक पर प्रतिक्रिया के लिए शब्दों का तांता पड़ गया है। कारण यह कि यह सूचकांक किसी विपक्षी नेता या भाजपा व उसकी मोदी सरकार के आलोचक का विश्लेषण नहीं है, जिसे स्वीडन की पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग द्वारा किसान आंदोलन के समर्थन में किए गए ट्वीट की तरह किसी साजिश से जोड़कर वे आसानी से अपने हो-हल्ले की भेंट कर सकें।

इस सूचकांक की प्रमाणिकता असंदिग्ध मानी जाती है और उसे दुनियाभर में लोकतंत्र की वास्तविक स्थिति के आंकलन के लिए बेझिझक इस्तेमाल किया जाता है। इससे जुड़ी 'डेमोक्रेसी इन सिकनेस एंड इन हेल्थ' शीर्षक रिपोर्ट के अनुसार देश का लोकतंत्र 2020 में तो 2019 के मुकाबले दो अंक ही नीचे गिरा है- 51वें से 53वें स्थान पर लेकिन इस गिरावट को ठीक से समझने के लिए जानना चाहिए कि 2014 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा सत्ता में आई, तो इसकी रैंकिंग 7.29 अंकों के साथ 27वीं थी, जो अब 6.61 अंकों के साथ 53वीं पर लुढ़क गई है।

दूसरे शब्दों में कहें तो तब के मुकाबले वह आधा रह गया है। जैसा कि रिपोर्ट में बताया गया है, भाजपा की पिछले छह-सात साल की सत्ता 'लोकतांत्रिक मूल्यों से पीछे हटने' और 'नागरिकों की स्वतंत्रता पर कार्रवाई' के रास्ते चलकर आधे लोकतंत्र को खा गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि मोदी सरकार ने 'भारतीय नागरिकता की अवधारणा में धार्मिक तत्व को शामिल किया है और कई आलोचक इसे भारत के धर्मनिरपेक्ष आधार को कमजोर करने वाले कदम के तौर पर देखते हैं', जबकि 'कोरोनावायरस की वैश्विक महामारी से निपटने के तरीके के कारण 2020 में देश में नागरिक अधिकारों का और दमन हुआ।' इसी का फल है कि ताजा सूचकांक में भारत को अमेरिका, फ्रांस, बेल्जियम और ब्राजील आदि 52 देशों के साथ 'त्रुटिपूर्ण', दूसरे शब्दों में कहें तो, 'लंगड़े लोकतंत्र' के तौर पर वर्गीकृत किया गया है। यह स्थिति कम से कम दो कारणों से बहुत चिंतित करती है। पहला यह कि यह गिरावट लगातार होकर रह गई है, जिससे स्वत: सिद्ध है कि किसी भूल-चूक का नहीं बल्कि सोची-समझी कार्रवाइयों का नतीजा है। दूसरा यह कि चूंकि ये सोची-समझी कार्रवाईयां **बदस्तूर** हैं, यह उम्मीद भी नहीं है कि आगे स्थिति में कोई सुधार होगा।

पिछले साल जम्मू-कश्मीर की बाबत वहां के निवासियों को विश्वास में लिए बगैर किए गए फैसले और संशोधित नागरिकता कानून व राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर को लेकर शुरू हुए उद्वेलनों के इस साल कारपोरेटपरस्त कृषि कानूनों के विरुद्ध किसानों के आंदोलन और उसके दमन के सिलसिले तक देश के लोकतंत्र को संभाल पाने में सत्ताधीशों की अनिच्छाभरी नाकामी इस बाबत खुद ही इतना सब कह देती है कि आईने की तरह सब कुछ साफ हो जाता है। आज की तारीख में यह एक खुला हुआ तथ्य है कि जम्मू-कश्मीर में संविधान का अनुच्छेद-370 अथवा राज्य की विशेष स्थिति ही खत्म नहीं की गई, नागरिकों के मौलिक अधिकार भी दांव पर लगा दिए गए थे। लंबे वक्त तक इंटरनेट पर पाबंदी, मीडिया पर लगाम और विपक्ष पर कार्रवाई जैसे कार्यों से भी लोकतंत्र को बाधित किया जाता रहा था। अब राजधानी दिल्ली में किसान आंदोलन से निपटने के नाम पर भी वैसे ही हालात बना दिए गए हैं, जहां किसानों को रोकने के लिए न सिर्फ सड़कें खुदवाई या उन पर कीलें ठुकवाई जा रही हैं, बल्कि ऐसी कंटीली बाड़ भी लगाई जा रही हैं, जैसी सीमाओं पर दुश्मन को रोकने के लिए भी नहीं लगाई जातीं।

सत्ताधीशों के ऐसे कृत्य किसी भी नजरिए से लोकतांत्रिक नहीं कहे जा सकते और न लोकतंत्र सूचकांक में देश को बेहतर जगह दिला सकते हैं। सो भी, जब किसान समूह नागरिकों को प्राप्त शांतिपूर्ण प्रदर्शन के अधिकार के अहिंसक इस्तेमाल के अलावा कुछ कर ही नहीं रहे और सत्तापक्ष कभी **उन्हें विपक्ष** द्वारा भटकाया हुआ, कभी आतंकवादी या खालिस्तानी और देशद्रोही बता और कभी अंतरराष्ट्रीय साजिशों से जोड़ रहा है। उनके आंदोलन के बारे में कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो, पॉप आइकन रिहाना, पर्यावरण प्रवक्ता ग्रेटा थनबर्ग और अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की भतीजी मीना हैरिस के बयान आते हैं, तो वह उन्हें आपत्तिजनक बताने और उनके पीछे साजिश सूंघने लगता है लेकिन अमेरिका के बाइडन-प्रशासन की 'रामाय स्वस्ति, रावणाय स्वस्ति' जैसी टिप्पणी के बाद लाल किले की 26 जनवरी की घटना को कैपिटल हिल पर डोनाल्ड ट्रंप समर्थकों के हमले जैसी बताने लग जाता है।

● **राजेश बोरकर**

देश में दिखा दोहरा कानून

प्रधानमंत्री मोदी जिस न्यू इंडिया का जिक्र करते नहीं थकते, उसकी ओर यात्रा में उनकी सरकार के फैसले और कार्रवाईयां लोकतंत्र के लिए इतनी घातक क्यों साबित हो रही हैं? क्यों उनके लिए सत्ता की सुरक्षा इतनी अहम हो गई है कि कोरोना जैसी आपदा को भी लोकतंत्र को सीमित करने व खाई में गिराने के सरकारी अवसर में बदल दिया जाता है? एक ओर 'दो गज की दूरी और मॉस्क है जरूरी' के नियम से लोगों को एकजुट होने से सख्ती से रोका जाता है और दूसरी ओर 'अपनी' रैलियां, सभाओं और अन्य आयोजनों में उसकी खिल्ली उड़ाई जाती है। सोचिए जरा, क्या अर्थ है इसका? अगर यह कि देश के लोकतंत्र को निर्बल व बीमार बनाए जाने की कोशिशों को इसलिए गंभीरता से नहीं लिया जाना चाहिए कि जनसंख्या विस्फोट के कारण वह 'दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र' तो बना ही हुआ है, तो यह भी उक्त गिरावट जितना ही चिंताजनक है। इस चिंता से संदर्भित होकर यह सवाल और जरूरी हो जाता है कि जब हमारे सत्ताधीश हमारे दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का आधा हिस्सा हजम कर गए हैं, हम क्या कर रहे हैं? उसे दुनिया का सबसे बढ़िया लोकतंत्र बनाने का कोई सपना हमारे पास बचा है या नहीं?

इन दिनों जनता में नंबर एक चर्चा, नंबर एक सवाल है विपक्ष कहां है? पेट्रोल-डीजल के दाम रिकार्ड तोड़ ऊंचाई पर है, महंगाई बढ़ रही है और लोगों का रोना है कि विपक्ष नहीं है। दरअसल, विपक्ष को अपनी भूमिका का अंदाजा ही नहीं है। वह केवल बयानों तक अपने आपको समेटे हुए है।

विपक्ष कहां है?

लोकतंत्र में विपक्ष की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगर यह कहा जाए कि वह सत्तापक्ष को निरंकुश होने से रोकता है तो इसमें कोई अतिश्योक्ति नहीं होगी। लेकिन भारत में तो ऐसा लगता है जैसे यहां विपक्ष नाम की कोई चीज ही नहीं है। देश में महंगाई, बेरोजगारी चरम पर है। लेकिन विपक्ष चुप है। लोग सवाल पूछने लगे हैं कि आखिरकार विपक्ष कहां है? सचमुच विरोधी पार्टियों, सिविल सोसायटी, मीडिया और पंच-सरपंच सभी यह रोना लिए हुए हैं कि ऐसा कोई नेता ही नहीं है, जो लोगों की बेहाली, गुस्से को नेतृत्व दे सके। उलटे नरेंद्र मोदी हर तरह से कमान में हैं। प्रत्यक्षत: यह बात सही होते हुए भी सतही है। जरा विचार करें भारत में कब पहले विरोधी नेता की जन कमान ने सत्ता परिवर्तन कराया। कभी नहीं। हमेशा जनता ने, लोगों के अनुभव और मौन खदबदाहट ने सत्ता परिवर्तन कराया। क्या मनमोहन सिंह ने 10 साल खटके से राज नहीं किया था? अन्ना हजारे, रामदेव, अरविंद केजरीवाल ने लोकपाल, भ्रष्टाचार पर जन असंतोष को आवाज जरूर दी लेकिन नरेंद्र मोदी सियासी विकल्प तो हाशिए में थे। वे गुजरात में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हुए दूर से तमाशा देख रहे थे। लोकपाल आंदोलन, भ्रष्टाचार के खिलाफ माहौल में उनका कोई योगदान नहीं था। भाजपा ने जब उन्हें प्रचार अभियान का प्रमुख बनाया तभी उनका मौका बना और अवसर का फायदा उठाया।

हां, याद करें डॉ. मनमोहन सिंह ने अपनी हर तरह से चलाई। अमेरिका के साथ अकल्पनीय एटमी करार की हिम्मत की। महंगाई और भ्रष्टाचार के शोर के बावजूद वे खटके से राज करते रहे। उनके आगे न लेफ्ट आंदोलन खड़ा कर पाया और न राहुल गांधी की मौजूदा स्थिति के मुकाबले लाख गुना अधिक लौह पुरूष समझे जाने वाले लालकृष्ण आडवाणी व उनकी टोली की सुषमा, जेटली, वेंकैया, अनंत कुमार आदि यह माहौल बना पाए थे कि मनमोहन सिंह हटाओ देश बचाओ।

सन् 2009 में मनमोहन सिंह-कांग्रेस के आगे आडवाणी-भाजपा-एनडीए की हार नेतृत्व की कसौटी पर चुनाव का होना नहीं था, बल्कि जनता का बिना खदबदाहट के होना था। सन् 2012 के बाद आंदोलनों से खदबदाहट बनी तो अपने आप सरकार विरोधी सुगबुगाहट बनी, वह फैली और परिस्थितियों ने नरेंद्र मोदी का वक्त बनवा दिया। तब और अब की स्थिति में फर्क यह है कि नरेंद्र मोदी और उनके मीडिया तंत्र ने पहले दिन से मिशन बनाया हुआ है कि राहुल गांधी पप्पू हैं और ऐसी धारणा बनी रहे। भाजपा और हिंदुवादी वोट पुख्ता बने रहें। लोग राहुल गांधी के हवाले सोचे ही नहीं कि विकल्प है या विकल्प हो सकता है। जाहिर है नरेंद्र मोदी ने गुजरात अनुभव, गुजरात मॉडल से हर तरह का यह प्रबंध बनाया हुआ है कि लोगों के जहन में या पार्टी-संघ में कोई विकल्प उभरे नहीं! वे लगातार फेल हों तब भी लोग यही सोचें कि विकल्प नहीं है। पर भारत की 138 करोड़ लोगों की भीड़ गुजरात नहीं है। कई लोग मानते हैं कि ईवीएम से भीड़ नियंत्रित है। निर्णायक मसला लोगों के **दिमाग की प्रोग्रामिंग** है। गौर करें पिछले जून से अब तक बदले पंजाब पर। पंजाब में क्या ईवीएम मशीन से वापस 2021 में मोदी का जादू निकल सकता है? कृषि कानूनों के बाद पंजाब में लोगों का मनोभाव जैसे बदला है वह क्या बिना नेतृत्व के हवा का बदलना नहीं है। फालतू बात है कि खालिस्तानियों ने लोगों को भड़काया। हकीकत में लोगों ने अपने आप खतरा बूझा, उनमें स्वंयस्फूर्त धारणाएं बनीं। खुद नरेंद्र मोदी, भाजपा-संघ में किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि सरकार के एक फैसले का इतना उलटा असर होगा। पंजाब इतना बदलेगा।

मूल वजह क्या? वही जो मनमोहन सिंह के आखिरी सालों या राजीव गांधी, या अटल

विपक्ष ने कोई बड़ी रचनात्मक भूमिका नहीं निभाई

हकीकत यह है कि विपक्ष में चाहे कांग्रेस रहे या भाजपा, किसी ने कोई बड़ी रचनात्मक भूमिका नहीं निभाई है और न कोई सार्थक आंदोलन खड़ा किया है। इंदिरा गांधी की इमरजेंसी के विरोध में भी छात्रों ने आंदोलन किया और बाद में अराजनीतिक व्यक्ति जयप्रकाश नारायण ने उसका नेतृत्व किया। इसी तरह मनमोहन सिंह के राज के विरोध में अराजनीतिक लोगों अन्ना हजारे, अरविंद केजरीवाल या बाबा रामदेव ने आंदोलन खड़ा किया। भाजपा के सारे मजबूत नेता उस समय सक्रिय थे लेकिन भाजपा ने मनमोहन सरकार के खिलाफ आंदोलन नहीं किया। भ्रष्टाचार के आरोप हों या निर्भया कांड जेएनयू और दिल्ली विश्वविद्यालयों के छात्रों ने आंदोलन किया और बाद में दूसरे लोगों ने कमान संभाली। जिस तरह से 10 साल भाजपा चुपचाप बैठी रही थी या प्रतीकात्मक विरोध किया था वैसे ही आज कांग्रेस कर रही है। हां, छात्र, किसान या दूसरे लोग पहले की तरह ही आंदोलन कर रहे हैं लेकिन अब उनके आंदोलन को देशद्रोही ठहराया जा रहा है। यह भी कमजोर विपक्ष की नहीं, तानाशाह सरकार की निशानी है।

बिहारी वाजपेयी या इंदिरा गांधी के पतन के आखिरी दो-तीन सालों में थी? सत्ता का अहंकार! सरकार ही सही बाकी सब गलत। भक्तों की फौज (याकि भाजपा के पक्के 20-22 करोड़ वोट) में आस्था, प्रचार से भले पेट्रोल-डीजल और महंगाई को देश-देश जरूरत में त्याग माना जाए लेकिन नौजवान बेरोजगारों की हकीकत में यदि यूथ प्रमोटर साइकिल में 100-200, 300 रुपए का पेट्रोल प्रतिदिन भराता रहा और इस सबकी महंगाई में अगले दो-तीन साल लगातार महंगाई में वह जिया तो 90 करोड़ मतदाताओं में दुखी लोगों की क्या तादाद बनेगी इसका अनुमान लगाया जा सकता है। वह न तो विकल्प सोचते हुए होगी और न पुलवामा, सर्जिकल स्ट्राइक के फार्मूलों में फिर पहले जैसा भभका बनेगा। ध्यान रखें इंदिरा गांधी के बांग्लादेश बनवाने और वाजपेयी की कारगिल डुगडुगी के बावजूद लोग भ्रम में अधिक नहीं रहे।

कह सकते हैं नरेंद्र मोदी अजेय हैं। हिंदू जाग गया है। मीडिया पूरी तरह नियंत्रित है। सो, राहुल गांधी और विपक्ष खड़ा नहीं हो पाएगा। या यह ख्याल कि वे इमरजेंसी लगा देंगे। सत्ता छोड़ेंगे ही नहीं। ईवीएम मशीन का खेल होगा। ये सब फालतू बातें हैं। नरेंद्र मोदी को अब दुनिया की अधिक चिंता करनी होगी। मोदी की, हिंदू की और हिंदुवादी राजनीति की अब वैश्विक तौर पर इतनी अधिक बदनामी हो गई है और मोदी सरकार गलतियों, अहंकारों के ऐसे चक्रव्यूह में अपने को उलझा चुकी है, देश में विभाजकता के इतने बीज फूट चुके हैं कि अंधा-काना-लूला विपक्ष भी वैसे ही उठ खड़ा होगा जैसे वाजपेयी के शाइनिंग इंडिया हल्ले में सोनिया गांधी का नेतृत्व उभरा था। राजीव गांधी के आगे वीपी सिंह भी खिचड़ी विकल्प थे तो इंदिरा गांधी के आगे जनता पार्टी का विकल्प भी भानुमति का कुनबा था जबकि राहुल गांधी आज हम दो, हमारे दो का नारा लगाने की हिम्मत तो लिए हुए हैं। राहुल गांधी जैसे बोल रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी जवाब में अपने मंत्रियों को उनके खिलाफ जैसे उतारते हैं उसमें आगे कौन पप्पू साबित होगा और कौन छप्पन इंची छाती वाला?

विपक्ष के मजबूत होने के क्या-क्या लक्षण होते हैं? किस तरह विपक्ष को मजबूत विपक्ष माना जाना चाहिए? अगर सदन में विपक्षी पार्टियों के ज्यादा सदस्य होंगे तब विपक्ष मजबूत माना जाएगा या विपक्ष का नेता खूब भाषण करने, आंदोलन करने और झूठ बोलने में प्रवीण हो तब विपक्ष को मजबूत माना जाएगा? संसद या विधानसभा ठप्प कर देने और सड़क जाम कर देने वाले को मजबूत विपक्ष माना जाएगा या सरकार की नीतियों का तार्किक और वैज्ञानिक तरीके से सतत् विरोध करने वाले को मजबूत विपक्ष माना जाएगा? निश्चित रूप से इन सवालों पर देश में कोई विचार नहीं करता है लेकिन मुंह उठाते ही यह कह देने वाले हर जगह बैठे हैं कि विपक्ष कमजोर है या देश में मजबूत विपक्ष होना चाहिए। सबसे मजेदार बात यह है कि ऐसा कहने वाले 100 फीसदी लोग भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थक हैं। अब इसके दो निष्कर्ष निकलते हैं। पहला, यह कि भाजपा और मोदी के समर्थक उनसे उबे हुए हैं और उनको लग रहा है कि विपक्ष में कोई मजबूत नेता होता तो उसे वोट कर देते, अगर ऐसा है तो यह सरकार के लिए खतरे की घंटी है। दूसरा, इस देश में तोतारटंत की परंपरा है इसलिए ज्यादातर लोग इसलिए यह रट लगा रहे हैं कि विपक्ष कमजोर है क्योंकि उनको लगातार यह फीड किया जा रहा है।

भाजपा देश के कई राज्यों में मुख्य विपक्षी पार्टी है और मजबूत भी है क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और लौह पुरुष जैसे नेता का नेतृत्व उसके पास है। फिर भी विपक्ष के तौर पर भाजपा क्या कर रही है? कांग्रेस या दूसरी क्षेत्रीय पार्टियों के विधायकों को तोड़ने की साजिश करने के अलावा मुख्य विपक्षी के तौर पर भाजपा कुछ कर रही है, इसकी मिसाल नहीं है। भाजपा किस राज्य में रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभा रही है? महाराष्ट्र में भाजपा संख्या के लिहाज से भी बहुत मजबूत है लेकिन क्या वह सरकार पर किसी तरह का दबाव बनाने में कामयाब हो रही है? दिल्ली में भाजपा के नेता कहते रहे थे कि कोरोना संकट के समय सरकार को काम करने देना चाहिए और सहयोग करना चाहिए लेकिन महाराष्ट्र में भाजपा के नेता कोरोना के पीक समय में राज्य सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे! क्या यही मजबूत विपक्ष की निशानी है?

● इन्द्र कुमार

आलाकमान के हिसाब से काम नहीं

लोकसभा चुनाव में छप्पर फाड़ जीत के बाद लग रहा था कि भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टीम देश के सोशल, पॉलिटिकल व इकोनॉमिक नैरेटिव को कंट्रोल किए रहेगी। जो कुछ हो रहा है वह या तो उनकी मर्जी और उनके किसी ग्रैंड प्लान के तहत हो रहा है या अपने आप भी हो रहा है तो वे इसका अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर ले रहे हैं। हर छोटी-बड़ी घटना भाजपा का मास्टरस्ट्रोक हो जा रही थी और विपक्ष ठगा सा देखता रह जाता था। लेकिन पिछले डेढ़ साल में हालात बदल गए हैं। अब ऐसा लग रहा है कि भाजपा और प्रधानमंत्री का घटनाओं पर नियंत्रण नहीं है और किसी भी घटना का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने की तिकड़म भी सफल होती नहीं दिख रही है। यहां तक भाजपा के अपने क्षत्रप स्वतंत्र होने लगे हैं और कर्नाटक से लेकर उप्र, बिहार, झारखंड, राजस्थान, मप्र तक कहीं भी भाजपा आलाकमान के हिसाब से काम नहीं हो रहा है। इस बदलाव का प्रस्थान बिंदु महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनाव को भी मान सकते हैं, जो लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद हुए थे और कोरोना वायरस का संक्रमण रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन को भी मान सकते हैं। यह तथ्य है कि लोकसभा के बाद जितने भी विधानसभा चुनाव हुए हैं उनमें भाजपा का वोट और सीटें घटी हैं। वह लोकसभा चुनाव का प्रदर्शन नहीं दोहरा पाई है। ज्यादातर राज्यों में वह पिछले विधानसभा चुनाव का भी प्रदर्शन नहीं दोहरा पाई। उसे महाराष्ट्र और झारखंड में सत्ता गंवानी पड़ी। दिल्ली में सत्ता हासिल करने का सपना 22 साल बाद भी पूरा नहीं हुआ और हरियाणा में दुष्यंत चौटाला के समर्थन से सत्ता बची। बिहार में जरूर भाजपा का प्रदर्शन सुधरा लेकिन उसे इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है।

बंगाल का 'महासंग्राम'

पश्चिम बंगाल में सत्ता का महासंग्राम जोरों पर है। टीएमसी और भाजपा में जंग छिड़ी हुई है। शह-मात के इस खेल में कभी भाजपा तो कभी टीएमसी आगे होती है। फिलहाल दोनों के बीच बराबरी का मुकाबला नजर आ रहा है। दोनों अपनी-अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। लेकिन चुनावी घोषणा नहीं होने के कारण प्रदेश की जनता फिलहाल मौन है। वहीं कांग्रेस और वामदल भी चुनावी मैदान में जोर-आजमाइश करने में जुटे हुए हैं। इसका असर यह हो रहा है कि पूरे देश की नजर पश्चिम बंगाल पर टिक गई है।

पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनावों के लिए अब दो माह से भी कम समय बचा है। यूं तो सभी प्रमुख राजनीतिक दलों ने चुनाव प्रचार के लिए युद्धस्तर पर तैयारियां पहले से ही शुरू कर दी हैं और प्रचार-प्रसार की गतिविधियां बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद से ही चल रही हैं। ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) का सीधा मुकाबला भाजपा से है। हालांकि वाम दलों और कांग्रेस का प्रभाव भी राज्य में है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। लेकिन ये दल वर्तमान माहौल और पिछले लोकसभा चुनाव को देखते हुए फिलहाल मुख्य दौड़ में नजर नहीं आ रहे। अब तक की गतिविधियों के मुताबिक, पड़ोसी राज्य बिहार से ताल्लुक रखने वाली जदयू और राष्ट्रीय जनता दल व महाराष्ट्र की शिवसेना भी बंगाल की राजनीति में अपना हाथ आजमाने की तैयारी में हैं।

पश्चिम बंगाल में करीब 30 फीसदी मुस्लिम आबादी है और मुस्लिम 100 से 110 सीटों पर जीत दिलाने में निर्णायक भूमिका अदा करते हैं। टीएमसी नेताओं का कहना है कि भाजपा की मदद करने के लिए और मुस्लिम मतों (वोटों) को बांटने की खातिर एआईएमआईएम को चुनाव लड़ाया जा रहा है। सन् 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान मुसलमानों ने अपने प्रतिद्वंद्वियों के खिलाफ टीएमसी का साथ दिया और अधिकांश ने ममता की पार्टी के पक्ष में मतदान किया। पार्टी के लिए मुस्लिम मतदाता एक अहम फैक्टर हैं, जो राज्य में भगवा पार्टी का खुलकर विरोध कर सकते हैं। हालांकि इस बीच हुगली में फुरफुरा शरीफ के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी ने भी सभी 294 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। उन्होंने इंडियन सेकुलरफ्रंट नाम की सियासी पार्टी भी बना ली है। मुस्लिमों के बीच प्रभावती अब्बास सिद्दीकी की इस पहल से कई राजनीतिक दलों का समीकरण गड़बड़ा सकता है।

सन् 2019 के लोकसभा चुनावों में पश्चिम बंगाल में अपनी बड़ी जीत से उत्साहित भाजपा नेता अमित शाह ने इस बार विधानसभा चुनावों में भी खुद मोर्चा संभाला है और सीधे टीएमसी से मुकाबला करने के लिए अपने को भाजपा के अगुवा के तौर पर पेश किया है। इसके लिए शाह ने भाजपा के अन्य वरिष्ठ नेताओं के साथ मिलकर रैलियों व अन्य **कार्यक्रमों की रणनीति** तैयार की और अपना मकसद पूरा करने के लिए टीएमसी के असंतुष्टों को पार्टी में शामिल करवाया।

टीएमसी नेताओं ने भाजपा में हिंदू मतों के ध्रुवीकरण और सोनार बांग्ला को बढ़ावा देने के लिए नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए का मुद्दा उठाया। सीएए और अल्पसंख्यकों खासकर घुसपैठियों को लेकर भाजपा ने आक्रामक रुख अख्तियार किया। इससे अल्पसंख्यकों के बीच असुरक्षा की भावना पैदा की, ताकि दूसरी ओर हिंदू मतदाताओं का ध्रुवीकरण हो सके। निसंदेह श्यामा प्रसाद मुखर्जी की

फिल्मी सितारों को जोड़ने का नया ट्रेंड शुरू

चुनावी राज्य पश्चिम बंगाल में नेताओं के पार्टियां बदलने का चलन फीका पड़ गया है और अब पार्टी में फिल्मी सितारों को जोड़ने का नया ट्रेंड शुरू हो चुका है। पिछले हफ्ते सत्तारुढ़ तृणमूल कांग्रेस के मुख्य विपक्षी दल भाजपा ने बंगाली फिल्म इंडस्ट्री के जाने-माने अभिनेताओं यश दासगुप्ता और हिरन चटर्जी को पार्टी में शामिल किया। बीते कुछ समय में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष और राज्य प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय के नेतृत्व में कई फिल्मी सितारे सहित आधा दर्जन अन्य लोगों ने पार्टी का दामन थाम लिया है। इन सबके बीच चर्चा हो रही है कि भाजपा में कुछ ऐसी हस्तियां शामिल हो सकती हैं, जो टीएमसी के कार्यक्रमों और चुनावी अभियान का प्रमुख चेहरा रहे हैं। मशहूर हस्तियों को आकर्षित करने के लिए भाजपा ने तृणमूल कांग्रेस की चुनावी किताब से एक पन्ना उधार ले रही है। बंगाली फिल्म इंडस्ट्री को टॉलीवुड के रूप में जाना जाता है और करीब एक दशक तक टीएमसी का टॉलीवुड पर एकाधिकार था। एक्टर शोली मित्रा और बिभास चक्रवर्ती, निर्देशक गौतम घोष, कवि जॉय गोस्वामी और अभिनेता-निर्देशक अपर्णा सेन इस लिस्ट में शामिल हैं।

विरासत के लिए भाजपा का दावा पार्टी के लिए फायदेमंद हो सकता है। वर्तमान में टीएमसी के भाजपा को बाहरी लोगों की पार्टी बताने के आरोपों को राज्य में साबित करने लिए लंबा रास्ता तय करना होगा। भाजपा में शामिल किए गए अधिकांश प्रभावशाली नेता मूल पार्टी के सदस्य नहीं हैं, लेकिन वे वाम मोर्चा अथवा टीएमसी को छोड़कर शामिल हुए हैं।

इसमें कोई अतिश्योक्ति नहीं है कि भाजपा ने सन् 2019 के लोकसभा चुनावों के बाद से पश्चिम बंगाल में एक लंबी छलांग लगाई है। सन् 2014 के आम चुनाव में 42 में से दो सीटों की गिनती से वह सन् 2019 में 18 सीटों तक पहुंची। राजनीति के जानकारों के अनुसार, इस जीत में भाजपा के हिंदू मतों की भूमिका रही। सन् 2014 और सन् 2019 के बीच किसी भी संसदीय क्षेत्र में मत फीसदी में कमी नहीं देखी गई, जबकि हर सीट पर वाम मोर्चे की हिस्सेदारी में कमी दर्ज की गई।

वाम दलों के नुकसान का सीधा फायदा भाजपा को हुआ, क्योंकि टीएमसी के मत हस्तांतरित नहीं हुए। मोटे तौर पर कहें, तो वामपंथी कैडर (संवर्ग) और समर्थकों ने टीएमसी को हराने के लिए भाजपा को रणनीतिक तरीके से समर्थन किया। सन् 2019 के बाद की अवधि में वाम दलों के साथ-साथ टीएमसी की भी हार हुई है। फिर भी भाजपा की रणनीति का एक प्रमुख घटक ममता की अगुवाई वाली टीएमसी के प्रमुख सहयोगियों, मंत्रियों, सांसदों और विधायकों को पार्टी में शामिल कराकर उसका मनोबल गिराना है। मीडिया के एक वर्ग की रिपोर्ट्स के अनुसार, पश्चिम बंगाल में भाजपा ने 23 जनवरी को कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल में एक सभा आयोजित करके नेताजी सुभाष चंद्र बोस की विरासत के जरिए चुनावी लाभ लेने का प्रयास किया है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में नेताजी की 125वीं जयंती मनाई गई, जिसे प्रधानमंत्री ने पराक्रम दिवस बताया। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जब संबोधित करने वाली थीं, तो समर्थकों ने जय श्रीराम के नारे लगाए। एक विशेषज्ञ ने बताया है कि टीएमसी प्रमुख के सामने सियासी रूप से अहम यह नारा लगवाया गया, ताकि दोनों के बीच तल्खी और बढ़े और वोट बैंक के लिए ध्रुवीकरण का रास्ता तैयार हो। कुछ पर्यवेक्षकों को लगता है कि नेताजी की विरासत को उपयुक्त बनाने के भाजपा के प्रयासों को वैचारिक विरोधाभासों से भरा हुआ है, क्योंकि नेताजी अपने राजनीतिक कैरियर के तौर पर पूरी तरह धर्मनिरपेक्ष थे।

टीएमसी को छोड़कर कुछ नेताओं के भाजपा का दामन थाम लेने के बावजूद तृणमूल पूरी तरह आश्वस्त है कि आगामी राज्य के विधानसभा चुनाव में उसी के नेतृत्व वाली सरकार बनेगी। हालांकि चुनाव से पहले नेताओं का पार्टी छोड़कर जाना टीएमसी जैसी क्षेत्रीय पार्टी के लिए बेहतर कदम नहीं हो सकता। फिर भी जब इसका सामना भाजपा जैसी राष्ट्रीय पार्टी के साथ होता है, तो आगामी चुनावी लड़ाई टीएमसी नेतृत्व के लिए न केवल अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए और अधिक प्रतिस्पर्धी हो जाती है, बल्कि रक्षात्मक तरीके से आक्रामक रुख अख्तियार करने से पार्टी के होने वाले नुकसान को भी नियंत्रित कर सकती है।

सन् 2019 में 18 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल करने वाली भाजपा 121 विधानसभा क्षेत्रों में तब्दील हो जाती है। लेकिन अमित शाह के 200 सीटों के अनुमान का अहसास करने के लिए भाजपा को मतों का फीसदी बढ़ाना होगा। टीएमसी के साथ-साथ कुछ राजनीतिज्ञ भी यह मानते हैं कि लोकसभा चुनाव का माहौल आमतौर पर विधानसभा चुनावों से अलग होता है और पार्टी नेतृत्व यह विश्वास दिलाता है कि टीएमसी का किला उखड़ने वाला नहीं है। टीएमसी के भीतर हाल ही में उथल-पुथल से पता चलता है कि आंतरिक असंतोष पार्टी के भीतर केंद्रीकृत शक्ति को संभालने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ रहे होंगे। कुछ विशेषज्ञों के अनुसार, टीएमसी में कुछ खामियां तो हैं, क्योंकि यह एक नेता के व्यक्तित्व पर केंद्रित पार्टी हो गई है। माना जाता है कि शुरुआती चरण में टीएमसी की एक आंदोलनकारी पार्टी के रूप में पहचान थी, जिसने राज्य में तीन दशकों से चली आ रही वाम दलों की **सरकार का किला ध्वस्त किया था।** इसमें स्थानीय और दिग्गज नेताओं के साथ-साथ बहुत सारे जमीनी कार्यकर्ता शामिल हुए थे, जिससे सत्ता हासिल करने में आसानी हुई थी। नेता के प्रति निष्ठा रखने वालों ने पार्टी को एक साथ रखा और वफादारी को संरक्षण प्रदान करके उनको पार्टी में शामिल कराया।

कुछ नेता-राजनेता पार्टी में अहमियत और पद की चिंता के चलते भाजपा में चले गए। इन नेताओं का मानना है कि उनको वह पद और मुकाम नहीं मिला, जिसके वे हकदार थे। वरिष्ठ टीएमसी नेतृत्व की ओर से इस बाबत ध्यान देने में देरी को भी जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। साथ ही इस बात पर भी जोर दिया जा रहा है कि टीएमसी को सभी को आत्मसात करने और आपसी मतभेद दूर करने की जरूरत है।

● **दिल्ली से रेणु आगाल**

ममता और टीएमसी के लिए चुनौती

तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष ममता बनर्जी के बाद पार्टी में उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी का कद दूसरे नंबर के नेता के तौर पर है। माना जाता है कि ममता बनर्जी की राजनीतिक विरासत के उत्तराधिकारी अभिषेक बनर्जी ही होंगे। इस स्थिति में अगर अभिषेक पर कोई आरोप लगता है, तो वह सीधे तौर पर ममता बनर्जी को नुकसान पहुंचाता है। ममता बनर्जी की पश्चिम बंगाल में एक बेदाग नेता की छवि बनी हुई है। इसे 'कट मनी' मामले से ही समझ सकते हैं। ममता बनर्जी ने कट मनी को लेकर टीएमसी नेताओं को ही आड़े हाथों ले लिया था। हालांकि, इससे पार्टी की छवि को धक्का लगा था। लेकिन, ममता बनर्जी ने इस मामले पर खुद को एक ब्रांड के तौर पर चमका लिया था। कोयला तस्करी के मामले में दूसरे मुख्य आरोपी विनय मिश्र को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी का करीबी माना जाता है। विनय मिश्र तृणमूल कांग्रेस के युवा मोर्चा की टीम का सदस्य था। अभिषेक बनर्जी टीएमसी की यूथ विंग के अध्यक्ष हैं। इसी कड़ी को जोड़ते हुए सीबीआई अब मुख्यमंत्री के भतीजे के घर पहुंच गई है। विनय मिश्र को अभिषेक बनर्जी के साथ कई विदेश यात्राओं पर साथ देखा गया है। इसे लेकर भाजपा ने टीएमसी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पामेला गोस्वामी की गिरफ्तारी के बाद बैकफुट' पर आई भाजपा, इस मामले पर अचानक से ही 'फ्रंटफुट' पर आकर बैटिंग करती नजर आने लगी है।

पांच राज्यों में चुनावी शंखनाद

5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखें तय कर दी गई हैं। पूरा चुनाव करीब एक महीने तक चलेगा और नतीजे आने में एक महीने से कुछ अधिक समय लगेगा। 27 मार्च को पहला और 29 अप्रैल को आखिरी मतदान होगा। मतों की गणना दो मई को होगी। केरल, तमिलनाडु और पुदुचेरी में एक ही दिन मतदान होगा। असम में तीन चरण में वोट पड़ेंगे और पश्चिम बंगाल में मतदान आठ चरणों में संपन्न होगा। इसे लेकर स्वाभाविक ही सवाल उठने शुरू हो गए हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने निर्वाचन आयोग पर सीधा हमला बोलते हुए पूछा है कि क्या ये तारीखें उसने भाजपा की योजनाओं को ध्यान में रखकर तय की हैं। ऐसी क्या अड़चन थी, जिसके चलते दक्षिण परगना जिले में तीन चरण में चुनाव कराने पड़ रहे हैं। इसके पहले पश्चिम बंगाल में दो चुनाव सात चरणों में संपन्न कराए गए थे। निर्वाचन आयोग ने इसके पीछे सुरक्षा व्यवस्था को बड़ा कारण बताया है। केंद्रीय रिजर्व बल की करीब सवा सौ बटालियनें वहां तैनात करने की योजना है। इसके अलावा सुरक्षा संबंधी जिम्मेदारियों के बंटवारे के लिए एक समिति भी गठित की जा रही है।

छिपी बात नहीं है कि पश्चिम बंगाल में चुनावों के दौरान बड़े पैमाने पर हिंसा की घटनाएं होती हैं। चुनाव की तारीखें घोषित होने के बहुत पहले से ही राजनीतिक दलों ने अपना प्रचार अभियान तेज कर दिया था और उसमें अक्सर भाजपा और तृणमूल कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़पें देखी गई हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान भी निर्वाचन आयोग के अनुभव कुछ अच्छे नहीं हैं। इसलिए उसका सावधानी बरतना समझा जा सकता है। मगर फिर भी निर्वाचन आयोग के सामने यह सवाल बना रहेगा कि वह चुनावों की अवधि को समेट क्यों नहीं पा रहा।

सीटों के लिहाज से देखें तो तमिलनाडु की विधानसभा सीटें पश्चिम बंगाल से कुछ ही कम हैं। जब तमिलनाडु में एक दिन में मतदान कराए जा सकते हैं, तो पश्चिम बंगाल में आठ चरण में कराने से क्यों नहीं बचा गया। चुनाव की अवधि कम करने पर लंबे समय से जोर दिया जाता रहा है। इसकी कई वजहें हैं। एक तो यह कि जब भी चुनाव लंबे समय तक खिंचता है, उसमें निष्पक्ष मतदान की संभावना क्षीण होती जाती है, क्योंकि राजनीतिक दलों को मतदाताओं को प्रलोभित-प्रभावित करने का समय अधिक मिल जाता है। फिर आचार संहिता के पालन को लेकर भी सवाल उठने लगते हैं। देखा जाता है कि ज्यादा चरणों में चुनाव होने की वजह से एक ही जिले के एक हिस्से में मतदान हो रहा होता है और उसी दिन दूसरे हिस्से में राजनेता अपनी रैलियां निकाल रहे होते हैं। पश्चिम बंगाल में भी यही होगा।

दूसरी महत्वपूर्ण बात कि चुनाव की अवधि जितनी लंबी होती है, उस पर खर्च भी उतना ही बढ़ जाता है। इतने समय तक सुरक्षा बलों की तैनाती और दूसरी व्यवस्थाओं पर खर्च बढ़ जाएगा। जब आमचुनाव के समय पूरे देश में एक साथ मतदान कराए जाते हैं, तब भी सुरक्षा व्यवस्था का ध्यान रखना पड़ता है। विधानसभा चुनाव में क्षेत्र छोटा होता है, इसलिए उसमें सुरक्षाबलों की कमी समझ से परे है। फिर जिन राज्यों में मतदान 6 अप्रैल को संपन्न हो जाएंगे, उन्हें भी नतीजों के लिए करीब महीनेभर तक इंतजार करना पड़ेगा। इतने दिनों तक वोटिंग मशीनों की सुरक्षा पर जो खर्च बैठेगा, सो अलग। इसलिए कम से कम दिनों में चुनाव कराने की व्यवस्था पर गंभीरता से विचार की जरूरत से इनकार नहीं किया जा सकता।

चुनाव आयोग की इस घोषणा के साथ ही सभी चुनावी राज्यों और पुडुचेरी में चुनाव आचार संहिता भी लागू हो गई है। विधानसभा चुनाव की यह प्रक्रिया उक्त राज्यों की कुल 824 सीटों पर संपन्न होगी, जिसमें 18.68 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे। इसके लिए 2.7 लाख मतदान केंद्र बनाए गए हैं। विभिन्न राज्यों में इस दौरान सत्ता बचाने और कब्जाने की दिलचस्प लड़ाई देखने को मिलेगी। पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव पर देशभर की नजरें हैं। भाजपा यहां सत्ता कब्जाने की जुगत में है और इसके लिए पार्टी ने यहां पूरी ताकत झोंक रखी है। वहीं ममता बनर्जी की अगुवाई में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस अपना गढ़ बचाने की कोशिश में लगी है। बीते कुछ समय में चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा और टीएमसी के बीच की जुबानी जंग ने खूब सुर्खियां बटोरीं।

● **कुमार विनोद**

टीएमसी-भाजपा के सामने चुनौती

पश्चिम बंगाल जहां सत्ता बचाने की चुनौती टीएमसी के पास है, वहीं पूर्वोत्तर के राज्य असम में यह चुनौती भाजपा के सामने है। यहां भाजपा का मुकाबला कांग्रेस और एआईयूडीएफ के गठबंधन से है। 2016 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के बीते 10 वर्षों के शासन का अंत करते हुए भाजपा यहां सत्ता में आई थी। यह पूर्वोत्तर के राज्यों में भाजपा की पहली ऐसी जीत थी, जिसने सियासी पंडितों को भी हैरान कर दिया था। बीते विवधानसभा चुनाव की बात करें तो भाजपा को यहां 60 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि उसके सहयोगियों असम गण परिषद को 14 और बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट को 12 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। भाजपा ने तत्कालीन सांसद सर्वानंद सोनोवाल को राज्य का मुख्यमंत्री बनाया था। कांग्रेस को उस चुनाव में 26 सीटें मिली थीं, जबकि सांसद बदरूद्दीन अजमल के नेतृत्व वाले एआईयूडीएफ को 13 सीटों पर जीत मिली थी। पश्चिम बंगाल में पिछला विधानसभा चुनाव सात चरणों में संपन्न हुआ था, जबकि इस बार यह आठ चरणों में कराया जा रहा है। राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसे लेकर केंद्र सरकार पर निशाना भी साधा है और कहा कि चुनाव भले ही आठ चरण में हों, पर जीत भाजपा की नहीं होगी। टीएमसी यहां बीते 10 वर्षों से सत्ता में है। वह सबसे पहले 2011 में वामपंथी सरकार को सत्ता से हटाकर यहां सत्तासीन हुई थी। इस बार राज्य में टीएमसी को भाजपा बड़ी चुनौती दे रही है। अब देखना यह है कि कौन बाजी मारता है।

आखिर किसका विकास हो रहा है?

छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से लगभग 120 किमी की दूरी पर पिथौरा नाम का ब्लॉक है। इस क्षेत्र का एक बहुत बड़ा इलाका घने जंगलों से आबाद है। यह जंगल न केवल वनस्पति और जीवों से समृद्ध हैं, बल्कि यहां पर पिछले 70-80 साल से कईं छोटे-बड़े गांव भी बसे हैं। इसी जंगल में 24 गांव की 474 हेक्टेयर भूमि, सोनाखान क्षेत्र में आती है। घने जंगल से सटे होने के कारण बाघमारा का यह क्षेत्र पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र में आता है और प्रस्तावित खनन से सीधे-सीधे प्रभावित होगा। प्रस्तावित खनन क्षेत्र में जंगली जीवों का एक बड़ा समूह है, जिसमें बाइसन, भालू, तेंदुआ, बाघ, हिरण और कई अन्य वन्य प्राणी शामिल हैं, यह इलाका हाथियों के मुक्त आवागमन का क्षेत्र भी है।

सोनाखान में सोने के खनन के लिए चिन्हित क्षेत्र में 2 लाख से अधिक पेड़ हैं, जिनमें बांस, तेंदू, महुआ और कई अन्य छोटे वन उत्पाद और कई प्रकार की इमारती लकड़ी शामिल हैं। इन समृद्ध, घने जंगलों के विनाश से कीमती वन्य जीवों का विनाश होगा और मानव-पशु संघर्ष और ज्यादा बढ़ेगा। यह क्षेत्र ऐतिहासिक रूप से भी महत्वपूर्ण क्षेत्र रहा है जो कि 18वीं सदी में शहीद वीर नारायण सिंह का जमींदारी क्षेत्र था। इससे यह बात तो स्पष्ट होती है कि वहां के बसे गांवों का वहां के जंगलों से कई पीढ़ियों पुराना रिश्ता है और संसाधनों से संपन्न अपनी प्रकृति के साथ लोग सौहार्दपूर्वक जीवन बिताते आए हैं।

आश्चर्य और विडंबना की बात यह है कि एक हाथ पर बीते कुछ सालों में इस (सोनाखान और उसके आसपास के) क्षेत्र में कुछ जगहों पर जमीन के नीचे सोना पाया गया है। फरवरी 2016 में खबर मिली कि वहां अब खनन करने का अधिकार वेदांता कंपनी को मिल गया है। लंबे समय तक प्रशासन ने इस बात को सिर्फ अफवाह बताया था और बिना लोगों के चर्चा के ही सोनाखान में कंपनी को ये 474 हेक्टेयर जमीन में खुदाई की इजाजत दे दी। भारत में पहली बार सोने की खान की नीलामी यहीं की गई, जिसे खूब बढ़-चढ़ कर जीत की तरह बताया गया। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार जिले के बाघमारा गांव में सोने की खदान के प्रोस्पेक्टिंग कम माइनिंग लाइसेंस वेदांता को दिए गए हैं, जिसमें केवल 2700 किलो सोना होने का अनुमान है। जिस हिस्से में खनन के लिए लाइसेंस दिया गया है, वहां उसमें से 414 हेक्टेयर तो वन्यजीव से बहुल वन क्षेत्र है।

सोनाखान इलाके में बसे लोगों का कहना है कि लंबे समय तक नीलामी और होने वाली खनन की सूचना से लोग अंजान थे। जब लाइसेंस मिलने की बात खबरों में आई, तब जाकर लोगों को इसकी जानकारी मिली। 2016 में खदान की नीलामी और होने वाली खनन की सूचना के बाद से सभी 24 प्रभावित गांवों के लोगों ने संयुक्त रूप से सरकार द्वारा खानों को लीज पर देने के कदम का विरोध किया है। कईं विरोध प्रदर्शन, 100 किलोमीटर लंबी पदयात्रा और विभिन्न धरने भी गांव वालों ने आयोजित किए हैं। राज्य सरकार के बदलने से लोगों को उम्मीद थी कि वेदांता को दी गई लीज निरस्त की जाएगी। भूपेश सरकार ने 2019 में लीज पर रोक तो लगा दी, पर क्षेत्र में कंपनी की गतिविधियां और समय-समय पर दखल समाप्त नहीं हुआ है।

सरकार की दोहरी नीति

विकास के घोड़े पर भागती हुई सरकार, जमीन के टुकड़े पर एक तरफ सेंचुरी बनाना चाहती है और क्षेत्र में ईको-टूरिज्म को बढ़ावा देना चाहती है, पर उसी जमीन के टुकड़े पर दूसरी ओर खनन कर सोना निकालना चाहती है। इस पूरी प्रक्रिया में नुकसान हो रहा है। वहां की प्राकृतिक संपदा और उसको बचाकर रखने वाले इंसानों का, जिनको इस विकास से दो-तरफा चोट आई है। इस पूरी प्रक्रिया में पीढ़ियों से बसे आए लोग विस्थापित किए जा रहे हैं। तो एक मासूम सवाल मन में आता है, आखिर विकास हो किसका रहा है? पर लड़ाई अभी लंबी और कई स्तरों की है। मामला इसलिए भी पेंचीदा है, क्योंकि विस्थापन और पुनर्वास पैकेज तक ही लड़ाई सीमित नहीं है। हक-अधिकारों के इस संघर्ष में वन अधिकार कानून का न्यायोचित कार्यान्वयन एक जरिया है जिससे लोगों की जमीन से बेदखली होनी रोकी जा सकती है। साथ ही साथ होने वाले खनन और सेंचुरी की वजह से प्रकृति और पर्यावरण में असंतुलन पर रोकथाम लगाने में भी यह कानून न केवल लोगों के लिए हितकारी साबित होगा, बल्कि जंगल और वन संपदा को भी बचाने में एक बड़ी भूमिका निभाएगा।

हाल ही में वन विभाग द्वारा जारी की गई रिपोर्ट में भी इस खनन पर आपत्ति जताई गई है, क्षेत्र में दुर्लभ वन संपदा के नष्ट होने के तर्ज पर बात करने पर पता चला कि एक ओर अधिकांश लोग अपनी जमीन से बिलकुल हटना नहीं चाहते। परंतु भूमिहीन परिवार अपने स्थिति से विवश होकर व अन्य कुछ परिवार जो पंचायत स्तर पर प्रभावशाली हैं, उनके कारण बहुत से गांवों से विस्थापित होने को लेकर सहमती भी दिखाई-सुनाई पड़ती है।

दूसरी तरफ इस जंगल क्षेत्र का एक बहुत बड़ा हिस्सा-245 वर्ग किमी क्षेत्र, 1 जुलाई 1975 में बारनवापारा वाइल्डलाइफ सेंचुरी के नाम से अधिसूचित कर दिया गया था। और वहां के जानवरों और जंगल की सुरक्षा के नाते, लोगों को क्षेत्र से विस्थापित करने के लिए आज तक भी कार्रवाई चल रही है। वन्यप्राणियों की संख्या में बढ़ोतरी का हवाला देते हुए बात यह तक उठी कि सोनाखान क्षेत्र को भी सेंचुरी का हिस्सा बनाया जाए। इससे क्षेत्र के लोगों में भय व्याप्त है। वहीं लोगों को उम्मीद है कि दलित आदिवासी मंच उन्हें परेशान नहीं होने देगा। राजिम केटवास के नेतृत्व में, लोगों द्वारा बनाया गया संगठन-दलित आदिवासी मंच, क्षेत्र के दलित-आदिवासी समुदायों के साथ समुदायों के प्राकृतिक संसाधन और जल, जंगल, जमीन के अधिकारों पर पिछले 20 सालों से संगठित होकर काम कर रहा है। संगठन ने पिछले कुछ सालों में जंगल में रह रहे समुदायों के लिए पुरजोर आवाज उठाई है, जिसमें वन विभाग द्वारा समुदायों का शोषण, उनके जीवन-यापन करने में दखल जैसे मुद्दों को उजागर किया है तो कभी महिलाओं के खिलाफ हो रही हिंसा, तस्करी पर पुलिस और न्यायालय से कानूनी मदद ली है, साथ ही साथ घरेलू श्रम मजदूरी, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी संगठन आवाज उठाता रहा है।

● **रायपुर से टीपी सिंह**

पायलट का शक्ति प्रदर्शन

राजस्थान के पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट फिर अपनी राजनीतिक जमीन को मजबूत करने में जुट गए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ अदावत और आलाकमान द्वारा किए गए वादे के बावजूद अपने समर्थकों को सरकार में स्थान नहीं मिलते देख पायलट ने अपनी ताकत दिखाने का अभियान शुरू किया है। जिलों में किसान महापंचायत कर पायलट गहलोत व पार्टी आलाकमान को अपनी ताकत का अहसास कराने में जुटे हैं। इसी के तहत दौसा में हुई महापंचायत में केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ आवाज बुलंद की, वहीं पार्टी नेतृत्व को भी इशारों ही इशारों में उनकी सुनवाई करने के लिए कहा। इस दौरान पायलट ने कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी की जमकर तारीफ की, लेकिन गहलोत का नाम तक नहीं लिया।

सचिन पायलट ने राजस्थान सरकार की योजनाओं की चर्चा तक नहीं की। उन्होंने कहा कि किसानों का भविष्य अंधकार में धकेला जा रहा है। सरकार को ये कृषि कानून वापस लेने ही होंगे। पायलट ने कहा कि कृषि कानूनों से किसान का बड़ा नुकसान होने वाला है। किसान दिल्ली की सड़कों पर ठंड में बैठे हैं, लेकिन केंद्र सरकार की बेरुखी उन्हें यातना दे रही है। उन्होंने कहा कि चंद उद्योगपतियों की वजह से केंद्र सरकार किसानों का भविष्य अंधकार में धकेल रही है। कृषि कानूनों से खेती और मंडियां दोनों चौपट हो जाएगी। किसानों को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने दिल्ली की सीमा पर जो प्रबंध किए हैं, वैसे तो भारत-पाकिस्तान की सीमा पर भी नहीं होते। इस दौरान पायलट समर्थक 8 विधायक और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आधा दर्जन पदाधिकारी भी किसान महापंचायत में पहुंचे। सभी विधायकों ने अपने संबोधन में केंद्र सरकार पर हमला तो बोला, लेकिन प्रदेश की गहलोत सरकार का नाम तक नहीं लिया।

राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री सचिन पायलट किसान महापंचायत कर लगातार शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। उनके शक्ति प्रदर्शन ने कांग्रेस आलाकमान की नींद उड़ा दी है। पूर्वी राजस्थान के तीन जिलों में वे किसान महापंचायत कर अब तक शक्ति प्रदर्शन कर चुके हैं। अब वे जोधपुर और अजमेर संभाग में किसान महापंचायत के नाम पर शक्ति प्रदर्शन की तैयारी कर रहे हैं। पायलट खेमे के वरिष्ठ विधायक विश्वेंद्र सिंह, हेमाराम चौधरी, रमेश मीणा, मुकेश भाकर व जीआर खटाना मुख्यमंत्री के गृह संभाग जोधपुर व अजमेर में किसान महापंचायत की तैयारियों में जुटे हैं। अगले एक-दो दिन में इन महापंचायतों की तारीख घोषित होगी। अब तक गुर्जर और मीणा बहुल इलाकों में शक्ति प्रदर्शन करने के बाद पायलट अब जाट बहुल बाड़मेर, अजमेर व नागौर जिलों में अपनी ताकत दिखाएंगे। इसके बाद जोधपुर जिले में उनकी महापंचयात होगी।

जानकारी के अनुसार महापंचायतों का दौर अप्रैल तक पूरा करने के बाद दलित बहुल इलाकों का दौरा करने की योजना बनाई जा रही है। इसकी कमान विधायक वेद प्रकाश सोलंकी ने संभाली है। महापंचायत के जरिए पायलट एक तरफ तो आलाकमान और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को अपनी ताकत दिखाने में जुटे हैं, वहीं यह संदेश भी देने का प्रयास कर रहे हैं कि सभी समाजों में उनकी स्वीकार्यता है। पिछले सप्ताह जयपुर जिले के कोटखावदा में हुई पायलट की किसान महापंचायत में जुटी भीड़ को देखते हुए आलाकमान भी सक्रिय हुआ है। आलाकमान चाहता है कि अब विधानसभा का बजट सत्र खत्म होने के बाद पायलट समर्थक विधायकों को मंत्री और राजनीतिक नियुक्तियों के माध्यम से सरकार में जगह दी जाए। इसके लिए प्रदेश प्रभारी व राष्ट्रीय महासचिव अजय माकन एक बार फिर सक्रिय हुए हैं। हालांकि माकन दो बार पहले भी सार्वजनिक रूप से पहले दिसंबर और फिर जनवरी में राजनीतिक नियुक्तियों का काम पूरा करने का वादा कर चुके, लेकिन मुख्यमंत्री गहलोत ने उनकी एक नहीं मानी। चार विधानसभा सीटों पर अप्रैल के पहले सप्ताह तक संभावित उपचुनाव को देखते हुए मुख्यमंत्री गहलोत फिलहाल मंत्रिमंडल विस्तार और राजनीतिक नियुक्तियां करने के मूड में नहीं है।

उधर पायलट खेमे में खुशी इस बात को लेकर है कि गहलोत खेमे के दो विधायक प्रशांत बैरवा और विरेंद्र सिंह उनके साथ आ गए। कोटखावदा की महापंचायत में इन दोनों सहित कुल 16 विधायक शामिल हुए थे। पायलट खेमे के दो विधायक पारिवारिक कारणों से महापंचायत में नहीं पहुंच सके। पिछले दिनों कांग्रेस नेता राहुल गांधी की राजस्थान यात्रा के दौरान हुई चार सभाओं में से दो में सचिन पायलट को संबोधन का मौका नहीं देने और एक में मंच से उतारे जाने से उनके समर्थक विधायक और कार्यकर्ता नाराज है। पायलट खेमा कांग्रेस आलाकमान तक इस मुद्दे पर अपनी नाराजगी पहुंचा चुका है। पायलट अब गहलोत के गृह संभाग जोधपुर का दौरा करने की तैयारी कर रहे हैं।

● **जयपुर से आर.के. बिन्नानी**

जगन मॉडल पर राजस्थान में राजनीति करेंगे सचिवन पायलट

पायलट ने आंध्र प्रदेश में जगनमोहन रेड्डी द्वारा अपनाई गई रणनीति को राजस्थान में मॉडिफाइड करके आगे काम करने का निर्णय लिया है। जगनमोहन रेड्डी मॉडल के तहत फील्ड में आम लोगों के बीच लगातार सक्रिय रहना, सही मौकों पर ताकत दिखाना और विधायकों से लेकर ब्लॉक स्तर तक अपने समर्थकों को लगातार सक्रिय रखना। जगनमोहन रेड्डी की तर्ज पर पायलट अपने समर्थकों व आम जनता के बीच लगातार सक्रिय रहेंगे। हालांकि इससे कांग्रेस नेतृत्व की चिंता जरूर बढ़ सकती है। पायलट के निकटस्थों के अनुसार फिलहाल वे अभी ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे उन पर बगावत के आरोप लगे। पायलट प्रदेश के विभिन्न इलाकों में कृषि कानून के विरोध के नाम पर महापंचायत करते रहेंगे। इनमें पायलट के साथ ही सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कटआउट व कांग्रेस के झंडे लगाए जाएंगे। महापंचायतों में भीड़ जुटाकर आलाकमान तक यह संदेश पहुंचाने की रणनीति है कि पार्टी का भविष्य प्रदेश में वे ही हैं। कार्यकर्ताओं को यह विश्वास दिलाने की कोशिश करेंगे कि वे ही अगला चेहरा हैं।

विदर्भ पर सबकी नजर

भाजपा के खिलाफ अपनी साझा ताकत बढ़ाने में जुटे महाविकास अघाड़ी (एमवीए) के तीनों घटक दल शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) और कांग्रेस भाजपा का गढ़ माने जाने वाले विदर्भ क्षेत्र में अपने-अपने विस्तार पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। शिवसेना प्रमुख और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने पिछले साल के अंत में राज्य के सक्रिय कोविड-19 केसलोड में कमी आने के बाद अपने आधिकारिक टूर और विभिन्न क्षेत्रों के दौरे शुरू करने के दौरान विदर्भ पर खास ध्यान दिया है।

दिसंबर 2020 से अब तक मुख्यमंत्री ने मुंबई से बाहर 11 यात्राएं की हैं जिसमें से पांच विदर्भ के विभिन्न जिलों की थीं। राजनीतिक विश्लेषक हेमंत देसाई ने कहा, 'महाराष्ट्र में अगले दो सालों में कई स्थानीय निकाय चुनाव होने हैं। सभी दल उसके लिए जमीनी समर्थन जुटाने में लगे हैं।' उन्होंने आगे कहा, 'उद्धव ठाकरे भी देवेंद्र फडणवीस के गढ़ जाकर और वहां विस्तार के जरिए कुछ साबित करना चाहते हैं। जहां तक एनसीपी की बात है तो विदर्भ उसके लिए हमेशा से ही एक कमजोर कड़ी रहा है।'

ठाकरे के विदर्भ क्षेत्र के पांच दौरों में से चार क्षेत्र में विकास कार्यों की समीक्षा से संबंधित थे। मुख्यमंत्री ने 5 दिसंबर को मुंबई-नागपुर एक्सप्रेसवे की प्रगति की समीक्षा के लिए अमरावती जिले का दौरा किया। 8 जनवरी को उन्होंने भंडारा जिले में घोसीखुर्द बांध परियोजना की स्थिति का जायजा लिया। 26 जनवरी को ठाकरे ने नागपुर पहुंचकर गोरेवाड़ा चिड़ियाघर का उद्घाटन किया और 5 फरवरी को बुलढाणा जिले में लोनार क्रेटर झील का दौरा करने पहुंचे मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को वहां पर्यटक सुविधाएं बढ़ाने का निर्देश दिया।

26 जनवरी की नागपुर की यात्रा के दौरान तो ठाकरे ने यहां तक कहा कि विदर्भ उनकी रगों में बसा हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा, 'मेरी दादी, बालासाहेब की मां, अमरावती के परातवाड़ा से थीं। इसलिए हमारी रगों में तो विदर्भ का खून दौड़ता है। अच्छा होगा, कोई हमें विदर्भ के लिए प्रेम के बारे में सिखाने की कोशिश न करे। हमारा तो विदर्भ के साथ खून का रिश्ता है।' उन्होंने अपने भाषण में इस क्षेत्र की लगातार यात्राओं का जिक्र करते कहा कि वे इस धारणा को दूर करना चाहते हैं कि विदर्भ को विकास से दूर रखा गया है। शिवसेना के एक पदाधिकारी ने बताया, 'हम सक्रिय तौर पर विदर्भ में अपनी जमीन मजबूत करने की कोशिश करने में जुटे हैं और हर पखवाड़े समीक्षा बैठकें कर रहे हैं। उद्धव साहब द्वारा क्षेत्र के विभिन्न जिलों का दौरा करने से इसके प्रति शिवसेना की गंभीरता को उजागर करने में मदद मिली है।'

राज्य में जब शिवसेना और भाजपा सहयोगी दल होते थे तो गठबंधन के सीट बंटवारे के फॉर्मूले में अधिकांश सीटें भाजपा के कोटे में रहती थी, जिसके कारण क्षेत्र में शिवसेना हमेशा कमजोर स्थिति में रही। सिर्फ शिवसेना ही नहीं, बल्कि एनसीपी और कांग्रेस भी इस क्षेत्र में अपना जनाधार बढ़ाने की कोशिश में लगी हैं। एनसीपी के राज्य प्रमुख जयंत पाटिल ने महाराष्ट्र में पार्टी का जनाधार मजबूत करने के उद्देश्य से 28 जनवरी को विदर्भ के गढ़चिरौली जिले से 'राष्ट्रवादी परिवार संवाद यात्रा' निकाली। अभियान के पहले चरण में विदर्भ के सभी 11 और उत्तर महाराष्ट्र के तीन जिले कवर किए गए। इस बीच, कांग्रेस ने पार्टी के नए राज्य प्रमुख के रूप में विदर्भ का चेहरा माने जाने वाले नाना पटोले को चुना है, जो मुख्य रूप से क्षेत्र में भाजपा के हाथों गंवाई राजनीतिक जमीन को फिर से हासिल करने की कोशिश का एक हिस्सा है। नाम न देने के इच्छुक एनसीपी नेता ने कहा, 'विदर्भ में हमारी मौजूदगी ना के बराबर है क्योंकि हमने यहां हमेशा कांग्रेस के साथ गठबंधन में चुनाव लड़े हैं। अब हम विदर्भ में हर जगह बूथ-स्तर पर समितियां बनाने पर ध्यान दे रहे हैं और निकाय चुनाव लड़ने की योजना भी बना रहे हैं।'

कांग्रेस के लिए महाराष्ट्र के पार्टी प्रमुख के तौर पर पटोले को चुनना, राज्य के किसी ओबीसी चेहरे को शीर्ष नेतृत्व में लाने के साथ ही विदर्भ में खोई राजनीतिक जमीन हासिल करने की इच्छा का एक स्पष्ट संकेत है। कांग्रेस आलाकमान द्वारा इस माह के शुरू में पटोले को महाराष्ट्र का नया अध्यक्ष बनाए जाने के दौरान राजनीतिक विश्लेषक अभय देशपांडे कहते हैं, 'विदर्भ कांग्रेस का एक पारंपरिक गढ़ था। यह महाराष्ट्र का एकमात्र ऐसा क्षेत्र है, जहां आपातकाल के बाद भी कांग्रेस मजबूती से उभरती रही थी, लेकिन अंततः उन्होंने वह जनाधार गंवा दिया। पटोले को पार्टी अध्यक्ष चुनना इस क्षेत्र में खोई जमीन हासिल करने का एक तरीका है।' इस बीच, देसाई का कहना है, 'विदर्भ में कांग्रेस की अच्छी-खासी मौजूदगी है और वह भाजपा को दरकिनार करके अपना गढ़ फिर से हासिल करना चाहती है। शिवसेना के पास भी एक अच्छा मौका है क्योंकि विदर्भ के मतदाताओं के लिए अलग राज्य का मुद्दा, जिसका वह हमेशा विरोध करती रही है, अब उतनी ज्यादा अहमियत नहीं रखता है।'

● **बिन्दु माथुर**

विदर्भ का सियासी समीकरण

विदर्भ में कुल 62 विधानसभा क्षेत्र हैं जो कि महाराष्ट्र की कुल विधानसभा सीटों का लगभग 22 प्रतिशत है। अगले साल महाराष्ट्र में 10 प्रमुख नगर निगम चुनाव होने हैं। इनमें से तीन नागपुर, अकोला और अमरावती विदर्भ के हैं। महाराष्ट्र के भाजपा के कुछ शीर्ष नेता, जैसे नितिन गडकरी, देवेंद्र फडणवीस और सुधीर मुनगंटीवार विदर्भ क्षेत्र से ही आते हैं। 2014 के लोकसभा चुनावों में भाजपा ने 44 सीटों पर जीत हासिल करने के साथ इस क्षेत्र में अपनी मुख्य प्रतिद्वंद्वी कांग्रेस को धराशायी कर दिया था। हालांकि, बाद में विदर्भ में पार्टी की पकड़ ढीली पड़ने लगी। 2019 के विधानसभा चुनावों में भाजपा ने इस क्षेत्र में 29 सीटें जीतीं, जबकि कांग्रेस ने 2014 में 10 की तुलना में अपनी टैली बढ़ाते हुए 15 सीटें जीतीं। एनसीपी ने भी यहां अपना प्रदर्शन सुधारा है। 2014 में एक के मुकाबले उसने 6 सीटें जीतीं, जबकि शिवसेना ने 2014 की तरह ही 4 सीटों पर सफलता हासिल की।

बढ़ी चुनावी सरगर्मी

भले ही उप्र विधानसभा 2022 के चुनाव में एक साल के करीब का समय बचा हो, लेकिन सियासी गुणा-भाग के साथ-साथ सभी पार्टियों की चुनावी सरगर्मी भी दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही है। लेकिन इस बार उप्र विधानसभा चुनाव को लेकर नित नए समीकरण उभरते जा रहे हैं। वजह साफ है कि इस बार आम आदमी पार्टी (आप) प्रदेश की सभी 403 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवील ने कुछ समय पहले जैसे ही यह ऐलान किया कि आगामी विधानसभा चुनाव में आप दिल्ली की तर्ज पर उप्र की सभी 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी, वैसे ही उप्र में राजनीतिक ताना-बाना बुनना शुरू हो गया। आप के नेताओं का कहना कि जिस प्रकार दिल्ली में मोहल्ला क्लीनिक, बसों में महिलाओं को मुफ्त की यात्रा, पानी मुफ्त और 200 यूनिट बिजली मुफ्त दी जा रही है, उसी तरह पार्टी की सरकार बनने पर उप्र के लोगों को ये सारी सुविधाएं मुहैया कराएगी। आप उप्र में ग्राम पंचायत चुनावों के रास्ते विधानसभा का रास्ता तय करने की जुगत में है।

मौजूदा दौर में देश की सियासत में एक अजीब-सा वातावरण करवटें ले रहा है। लोगों के सियासत को लेकर तमाम सवाल हैं कि किस राजनीतिक दल पर विश्वास करें? कौन-सी पार्टी है, जो विकास के साथ-साथ लोगों को बेहतर सुविधाएं दे सके। बता दें कि उप्र के विधानसभा चुनाव के पहले अप्रैल-मई, 2021 में ग्राम पंचायत के चुनाव होने हैं। माना जा रहा है कि आप ग्राम पंचायत चुनावों के रास्ते जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं और **संगठन को मजबूत** कर प्रदेश में अपनी जड़े जमाएगी। आप के नेता दिनेश सिंह का कहना है कि उप्र की जनता प्रदेश में बदलाव चाहती है। क्योंकि अभी तक भाजपा, सपा, कांग्रेस और बसपा की सरकारों को यहां की जनता देख चुकी है। इन पार्टियों ने सत्ता पाने के बाद लोगों को निराश ही किया है। लेकिन अब उप्र की जनता एक उम्मीद और भरोसे के साथ आप को मौका देना चाहती है, ताकि प्रदेश में विकास के साथ-साथ एक ईमानदार राजनीतिक दल की सरकार बने।

आम आदमी पार्टी, उप्र के अध्यक्ष सभाजीत सिंह ने कहते हैं कि यहां के लोगों में एक उत्साह है कि आप ग्राम पंचायत से लेकर विधानसभा चुनावों में अपने प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारेगी। उनका कहना है कि दिल्ली में 8-9 साल की आप ने तीन बार अरविंद केजरीवाल को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाकर यह बता दिया है कि अरविंद केजरीवाल की कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। उप्र के लोग बड़ी संख्या में दिल्ली में रहते हैं और दिल्ली में हो रहे विकास कार्यों के प्रत्यक्षदर्शी हैं। इसलिए प्रदेशवासी चाहते हैं कि जो सुविधाएं दिल्ली वालों को मिल रही हैं, वो सुविधाएं उन्हें भी मिलें। प्रदेश की जनता चाहती है कि राज्य बड़ा है तो, यहां विकास भी अधिक होना चाहिए, क्योंकि सरकारी खाते में राजस्व अधिक जमा होता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के लोग यह बात समझ और मान रहे हैं कि आप के मार्फत ही विकास संभव है। सभाजीत ने बताया कि आप के कार्यकर्ता प्रदेश के गांव-गांव में जाकर लोगों के बीच आप के बारे बता रहे हैं और प्रतिदिन हजारों की संख्या में सदस्य बना रहे हैं। जिला इकाई के माध्यम से लोगों को जिम्मेदारी भी दी जा रही है। उनका कहना है कि उप्र में आप ग्राम प्रधान से लेकर जिला परिषद और विधानसभा तक के चुनाव लड़ेगी।

राजनीति विश्लेषक सचिन सिंह गौर का कहना है कि यह बात तो साफ देखी जा रही है कि लोग बदलाव के मूड में हैं, लेकिन मतदाता कितना बदलाव लाते हैं? ये तो तभी पता चलेगा, जब चुनाव हो जाएंगे और मतों की गिनती पूरी होगी। क्योंकि उप्र की सियासत पूरी तरह से जातीय समीकरण पर टिकी हुई है। सवाल यह है कि क्या आप भी जातीय जोड़-तोड़ पर सियासत करेगी? अगर वह ऐसा करती है, तो अन्य राजनीतिक दलों से कैसे अपने को हटकर बता पाएगी कि उसकी सियासत अलग है। सचिन कहते हैं कि यह बात तो है कि आप ने दिल्ली में शिक्षा और **स्वास्थ्य पर विशेष काम** किया है, जिसको लोग मानते भी हैं। लेकिन लोगों का यह भी मामना है कि दिल्ली की सत्ता 70 विधानसभा सीटों वाली है, जबकि उप्र की सत्ता 403 विधानसभा वाली। ऐसे में दोनों की तुलना कैसे की जा सकती है? दिल्ली के भौगौलिक ढांचे और उप्र के भौगोलिक ढांचे में जमीन-आसमान का अंतर है। उप्र की सियासत पर पैनी नजर रखने वाले वरिष्ठ पत्रकार हरिश्चंद्र पाठक का कहना है कि जन आंदोलन से निकली आप ने दिल्ली की सियासत में दूसरी बार सारे समीकरणों को धता बताकर यह साबित कर दिया है कि लोगों के बीच आप की पकड़ ही मजबूत नहीं है, बल्कि उसका काम भी बोलता है। अगर उप्र की जनता के बीच भी आप दिल्ली के लोगों में अपनी पकड़ बनाने में सफल होती है, तो उप्र में बहुत बड़ा सियासी उलटफेर संभव है।

● **लखनऊ से मधु आलोक निगम**

आप ने रोचक बनाया माहौल

आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का कहना है कि उनके पास उप्र से तमाम नेता और राजनीतिक संगठनों से जुड़े लोग आ रहे हैं और कह रहे हैं कि आप उप्र में चुनाव लड़े। वहां की जनता को यह विश्वास भी है कि आप बड़ा बदलाव कर सकती है। केजरीवाल का कहना है कि जो राजनीतिक दल उप्र को अपनी जागीर समझते हैं, उनसे वहां की जनता त्रस्त है। आप से जुड़कर लोग उसे मजबूत बना रहे हैं। वहीं आम आदमी पार्टी के विधायक दिलीप पांडे का कहना है कि उप्र में भले ही अभी आप का कोई विधायक नहीं है, लेकिन यहां आप प्रमुख विपक्षी पार्टी के तौर पर अपनी भूमिका निभा रही है और समय-समय पर उप्र सरकार की जनविरोधी नीतियों के विरोध में आवाज उठाकर लोगों को जागरूक कर रही है। उनका कहना है कि पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह देश के साथ-साथ उप्र में कोरोनाकाल में हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ और किसानों के समर्थन में संसद से लेकर सड़कों तक न्यायसंगत बात रख रहे हैं। दिलीप पांडे का कहना है कि उप्र में एक विशेष जाति के 6 फीसदी लोग अपनी सरकार समझकर 94 फीसदी लोगों की उपेक्षा कर रहे हैं, जिसको आप बर्दाश्त नहीं करेगी। उनका कहना है कि प्रदेश में 30 से ज्यादा जिलों में आप के सक्रिय जिला कार्यालय खुल गए हैं, बाकी अन्य जिलों में भी कार्यालय जल्द ही खुलेंगे।

दो पाटन के बीच भाजपा

बिहार में जनता दल-यूनाइटेड और लोक जनशक्ति पार्टी के बीच घमासान दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। यह घमासान अब और बढ़ गया है, क्योंकि विगत दिनों लोजपा से पहले ही बागी हो चुके प्रदेश महासचिव केशव सिंह के नेतृत्व में लोजपा के पांच महासचिव, दो प्रकोष्ठ अध्यक्ष, कई जिलाध्यक्ष समेत कुल 208 नेताओं ने जदयू का दामन थाम लिया। बिहार विधानसभा चुनाव में जिस लोजपा ने जदयू को कई सीटों पर हार तय करने में अपनी भूमिका निभाई, उसे जदयू ने अब करारा झटका दिया है। उधर, इन दोनों दलों की लड़ाई ने भाजपा को दुविधा में डाल दिया है। उसे समझ में नहीं आ रहा है कि वह दोनों के साथ किस तरह सामंजस्य बनाए रखे।

गौरतलब है कि जबसे एनडीए ने पिछले साल बिहार चुनाव जीता है, उसके दो सहयोगी दलों जनता दल-यूनाइटेड और लोक जनशक्ति पार्टी के बीच घमासान मचा हुआ है। राज्य में भाजपा के साथ सरकार चला रही जदयू अब तक इस बात से उबर नहीं पाई है कि लोजपा के अपने दम पर चुनाव लड़ने के फैसले से उसके 25 से 30 उम्मीदवारों की हार तय हो गई। पार्टी का कहना है कि लोजपा उसी दिन एनडीए का हिस्सा नहीं रही, जब उसने एनडीए गठबंधन के खिलाफ अपने उम्मीदवार उतारे। हालांकि, भाजपा की ओर से अभी तक यह नहीं कहा गया है कि चिराग पासवान की पार्टी गठबंधन का हिस्सा नहीं है। चुनावों के दौरान यह चर्चा आम थी कि चिराग ने बिहार में नीतीश को कमजोर करने के लिए भाजपा के साथ परदे के पीछे एक समझौता किया था। हालांकि भाजपा ने इस आरोप का खंडन किया था।

उधर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं कि भाजपा को यह तय करना है कि एनडीए में लोजपा की क्या भूमिका होगी। उन्होंने हाल में दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के बाद पटना वापसी पर कहा, हम ऐसे मुद्दों पर विशेष ध्यान नहीं देते हैं। विधानसभा चुनाव में लोजपा ने क्या किया, यह हर कोई जानता है। नीतीश ने भले ही भाजपा के पाले में गेंद डाल दी हो, लेकिन उनकी पार्टी लोजपा की एनडीए में मौजूदगी पर नाराजगी जाहिर कर चुकी है। बजट सत्र की पूर्व संध्या पर एनडीए की बैठक से पहले जदयू ने लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान को निमंत्रण देने पर कड़ी आपत्ति जाहिर की, जिसके बाद कथित रूप से भाजपा को निमंत्रण वापस लेने पर मजबूर होना पड़ा। हालांकि लोजपा ने कहा कि चिराग खराब स्वास्थ्य के कारण उस वर्चुअल मीटिंग में शामिल नहीं हो सके। लेकिन, जदयू के प्रमुख महासचिव केसी त्यागी ने उस पार्टी को **निमंत्रण भेजने** पर सवाल उठाया, जो बिहार में एनडीए के खिलाफ चुनाव लड़ी थी।

लोजपा का कहना है कि वह एनडीए का हिस्सा बनी हुई है और उसका अतीत में भी जदयू के साथ कोई गठबंधन नहीं रहा है। पार्टी के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष राजू तिवारी का कहना है कि नीतीश के अधिक सीटों से चुनाव लड़ने की जिद के कारण बिहार में एनडीए का प्रदर्शन बुरा हुआ। वे कहते हैं, नीतीश राज्य में बड़े भाई के रूप में शासन करना चाहते थे। तिवारी का आरोप है कि नीतीश जदयू के लिए 122 सीटें चाहते थे और लोजपा को 15 से अधिक सीटें देने को तैयार नहीं थे। वे कहते हैं, हमें नीतीश के लालच और अहंकार के कारण अकेले ही चुनाव लड़ना पड़ा। उन्होंने दावा किया कि लोजपा एनडीए से बाहर हो जाती, तो भाजपा की जीती हुई सीटों की संख्या कम हो जाती, जो उनकी पार्टी नहीं चाहती थी। इस बीच, भाजपा को उम्मीद है कि उसके दोनों सहयोगी दलों के बीच तनाव समय के साथ कम हो जाएगा, लेकिन फिलहाल इसके कोई संकेत नहीं दिख रहे हैं। दोनों की लड़ाई तल्ख होती जा रही है। बिगड़ती कानून-व्यवस्था को लेकर नीतीश सरकार पर निशाना साधने के अलावा, चिराग ने मुख्यमंत्री पर अपने जमुई (आरक्षित) संसदीय क्षेत्र में एक मेडिकल कॉलेज के निर्माण में अड़चनें पैदा करने का आरोप लगाया है।

चिराग कहते हैं कि मुख्यमंत्री ने राजनीतिक दुर्भावना के चलते जमुई मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के निर्माण के लिए जारी दो बार निविदाओं को रद्द करवाया है। उन्होंने नीतीश को पत्र लिखा, 'केंद्र ने मेरे प्रयासों से जमुई जिले के खैरा ब्लॉक के अंतर्गत बेला में एक मेडिकल कॉलेज और अस्पताल को मंजूरी दे दी थी, लेकिन बिहार मेडिकल सर्विसेज एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने दो बार इसकी निविदा रद्द कर दी।' लोजपा अध्यक्ष का दावा है कि अन्य नए मेडिकल कॉलेजों का निर्माण शुरू हो चुका है, जो जमुई से साथ स्वीकृत हुए थे। 'मैं यह नहीं समझ पा रहा हूं कि प्रक्रिया पूरी होने के बावजूद जमुई के लिए निविदाएं क्यों रद्द की जा रही हैं?'

● **विनोद बक्सरी**

कन्हैया कुमार को लेकर भी बिहार में सियासी तपिश

बिहार में मौसम में गर्माहट के साथ ही नेताओं की हो रही 'मुलाकातों' के बाद कयासों का दौर शुरू है, वहीं सियासत में भी गर्माहट देखी जा रही है। बिहार में जेएनयू के छात्र संघ के नेता कन्हैया कुमार ने जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष और भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी से मुलाकात की, तो अचानक राजनीति भी गर्म हो गई। इसके कई अर्थ निकाले जाने लगे। दोनों नेताओं ने मित्रों के साथ तस्वीरें भी खिंचवाई और सोफे पर बैठकर लंबी गुफ्तगू भी की। इन दिनों जेडीयू लगातार अपने कुनबे को बढ़ाने में लगी है। यही कारण है कि बसपा के एकमात्र विधायक जमां खान जेडीयू में आकर मंत्री पद पा चुके हैं और निर्दलीय सुमित सिंह भी जेडीयू को समर्थन देकर मंत्री की कुर्सी संभाल रखी है। गौरतलब है कि कन्हैया वामपंथी दल के बड़े चेहरे हैं और पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव में वामपंथी दल ने आरजेडी के साथ मिलकर चुनाव लड़कर अच्छी सफलता भी पाई है। ऐसे में भले ही इस मुलाकात को औपचारिक बताया जा रहा है, लेकिन इसको लेकर कयासों का दौर जारी है। कन्हैया कुमार की यह मुलाकात इस कारण खास हो गई है कि हाल ही में उनके खिलाफ पार्टी ने निंदा प्रस्ताव पारित किया है। कहा जा रहा है कि पार्टी के कई नेता भी उनके खिलाफ हैं।

फिर दगा दे सकता है चीन

एशिया के देशों की नाक में दम किए हुए है चीन

आज के चीन के असली अमृतकलश तिब्बत, शिनजियांग और दक्षिणी मंगोलिया जैसे उपनिवेश हैं। इनके अथाह स्रोतों को लूटकर वह अपना आर्थिक साम्राज्य खड़ा किए हुए है और भारत, नेपाल, भूटान और मध्य एशिया के देशों की नाक में दम किए हुए है। चीन का इलाज गलवन, पैंगोंग और देपसांग में एक या दो किलोमीटर हिस्से के लिए वार्तालाप की मेज पर आने से नहीं होगा। इसके बजाय भारत के लिए सही रणनीति यह होगी कि वह तिब्बत और शिनजियांग पर चीन के औपनिवेशिक कब्जे को चुनौती देते हुए उसे बताए कि तिब्बत की जिस जमीन पर खड़ा होकर वह लद्दाख और अरुणाचल के भूभाग पर दावे करता आ रहा है और सैनिक धमकियां दे रहा है, वहां उसकी खुद की उपस्थिति गैरकानूनी है। अगर मोदी सरकार चीन को इस सच का आईना दिखाने का साहस करती है तो तिब्बत की आजादी के इच्छुक अमेरिका, यूरोप और जापान इस अभियान में कूदने को तैयार हैं।

महीने तक लद्दाख के पैंगोंग झील इलाके में भारी जमावड़े के बाद भारतीय और चीनी सेनाओं द्वारा अपने-अपने सैनिकों को पीछे हटाने से दोनों देशों के बीच सैनिक तनाव कुछ कम तो जरूर हुआ है, लेकिन भारत में अभी भी चीन की नीयत के प्रति संदेह कम नहीं हो रहा है। संसद में रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने बताया कि लंबी आनाकानी के बाद चीन पीछे हटने को इस कारण राजी हुआ कि उसे समझ आ गया कि भारत चीनी दादागीरी के आगे झुक जाने की नीति छोड़ चुका है और अब वह अपनी एक इंच जमीन भी नहीं छोड़ेगा। रक्षामंत्री ने खास तौर से कैलास पर्वत श्रृंखला की दुर्गम चोटियों पर भारतीय सेना ने मोर्चा संभालने का जिक्र किया, जिसके कारण पूरे इलाके पर उसका दबदबा बन गया था और चीनी सेना के लिए हालात चिंताजनक हो गए थे, लेकिन रक्षा विषेशज्ञों को चिंता है कि अगर चीन किसी दिन मुकर गया तो उसके लिए फौज और टैंकों को फिर से फिंगर-4 तक लाना बहुत मुश्किल नहीं होगा। क्या इस स्थिति में भारतीय सेना उतने आराम से फिर से कैलाश की चोटियों पर मोर्चे बना सकेगी?

रक्षा विषेशज्ञों को इस पर शंका है कि चीन अधिक समय तक आक्रामक रवैया छोड़कर शांत बैठा रहेगा। वे गलवन घाटी में चीनी सैनिकों की उस हरकत की याद दिला रहे हैं, जब चीनी सैनिकों ने अचानक भारतीय सैनिकों पर हमला कर दिया था। चीन का इतिहास बताता है कि वह कोई भी समझौता अपनी सुविधा और मजबूरी के तहत ही करता है। परिस्थितियां बदलने पर या हालात अपने अनुकूल होने पर पिछले वादों और सहमतियों को ताक पर रखकर नया आक्रामक रवैया अपना लेना उसके व्यवहार का हिस्सा बन चुका है। इसलिए पैंगोंग झील के इलाके में मौजूदा शांति का अर्थ यह कतई नहीं लिया जा सकता कि इस इलाके में चीन और भारत का विवाद हल हो गया है और भविष्य में चीनी सेना वहां पर फिर से घुसने का प्रयास नहीं करेगी। पिछले कई दशकों में यह पहला अवसर है जब किसी इलाके में घुस आने और अपनी चौकियां बना लेने के बाद चीन अपनी सेना को वापस बुलाने पर राजी हुआ।

पैंगोंग झील इलाके में चीन के पीछे हटने के कई आयाम हैं, जिन पर ध्यान दिया जाना बहुत जरूरी है। पहली बात यह कि लद्दाख के गलवन, हॉट स्प्रिंग-गोगरा और देपसांग में विवाद अभी ज्यों का त्यों है। ये सभी इलाके हिमालय के बहुत ऊंचे हिस्से में हैं, जहां सर्दियां अत्यधिक कठिन होती हैं। चीनी सेना के लिए यह पहला मौका है, जब किसी टकराव वाली हालत में उसे इतने ठंडे इलाके में तैनात किया गया, जबकि भारतीय सेना को गलवन के निकट सियाचिन में पाकिस्तान से लोहा लेने का बहुत लंबा अनुभव है। चीनी सेना के पैंगोंग से पीछे हटने का एक कारण यह भी है कि वह सर्दियों में हथियारबंद टकराव को टालना चाहता था। इसलिए सर्दियां खत्म होने के बाद चीन की नीयत फिर से नहीं बदलेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है।

दूसरे, चीनी सेना के लिए इस इलाके में सबसे बड़ी चुनौती यह है कि भारत ने दरबुक से श्योक नदी और अक्साई चिन से एकदम सटी हुई अपनी हवाई पट्टी दौलत बेग ओल्डी तक सड़क बना ली है, जो गलवन से होकर गुजरती है। इस सड़क ने भारतीय सेना को सियाचिन तक के इलाके पर अपनी पकड़ मजबूत करने की सुविधा दे दी है। इसके कारण चीन के कराकोरम राजमार्ग पर खतरा बहुत बढ़ गया है। तीसरा कारण यह है कि गलवन में हमले का फैसला बीजिंग के निर्देश पर हुआ। बीजिंग के लिए परेशानी की एक बड़ी बात यह थी कि मोदी सरकार ने अपने सैन्य नेतृत्व को चीनी सेना की किसी भी हरकत से निपटने के लिए खुद फैसला करने और मौके पर तुरंत कार्रवाई करने की छूट दे दी थी। इससे पहले नई दिल्ली ने सेना के हाथ बांधे हुए थे और जवाबी कार्रवाई के लिए किसी सैन्य फैसले पर अमल करने से पहले सैन्य नेतृत्व को रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और प्रधानमंत्री कार्यालय की अफसरशाही की फाइलों के लंबे गलियारों में इतना ज्यादा समय नष्ट करना पड़ता था कि तब तक चीनी सेना कब्जा करने के बाद पक्के मोर्चे भी बना चुकी होती थी।

लद्दाख में चीन ने जो कार्रवाई की, उसके पीछे चीनी राष्ट्रपति शी चिनपिंग का यह इरादा था कि सीमित लड़ाई में लद्दाख का मोर्चा फतह कर वह कम्युनिस्ट पार्टी के शताब्दी सम्मेलन में हीरो बनकर उभरेंगे, लेकिन भारतीय सेना ने चीनी सेना को जैसी चुनौती दी, उसके बाद उन्हें डर सताने लगा कि लंबे समय तक सीमा पर भारत के साथ उलझे रहने से उनकी छवि एक कमजोर नेता की बनेगी और आजीवन पद पर बने रहने के बजाय 'लेने के देने' भी पड़ सकते हैं। चूंकि यह आशंका है कि चीन सीमा पर फिर से कोई हरकत कर सकता है इसलिए भारत को उससे निपटने के लिए एक नई रणनीति अपनाने की जरूरत है। मोदी सरकार को यह समझना जरूरी है कि चीन के इरादों से आत्मरक्षा पर टिकी पुरानी नीति से नहीं निपटा जा सकता। आर्थिक और सैनिक शक्ति बढ़ने के साथ चीन का दंभ बढ़ता जा रहा है। चीन रावण सरीखा बन चुका है। उसके सिरों को उगने से तब तक नहीं रोका जा सकता, जब तक उसकी नाभि के अमृतकुंड को नहीं सुखा दिया जाए।

● **ऋतेन्द्र माथुर**

स्त्री की आत्मनिर्भरता

आत्मनिर्भरता शब्द अपने आप में कई तथ्य समेटे हुए है। आत्मनिर्भरता का सामान्य अर्थ है, 'स्वयं पर निर्भर होना।' जो लोग अपनी सामान्य जरूरतों को अपने प्रयासों से पूरा करने में सक्षम हैं वे आत्मनिर्भर की श्रेणी में आते हैं। कहा जा सकता है कि अबोध बालकों, वृद्ध और कुछ खास व्याधियों तथा आलस्य से ग्रस्त लोगों के अलावा सामान्यतया सभी लोग, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष, आत्मनिर्भर हैं। साथ ही यह भी ध्यान देने की जरूरत है कि कोई देश या समाज पूर्ण या सीमित स्तरों पर आत्मनिर्भर तो हो सकता है, पर कोई भी व्यक्ति पूर्ण आत्मनिर्भर नहीं हो सकता। वह कुछ मामलों में स्वयं पर निर्भर, तो कुछ के लिए दूसरे पर आश्रित रहता ही है। अर्थात् आत्मनिर्भरता और पराश्रितता दोनों शब्द साथ-साथ चलते हैं।

हमारे समाज का केंद्र बिंदु परिवार है। इसी के इर्द-गिर्द लगभग शेष सारी संरचनाएं काम करती हैं। परिवार माता-पिता, भाई-बहन, दादा-दादी और कुछ अन्य नाते-रिश्तेदारों के योग से बनता है। आज के एकल परिवार के दौर में इसका आकार कुछ छोटा भी हुआ है। पर दोनों ही स्वरूपों में परिवार की धुरी में दो लोग होते हैं- एक सदस्य के ऊपर गृहस्थी के संचालन की जिम्मेदारी होती है, तो दूसरा उस कार्य के लिए धनोपार्जन करता है। सामान्यतया आर्थिक उपार्जन के लिए पुरुष गतिविधियां करता है और स्त्री गृहस्थी का संचालन करती है। संभव है कुछ स्थितियां इसके विपरीत भी हों। इसलिए स्वाभाविक रूप से कहा जा सकता है कि दोनों की जिम्मेदारी समान रूप से अपने-अपने स्थान पर महत्वपूर्ण है। एक की भी अनुपस्थिति परिवार रूपी गाड़ी को डामाडोल कर सकती है। यह भी कहा जा सकता है कि इस इकाई की दोनों ही धुरियां अपने आप में आत्मनिर्भर भी हैं और एक-दूसरे पर आश्रित भी।

प्रचलित अर्थ में इसका एक ही अर्थ होता है और वह है, 'आर्थिक आत्मनिर्भरता।' जैसे ही हम आत्मनिर्भर कहते हैं, तो वह आर्थिक आत्मनिर्भता का ही बोध कराता है। जबकि यह आत्मनिर्भता के कई उपादानों में से एक है। जैसे कोई शैक्षणिक रूप से, शारीरिक क्षमता से, गृहकार्य में, किसी कला या व्यवसाय आदि में से किसी एक में या कई विषयों में एक साथ आत्मनिर्भर और पारंगत हो सकता है, वैसे ही कोई धन की कमाई में भी पारंगत और आत्मनिर्भर हो सकता है। उपरोक्त प्रचलित अर्थों के अनुसार ही स्त्री की आत्मनिर्भरता को भी मूलत: आर्थिक आत्मनिर्भरता से जोड़ दिया गया। इस सोच ने न सिर्फ औरत के कामों का अवमूल्यन किया, बल्कि उसके अस्तित्व को ही दोयम बना दिया। दिन के सोलह-सोलह घंटे घरेलू कामों में लगी औरत भी घरेलू और सामाजिक रूप से आश्रित और अक्रियाशील मानी जाने लगी।

फलस्वरूप उसके कर्तव्यों की फेरहिस्त लंबी होती गई और अधिकार कम होते गए। घर को स्वरूप देने वाली औरत के मालिकाना हक में वह घर भी न रहा। सामाजिक विसंगतियों के जाल में पिता की संपत्ति से 'वास्तविक रूप' से बेदखल (कानूनी हक के बावजूद) स्त्री, ससुराल में भी दूजे घर से आई मेहमान की हैसियत से ही दो चार होती रही। और उधार में मिले उपनामों को बदलती कभी पिता और कभी पति की कृपापात्र बनी अपने वजूद की तलाश में गुम होती रही। बदलते वक्त ने जब उसे समझाया कि सम्मान और पहचान का रास्ता 'अर्थ' से होकर गुजरता है, तो वह चाहे, अनचाहे खुद को साबित करने के लिए उसी बदले आत्मनिर्भरता के दौर में शामिल होती गई।

ध्यान देने की बात है कि तमाम जद्दोजहद के बाद भी देश की मात्र 27 फीसदी महिला आबादी कामकाजी है। इसमें भी ग्रामीण क्षेत्र की ज्यादातर महिलाएं कृषि और असंगठित क्षेत्र के कार्यों में लगी हैं। अब प्रश्न है, कि क्या शेष महिलाओं को पराश्रित और अक्षम मान लिया जाना चाहिए? यह भी कि जिन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए 'अपने आप में सक्षम स्त्री' आर्थिक रूप से सक्षम होने की दिशा में बढ़ी, क्या उसे उन राहों की बदौलत मुक्ति और विकास की राहें हासिल हो पाईं? क्या उसकी आर्थिक सक्षमता ने एक पूर्ण समतामूलक समाज का निर्माण किया है? स्त्री को दोयम बनाती जड़ परंपराओं और मान्यताओं का छीजना क्या इसके माध्यम से हुआ?

● **ज्योत्सना अनूप यादव**

आत्मनिर्भरता का दंश जीवनभर झेलती औरतें

अथक कामों के बोझ से लदी ये औरतें अपनी कथित आत्मनिर्भरता का दंश जीवनभर झेलती हैं। यह सत्य है कि उनकी कमाई से घर में पैसे और भौतिक संसाधनों की बढ़ोतरी होती है, पर उसके बदले में उन्हें क्या हासिल होता है, यह प्रश्न भी विचारणीय है। सवाल घरेलू जीवन जीती उन अधिसंख्य स्त्रियों को लेकर भी है, जो बगैर कोई अपराध किए आत्मनिर्भरता के इस एकपक्षीय सोच की अपमानजनक मार झेल रही हैं। इन प्रश्नों के जवाब में आर्थिक रूप से सक्षम महिलाओं के जीवन में आए विकासात्मक बदलाव की बात की जा सकती है। इसने सदियों से शोषित और रीढ़-विहीन परंपराओं का मारक प्रहार झेलती औरतों की दशा और दिशा की बेहतरी में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह भी सही है कि आर्थिक सक्षमता की जिजीविषा ने आधी आबादी के विकास के कई रास्ते खोले हैं और वह सारे दुरूह मान्य-अमान्य सीमाओं को लांघती अपने लक्ष्य को भेद अपना मुकाम बना रही है। इन तमाम बातों के बावजूद यह प्रश्न अब भी पूर्ववत है। क्योंकि ये सफलताएं उन्होंने ही हासिल की, जिन्होंने इसका स्वप्न देखा और कोशिशें की। पर उनकी सफलता का दंड उन्हें हरगिज नहीं मिलना चाहिए, जिन्होंने सामान्य घरेलू जीवन का स्वप्न देखा और अपनाया। उनके चुनाव और पसंद को न कमजोरी और न अपमान का प्रयाय मानना चाहिए। हर इंसान को अपनी इच्छानुसार कार्य करने और जिंदगी जीने का मौका मिलना ही उसके स्वतंत्र होने का परिचायक है।

रामायण से ज्यादा प्रचलित है रामचरितमानस

मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम को समर्पित दो ग्रंथ हैं पहली तुलसीदास की 'श्रीरामचरितमानस' और वाल्मीकि की 'रामायण।' दोनों को ही सटीक ओर प्रमाणिक माना जाता है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि दोनों ही ग्रंथों यानी कि श्रीरामचरितमानस और रामायण में कुछ बातें हैं जो अलग हैं। वहीं कुछ बातें ऐसी हैं जिनका वर्णन केवल वाल्मीकि कृत रामायण में ही मिलता है।

वर्तमान में वाल्मीकि कृत रामायण को पढ़ना और समझना कठिन है क्योंकि उसकी भाषा संस्कृत है जबकि रामचरितमानस को वर्तमान की आम बोलचाल की भाषा में लिखा गया है। जनमानस की इस भाषा के कारण ही रामचरितमानस का पाठ हर जगह प्रचलित है। वाल्मीकि कृत रामायण में राम को एक साधारण लेकिन उत्तम पुरुष के रूप में चित्रित किया है, जबकि रामचरितमानस में पात्रों और घटनाओं का अलंकारिक चित्रण किया गया है। इस चरित्र चित्रण में तुलसीदास ने हिंदी भाषा के अनुप्रास अलंकार, श्रृंगार, शांत और वीररस का प्रयोग मिलेगा। इसमें तुलसीदासजी ने भगवान राम के हर रूप का चित्रण किया गया है। रामचरितमानस में राम ही नहीं रामायण के हर पात्र को महत्व दिया गया है। सभी के चरित्र का खुलासा हुआ है। तुलसीदासजी ने राम के चरित को एक महानायक और **महाशक्ति** के रूप में चित्रित किया।

वाल्मीकि की रामायण के अनुसार जिस समय भगवान श्रीराम वनवास गए, उस समय उनकी आयु लगभग 27 वर्ष की थी। राजा दशरथ श्रीराम को वनवास नहीं भेजना चाहते थे, लेकिन वे वचनबद्ध थे। जब श्रीराम को रोकने का कोई उपाय नहीं सूझा तो उन्होंने श्रीराम से यह भी कह दिया कि तुम मुझे बंदी बनाकर स्वयं राजा बन जाओ। वहीं भरत को अपने पिता राजा दशरथ की मृत्यु का आभास पहले ही एक स्वप्न के माध्यम से हो गया था। उन्होंने सपने में राजा दशरथ को काले वस्त्र पहने हुए देखा था। उनके ऊपर पीले रंग की स्त्रियां प्रहार कर रही थीं। सपने में राजा दशरथ लाल रंग के फूलों की माला पहने और लाल चंदन लगाए गधे जुते हुए रथ पर बैठकर तेजी से दक्षिण (यम की दिशा) की ओर जा रहे थे।

श्रीरामचरितमानस के अनुसार समुद्र ने लंका जाने के लिए रास्ता नहीं दिया तो लक्ष्मण बहुत क्रोधित हो गए थे, जबकि वाल्मीकि रामायण में वर्णन है कि लक्ष्मण नहीं बल्कि भगवान श्रीराम समुद्र पर क्रोधित हुए थे और उन्होंने समुद्र को सुखा देने वाले बाण भी छोड़ दिए थे। तब लक्ष्मण व अन्य लोगों ने भगवान श्रीराम को समझाया था। वहीं समुद्र पर पुल का निर्माण नल और नील नामक वानरों ने किया था। क्योंकि उन्हें शाप मिला था कि उनके द्वारा पानी में फेंकी गई वस्तु पानी में डूबेगी नहीं, जबकि वाल्मीकि रामायण के अनुसार नल देवताओं के शिल्पी विश्वकर्मा के पुत्र थे और वह स्वयं भी शिल्पकला में निपुण थे। अपनी इसी कला से उन्होंने समुद्र पर सेतु का निर्माण किया था।

श्रीरामचरितमानस के अनुसार सीता स्वयंवर के समय भगवान परशुराम वहां आए थे। जबकि रामायण के अनुसार सीता से विवाह के बाद जब श्रीराम पुन: अयोध्या लौट रहे थे, तब परशुराम वहां आए और उन्होंने श्रीराम से अपने धनुष पर बाण चढ़ाने के लिए कहा। श्रीराम के द्वारा बाण चढ़ा देने पर परशुराम वहां से चले गए थे। वाल्मीकि रामायण के अनुसार एक बार रावण अपने पुष्पक विमान से कहीं जा रहा था, तभी उसे एक सुंदर स्त्री दिखाई दी, उसका नाम वेदवती था। वह भगवान विष्णु को पति रूप में पाने के लिए तपस्या कर रही थी। रावण ने उसके बाल पकड़े और अपने साथ चलने को कहा। उस तपस्विनी ने उसी क्षण अपनी देह त्यागकर रावण को शाप दिया। उसने रावण को शाप दिया कि एक स्त्री के कारण ही तेरी मृत्यु होगी। उसी स्त्री ने दूसरे जन्म में सीता के रूप में जन्म लिया।

श्रीरामचरितमानस के अनुसार भगवान श्रीराम ने सीता स्वयंवर में शिव धनुष को उठाया और प्रत्यंचा चढ़ाते समय वह टूट गया, जबकि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण में सीता स्वयंवर का वर्णन नहीं है। रामायण के अनुसार भगवान राम व लक्ष्मण ऋषि विश्वामित्र के साथ मिथिला पहुंचे थे। विश्वामित्र ने ही राजा जनक से श्रीराम को वह शिवधनुष दिखाने के लिए कहा। तब भगवान श्रीराम ने खेल ही खेल में उस धनुष को उठा लिया और प्रत्यंचा चढ़ाते समय वह टूट गया। राजा जनक ने यह प्रण किया था कि जो भी इस शिव धनुष को उठा लेगा, उसी से वे अपनी पुत्री सीता का विवाह कर देंगे।

रामायण के अनुसार राजा दशरथ ने पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रेष्ठि यज्ञ करवाया था। इस यज्ञ को मुख्य रूप से ऋषि ऋष्यश्रृंग ने संपन्न किया था। ऋष्यश्रृंग के पिता का नाम महर्षि विभाण्डक था। एक दिन जब वे नदी में स्नान कर रहे थे तब नदी में उनका वीर्यपात हो गया। उस जल को एक हिरणी ने पी लिया था, जिसके फलस्वरूप ऋषि ऋष्यश्रृंग का जन्म हुआ था।

महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना प्रभु श्रीराम के जीवनकाल में ही की थी। राम का काल 5114 ईसा पूर्व का माना जाता है, जबकि गोस्वामी तुलसीदासजी ने रामचरित मानस को मध्यकाल अर्थात विक्रम संवत 1631 अंग्रेंजी सन् 1573 में रामचरित मान का लेखन प्रारंभ किया और विक्रम संवत 1633 अर्थात् 1575 में पूर्ण किया था। एक शोध के अनुसार रामायण का लिखित रूप 600 ईसा पूर्व का माना जाता है। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण को संस्कृत भाषा में लिखा था जबकि तुलसीदासजी ने रामचरितमानस को अवधी में लिखा था। हालांकि रामचरितमानस की भाषा के बारे में विद्वान एकमत नहीं हैं। कोई इसे अवधि मानता है तो कोई भोजपुरी। कुछ लोक मानस की भाषा अवधी और भोजपुरी की मिलीजुली भाषा मानते हैं। मानस की भाषा बुंदेली मानने वालों की संख्या भी कम नहीं है।

महर्षि वाल्मीकि ने श्रीराम के जीवन को अपनी आंखों से देखा था। उनकी कथा का आधार **खुद राम का जीवन ही** था जबकि तुलसीदासजी ने रामायण सहित अन्य कई रामायणों को आधार बनाकर रामचरितमानस को लिखा था। यह भी कहते हैं कि उनकी सहायता हनुमानजी ने की थी। रामायण को संस्कृत काव्य की भाषा में लिखा गया जिसमें सर्ग और श्लोक होते हैं, जबकि रामचरितमानस के दोहो और चौपाइयों की संख्या अधिक है। रामायण में 24000 हजार श्लोक और 500 सर्ग तथा 7 कांड है। रामचरितमानस में श्लोक संख्या 27 है, चौपाई संख्या 4608 है, दोहा 1074 है, सोरठा संख्या 207 है और 86 छंद है।

● **ओम**

नया पेड़

एक बड़ा पेड़ था, बहुत ही पुराना। बड़ा ही घना था वो, उस पर ढेर सारे पक्षी घोंसला बनाकर रहा करते थे। बड़े पेड़ के बगल में ही एक छोटा पेड़ उगा था, उसे खुद पर बड़ा घमंड था। नए-नए पत्ते लहराती सी उसकी डालियां, मंत्रमुग्ध था वो अपनी सुंदरता पर। बड़े पेड़ की जड़ें बहुत पुरानी थीं। वह बूढ़ा हो गया था इसलिए उसकी छाल भी खुरदरी थी, उसके तनों में बड़े-बड़े कोटर हो गए थे जिसमें बहुत सारे जीव-जंतु रहा करते थे। बड़े पेड़ पर चिड़ियों ने अपने ढेर सारे घोंसले बना रखे थे। नए पेड़ को इस बात से बहुत ईर्ष्या होती थी कि कोई जीव-जंतु आश्रय लेने मेरे पास क्यों नहीं आता?

एक बार पक्षी का एक नया जोड़ा आया। नया पेड़ लहराते हुए उनसे बोला, उस पुराने पेड़ पर तो बहुत सारे घोंसले हैं। वहां बहुत ज्यादा भीड़ है, तुम लोग तो मेरी चिकनी और सुंदर टहनियों पर अपना घोंसला बनाओ। पक्षी के जोड़े ने पेड़ की बात पर गौर किया और अपना घोंसला उसी पेड़ पर बना लिया। एक दिन अचानक बड़े जोर का तूफान आया। नया पेड़ लहरा-लहराकर तूफान का सामना कर रहा था लेकिन वो असफल रहा और टूटकर पुराने पेड़ पर झुक गया। पुराने पेड़ का सहारा मिल जाने से नए पेड़ पर बना घोंसला टूटने से बच गया। लेकिन वह नया सुंदर और चिकनी टहनियों वाला पेड़ धराशायी हो चुका था। कुछ दिनों बाद पुराने पेड़ की बूढ़ी जड़ों से पुनः वैसा ही नया पेड़ अपनी कोंपलें फोड़ रहा था।

- लवी मिश्रा

गीत

खपरैले के नीचे,
गौरैया के बच्चे रहते थे।।
यह बच्चे एक दिन,
उड़ जाएंगे, दादा जी कहते थे।
खपरैले में गोरैया ने
नन्ही नीड़ बनाई थी।
जाने कहां-कहां से वो
तिनके चुनचुनकर लाई थी।
बिना पंख के नन्हे चूजे
पीली-पीली चोंचो वाले
सिर निकालकर चूं-चूं करके
कैसी बातें करते थे?
एक रोज वो काला कौवा
खपरैले पे आया था
गोरैया के बच्चों को
जब उसने नजर लगाया था।
बड़ी देर तक नन्हीं गोरैया
कौवे से झगड़ी थी,
उसी रोज से चूजे
नीड़ के बाहर नहीं निकलते थे।
गांवों से भी दूर हो रहे
खपरैले औ छप्पर छानी।
कांक्रीट के बस जंगल हैं,
दूषित है अब हवा सुहानी।
अब तो एसी-कूलर वाले,
वर्षा, आतप, हिम क्या जानें?
वो कैसे पुरखे थे जो,
सारा दिन गर्मी सहते थे?

-डॉ. दिवाकर दत्त त्रिपाठी

बाजारवाद

देखो बहू! बच्चों को अच्छा आहार, अच्छा पोषण देना जरूरी है ताकि वे स्ट्रांग बने। सासु मां बहू से कह रही थीं।

'हां मां जी, अब हमें बच्चों को स्ट्रांग बनाने के साथ-साथ उनके इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने के लिए भी प्रयास करना पड़ेगा ताकि भविष्य में कोरोना जैसे कोई महामारी आए तो हमारे बच्चे उनका डटकर मुकाबला कर सकें।' बहू ने कहा।

'हां बहू, अब तो पता नहीं हमें प्रकृति का कौन-कौन सा कहर सहना पड़ेगा। आजकल के बच्चों का तो इम्यूनिटी सिस्टम बड़ा खराब है। क्या करें, अब के बच्चे पिज्जा, बर्गर, चाऊमीन खा-खा के अपनी सेहत बर्बाद कर चुके हैं। अब उन्हें कौन समझाए?'

सासु मां ने लंबी सांस भरते हुए कहा। तभी टीवी पर मैगी का विज्ञापन देखकर मुन्ना मैगी खाने की जिद कर रोने लगा। उसे चुप कराते हुए बहू ने कहा, 'रो मत मेरा राजा बेटा, सिर्फ दो मिनट हां, अभी मैगी बनाकर लाती हूं।'

बहू की यह बात सुनकर सासु मां सोचने लगी कि बाजारवाद और विज्ञापन आज सब पर भारी पड़ गया है।

- डॉ. शैल चन्द्रा

भारत और इंग्लैंड के बीच चल रहे टेस्ट क्रिकेट की सीरीज में अब दो मैच ही शेष बचे हुए हैं। यही दोनों मैच तय करेंगे कि विश्व में टेस्ट मैचों का बादशाह कौन है। न्यूजीलैंड, भारत, इंग्लैंड और आस्ट्रेलिया में से कोई एक विश्व विजेता 18 जून को बनेगा लेकिन उससे पहले इसी सीरीज में दो टीमों का सफर थम जाएगा। पिंक कलर की गेंद दुनिया की तीन क्रिकेट टीमों का मुकद्दर लिखने को तैयार है।

टेस्ट मैचों का बादशाह कौन?

विश्व टेस्ट चैंपियनशिप अपने निर्णायक मोड़ पर है। 18 जून को फाइनल मैच है। ऐसे में अब विश्व की सभी टेस्ट टीमों के भाग्य का फैसला अब कुछ ही दिनों में हो जाने वाला है। फिलहाल टूर्नामेंट की दौड़ में केवल चार टीमें ही बची हुई हैं। फाइनल मैच में प्रवेश पाने वाली एकलौती टीम है नंबर एक पर काबिज न्यूजीलैंड की टीम। वहीं फाइनल मैच का टिकट हासिल करने के लिए अभी तीन दिग्गज टीमों के बीच घमासान मचा हुआ है। इन तीन टीमों में नंबर दो पर काबिज भारत के साथ इंग्लैंड और आस्ट्रेलिया भी फाइनल मैच में जगह बनाने के लिए जद्दोजहद में जुटी हुई है। हालांकि भारत ने तीसरे टेस्ट में इंग्लैंड को हराकर अपनी दावेदारी मजबूत कर ली है। लेकिन भारत चौथे टेस्ट में भी कोई ऐसी गलती नहीं करेगा जिससे उसे हार का सामना करना पड़े।

आईसीसी पहली बार विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का आयोजन कर रहा है। इस चैंपियनशिप में टेस्ट खेलने वाले सभी देशों को द्विपक्षीय सीरीज खेलनी होती है जिसमें प्वाइंट देकर इसकी अंकतालिका आईसीसी जारी करता है। 18 जून 2021 को इस विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मैच होना है। यह मैच लॉर्डस के मैदान पर खेला जाना है। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप पहली बार ही इतना रोमांचक होगा इसकी उम्मीद कम थी, लेकिन अब इसके रोमांच को देखते हुए ऐसा लगता है कि यह टूर्नामेंट भी हिट साबित हुआ है।

टीम इंडिया ने 4 टेस्ट की सीरीज में 2-1 की बढ़त बना ली है। पहला टेस्ट इंग्लैंड ने 227 रन से जीता था। इसके बाद टीम इंडिया ने दूसरा टेस्ट 317 रन से अपने नाम कर सीरीज बराबर कर दी थी। यह तीसरा टेस्ट जीतकर टीम इंडिया टेस्ट चैंपियनशिप की पॉइंट टेबल में टॉप पर पहुंच गई है। चैंपियनशिप का फाइनल 18 जून को इंग्लैंड के लॉर्ड्स में होगा। भारत को फाइनल में पहुंचने के लिए अब सीरीज का आखिरी मैच जीतना या ड्रॉ कराना जरूरी है। वहीं, इंग्लैंड के विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में पहुंचने की उम्मीद खत्म हो गई। इस हार के साथ इंग्लैंड की टीम विश्व टेस्ट चैंपियनशिप टेबल में चौथे नंबर पर पहुंच गया है। अगर इंग्लिश टीम अगला मैच जीतती भी है, तो भी ऑस्ट्रेलिया फाइनल में पहुंचेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि इंग्लैंड के पॉइंट प्रतिशत ऑस्ट्रेलिया से कम होंगे। न्यूजीलैंड पहले ही फाइनल में अपनी जगह पक्की कर चुका है। सीरीज शुरू होने से पहले इंग्लैंड को फाइनल में पहुंचने के लिए 4-0, 3-0 या 3-1 से जीत की जरूरत थी, लेकिन अब तीनों विकल्प खत्म हो गए।

भारत को विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने के लिए 2-1 से जीत हासिल करने की जरूरत थी। अगर भारत अगला मैच जीत जाता है, तो और भी बेहतर स्थिति के साथ फाइनल में पहुंचेगा। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप पहली बार वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप करा रही है। फाइनल 18 जून से लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जाना है। कोरोना के कारण क्रिकेट पर काफी असर पड़ा। इसके चलते आईसीसी ने टेस्ट चैंपियनशिप के पॉइंट्स टेबल के फॉर्मेट में थोड़ा बदलाव किया था, ताकि कम मैच खेलने वाली टीम के साथ भेदभाव न हो। अनिल कुंबले की अगुवाई वाली आईसीसी की क्रिकेट कमेटी ने टीमों की रैंकिंग पर्सेंटेज बेसिस पर कैलकुलेट करने का फैसला किया था। इस नए सिस्टम में टीमों द्वारा खेली गई सीरीज और उस सीरीज में उनके पॉइंट्स के आधार पर पर्सेंटेज निकाला जा रहा है। कोई टीम अगर अपनी सभी 6 सीरीज खेलती है तो अधिकतम 720 पॉइंट्स पा सकती है। 6 सीरीज में अगर टीम के कुल 480 पॉइंट्स होते हैं, तो उसका पर्सेंटेज पॉइंट 66.67 प्रतिशत होगा। वहीं, कोई टीम अगर 5 सीरीज ही खेलती है, तो मैक्सिमम पॉइंट्स 600 हो जाएंगे। 5 सीरीज खेलने वाली इस टीम के अगर 450 पॉइंट्स होते हैं, तो उसके पर्सेंटेज पॉइंट्स 75 प्रतिशत होंगे। ऐसे में 5 सीरीज खेलने वाली टीम 6 सीरीज खेलकर 480 पॉइंट्स पाने वाली टीम से ऊपर रहेगी।

● **आशीष नेमा**

पाक्षिक पत्रिका अक्स के स्वामित्व एवं अन्य विषयों संबंधित विवरण

घोषणा

फार्म 4 (नियम 8 देखिए)

प्रकाशन	:	भोपाल
प्रकाशन अवधि	:	पाक्षिक
मुद्रक का नाम	:	राजेन्द्र आगाल
नागरिकता	:	भारतीय
पता	:	150 जोन-1, प्रथम तल मनोरमा काम्पलेक्स महाराणा प्रताप नगर भोपाल
प्रकाशक का नाम	:	राजेन्द्र आगाल
नागरिकता	:	भारतीय
पता	:	150 जोन-1, प्रथम तल मनोरमा काम्पलेक्स महाराणा प्रताप नगर भोपाल
संपादक का नाम	:	राजेन्द्र आगाल
नागरिकता	:	भारतीय
पता	:	150 जोन-1, प्रथम तल मनोरमा काम्पलेक्स महाराणा प्रताप नगर भोपाल
उन व्यक्तियों के नाम व पते जो समाचार पत्र के स्वामी हों तथा	:	राजेन्द्र आगाल 150 जोन-1, प्रथम तल मनोरमा काम्पलेक्स महाराणा प्रताप नगर भोपाल

जो समस्त पूंजी के एक प्रतिशत से अधिक के साझेदार या हिस्सेदार हों।

मैं राजेन्द्र आगाल एतद् द्वारा घोषित करता हूं कि मेरी अधिकृत जानकारी एवं विश्वास के अनुसार ऊपर दिए गए विवरण सत्य हैं।

दिनांक : 01.03.2021 **राजेन्द्र आगाल**

हस्ताक्षर

...जब आमिर खान की वजह से खूब रोई थीं दिव्या भारती

90 के दशक की लोकप्रिय अभिनेत्री दिव्या भारती को लेकर यूं तो कई किस्से मशहूर हैं लेकिन एक बार दिवंगत एक्ट्रेस ने खुलासा किया था कि आमिर खान की वजह से वे कई घंटे तक रोती रही थीं। कहा जाता है कि लंदन में हुए एक शो में दिव्या भारती अपनी डांस स्टेप्स भूल गई थीं जिसकी वजह से आमिर उनसे नाराज हो गए थे। हालांकि, जब इस बारे में खुद दिव्या से बात की गई तो उन्होंने कहा था कि आमिर को उनसे माफी मांगनी चाहिए। दिव्या ने यह भी कहा था कि शो के दौरान उनसे गलती हुई थी, लेकिन उन्होंने उसे तेजी से कवर कर लिया था।

दिव्या भारती ने भले ही अपनी गलती को कवर कर लिया था। लेकिन आमिर नहीं माने। कहा जाता है कि आमिर ने ऑर्गेनाइजर्स से दिव्या की जगह जूही चावला से परफॉर्मेंस कराने की सलाह दी थी। इतना ही नहीं, आमिर ने दिव्या के साथ परफॉर्म करने से इनकार कर दिया था। उन्होंने थकान का बहाना बनाया था। इसके बाद सलमान खान दिव्या के सपोर्ट में आए और उन्होंने स्टेज पर उनके साथ जबर्दस्त परफॉर्मेंस दी।

एक करोड़ फीस लेने वाली पहली अभिनेत्री थीं श्रीदेवी

फिल्म सदमा की याद्दाश्त खोई हुई मासूम लड़की का किरदार हो या फिर फिल्म मिस्टर इंडिया में हवा हवाई गाकर अपने चुलबुले पन से दर्शकों को सिनेमा के जादू का अहसास करवाने की बात, श्रीदेवी ने सिल्वर स्क्रीन पर निभाए अपने हर किरदार से दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया। श्रीदेवी का नाम एक ऐसी अभिनेत्री के रूप में लिया जाता है, जिन्होंने अपनी दिलकश अदाओं और दमदार अभिनय से अस्सी और नब्बे के दशक में दर्शकों पर अपनी छाप छोड़ी।

श्रीदेवी ने अपने तीन दशक लंबे कैरियर में लगभग 300 फिल्मों में काम किया। इनमें 63 हिंदी, 62 तेलुगु, 58 तमिल और 21 मलयालम फिल्में शामिल हैं। बॉलीवुड में यूं तो हमेशा ही एक्टर को एक्ट्रेस से ज्यादा फीस मिलती है। लेकिन 80 और 90 के दशक में प्रोड्यूसर-डायरेक्टर श्रीदेवी को फिल्में हिट कराने का सबसे बड़ा फॉर्मूला मानते थे। यही वजह है कि उस दौर में श्रीदेवी ऐसी एक्ट्रेस थीं, जिन्हें सबसे पहले बतौर फीस 1 करोड़ रुपए मिले थे। हिंदी फिल्मों में बतौर अभिनेत्री श्रीदेवी ने अपने सिने करियर की शुरुआत साल 1979 में आई फिल्म सोलहवां सावन से की। नगीना, मिस्टर इंडिया और चालबाज जैसी कई फिल्मों में वे अलग अंदाज में नजर आईं।

सलमान भी श्रीदेवी से इनसिक्योर फील करते थे

आज भले ही बॉलीवुड में सलमान का नाम चलता हो, लेकिन एक दौर ऐसा भी था, जब सलमान खुद श्रीदेवी के साथ काम करने से घबराते थे। एक इंटरव्यू में खुद सलमान ने बताया था कि उन्हें श्रीदेवी के साथ काम करने में डर लगता था। वजह ये थी कि जिस फिल्म में श्रीदेवी होती थीं, तो दूसरे एक्टर को दर्शक तवज्जो ही नहीं देते थे। श्रीदेवी ने सलमान के साथ चंद्रमुखी और चांद का टुकड़ा जैसी फिल्मों में काम किया।

शराब की लत से मौत की कगार पर पहुंच गई थीं पूजा भट्ट

पिता ने कही एक बात पर जिंदगी भर के लिए छोड़ दिया अल्कोहल पीना

एक्ट्रेस, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर रहीं पूजा भट्ट शुरुआत से ही कॉन्ट्रोवर्सी में रही हैं। इन्होंने फिल्म डैडी (1989) से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। इसे उनके पिता महेश भट्ट ने डायरेक्ट किया था। तब पूजा सिर्फ 17 साल की थीं। इस फिल्म में उन्हें काफी बोल्ड अंदाज में पेश किया गया था, फिल्म के लिए पूजा को फिल्मफेयर न्यू फेस ऑफ द ईयर का अवॉर्ड मिला था। सूत्रों के मुताबिक,

पूजा भट्ट ने 16 साल की उम्र से ही शराब पीना शुरू कर दिया था। धीरे-धीरे उन्हें शराब की ऐसी लत लगी कि वो इसकी आदी हो गईं। हालांकि, 45 साल की उम्र होने तक उन्हें अहसास होने लगा था कि शराब छोड़ देना चाहिए वरना वो ज्यादा दिन नहीं जिएंगी। उन्हें ऐसा लगने लगा था कि वह अब मरने की कगार पर हैं।

पूजा भट्ट ने 24 दिसंबर, 2016 को शराब छोड़ने की कसम खाई और तब से अब तक उन्होंने शराब की बोतल को हाथ तक नहीं लगाया। पूजा के पिता महेश भट्ट और उनके कैबरे डायरेक्टर कौस्तुव के स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की वजह से पूजा को शराब जैसी बुरी लत को छोड़ने में काफी मदद मिली।

महेश भट्ट की एक बात से पूजा को अपनी गलती का अहसास हुआ। महेश ने कहा था- अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो खुद से भी प्यार करो, क्योंकि मैं खुद को तुम्हारे अंदर जीता हूं। बस, उनकी इसी बात ने पूजा को हेल्दी लाइफ जीने के लिए मोटिवेट किया।

भैंस और लाठी की कथा

कल रात प्रभु मेरे सपने में आए और कहा भक्तजन तुम्हारे मायावी संसार में भैंस और लाठी को लेकर अनेक भ्रांतियां फैली हुई हैं। उसे ठीक करने की जिम्मेदारी मैं तुम्हारे कंधों पर डालता हूं। तुम कोई जतन ऐसा करो कि लाठी से भैंस का सदियों पुराना नाता खत्म हो जाए।

प्रभु कारपोरेट जगत के सीईओ की तरह आर्डर दे के अंतर्ध्यान हो गए। उन्हें काम लेना आता है। इन कारपोरेट वालों के लिए आप चाहे कितने पापड़ बेलो कोई गिनने वाला नहीं।

प्रभु का आदेश हो, और पालन न किया जाए, ऐसा बिरला ही होता है। लोग जेब में अठन्नी लेकर तीर्थयात्रा पर निकल जाते हैं, प्रभु अपनी लीला से उनके हर स्टेशन में, कदम-कदम इंतजाम किए देते हैं।

बस यही फर्क हिंदुस्तान और दीगर के मुल्कों में है।

उधर अठन्नी छाप को, आतंकवादी समझ के 'इन्कौनटर' के हवाले कर दिया जाता है। बातों-बातों में समय क्या बिताएं... प्रभु ने हमें 'लाठी और भैंस' पर अनुसंधान करने की जो जिम्मेदारी दी है, उसे निपटाएं।

अभी तक प्राप्त तथ्यों के माध्यम से जो जानकारी है वो ये कि लाठी रखने के अनेक फायदे हैं। प्रमुख यह कि इसके जरिए भैंस को पाया जा सकता है।

पुराने जमाने में भैंस को खरीदा नहीं जाता था। भैंसें, कई आसपास ही घूमा करती थीं। जिसके पास दबंगई होती थी या जो लाठी को तेल पिलाए रहता था वही अपने घर हांक ले जाता था।

उन दिनों लाठी को तेल पिलाने का अलग रिवाज था।

तेल पिलाई हुई लाठी दिनों-दिन मजबूत होते जाती है, ऐसा वे लोग सोचते थे। रंग, रोगन, पेंट लगाने का न वो जमाना था, न उन दिनों ये सब चीजें सहज उपलब्ध हो पाती थीं। सो तीज-त्यौहार में इस्तेमाल किए हुए तेल का जो 'डढेल' बच जाए उसे लाठी के हवाले कर दिया जाता था।

दबंगई में 'तेल पी' हुई लाठी से लट्ठेबाजों के हुनर में चार-छह चांद इकट्ठे लग जाया करते थे। लाठी, किसी पेड़ के सीधे शाख को छांट के बना ली जाती थी। बनने के बाद ये एक अच्छी, सीधी-सधी, कलाई से करीब आधी गोलाई वाली, पांच सात फुट की लकड़ी होती थी। शाखा के गाठ को तरीके से छील-घिस के, चिकना तैयार किया जाता था।

पहले इस लाठी पर, अहीर, ग्वाल, यादवों का एकाधिकार होता था।

उस जमाने में जो तमंचा-रामपुरी रखने के जो शौकीन नहीं होते थे, वे अनिवार्य रूप से, अपनी रक्षा के लिए या दूसरों को धमकाने के लिए लाठी रखा करते थे।

सामाजिक प्रतिष्ठा के ये प्रतीक चिन्ह भी होते थे।

चौधरी और ठाकुर कहलाने के लिए, आपके पास अनिवार्य रूप से मजबूत लाठी का पाया जाना अपेक्षित था।

बाद में यही कब, रायफल में बदल गया ये अब भी शोध का विषय है प्रभु।

एक लाठी ले के, पूरे गांव को हिला के आया जा सकता था।

लाठी चालन की विद्या जिस किसी ने तन्मयता से ले ली समझो उसका नाम आस पड़ोस के ग्रामीण लिमका में दर्ज नाम की तरह सम्मान के साथ जाना जाता था।

इस सम्मान को धक्का तभी लगता, जब इन जैसे, दस-पांच के समूह को जमींदार इकट्ठे अपने पे रोल में रख लेता था।

फिर ये लठैत की श्रेणी के हो जाते थे।

लठैत का श्रम-विभाजन, व उनकी अल्प बुद्धि के मद्देनजर वे समाज में अपना सम्मानजनक स्थान नहीं बना पाए।

ये (लठैत) लोग आंचलिक पृष्ठभूमि से उठकर शहरी सभ्यता में रम नहीं पाए। बस रेल का टिकट कटाते ही, इनके हाथ पांव फूलने लगते। इनकी लाठी रबर जैसी लुंज-पुंज पड़ जाती। यही हाल शहरी पुलिस को देख के दुगना भी होने लगता।

अब भैंस को लें, बेचारी दूध देना बखूबी जानती है। इसका ज्यादा इस्तेमाल प्राइमरी स्कूलों में निबंध लिखने में किया जाता था। उस जमाने में बच्चे सिवाय भैंस के कुछ देखे भी नहीं होते थे। आज के बच्चे रेल, हवाई जहाज, मेट्रो और डिज्नीलैंड आदि हजारों चीजों पर फर्राटे से लिख-पढ़, बोल सकते हैं।

भैंस के निबंधों में एक राष्ट्रीय समानता होती थी वही चार पैर, एक पूंछ, गोबर देने की बाध्यता प्रमुखता से व्यक्त की जाती थी। कहीं क्षेत्रीय-स्थानीय या राज्य की सीमा का न बंधन न उल्लंघन।

सब भैसों की एक गति थी। कोई नहीं कह सकता था कि तमिल का मावा महाराष्ट्र, गुजरात से जुदा है। घी बना लो, लस्सी छाछ पी लो, पंजाब से हरियाणा तक के भैसों की, एक वाणी, एक जुबान, एक स्वाद। इस निरीह प्राणी पर जाने क्यूं लाठी का आतंक युगों तक पसरा रहा?

सार बात ये कि भैंसें डंडा रखने वाले से भी कम दिमाग वाली होती है। गरीब की लुगाई जैसी हालत रहती है इनकी जिसे देखो वही हड़काए दिए रहता है।

भैंस की जरूरतें भी कम होती हैं, दिनभर मैदान में चारा चर के वे काम चला लेती थीं। आजकल वो भी मयस्सर नहीं, मैदान प्लास्टिक-पॉलीथीन से भर गए हैं। उनके पेट में जाने अनजाने यही घुस रहा है।

सरकारी आंकड़ों के आडिट में भैसों के साथ चारा खाने वाले लोगों में बड़े अफसरान, संतरी और मंत्री भी शामिल पाए गए। प्रभु आप तो स्वयं जानते हैं, हमारे देश में जानवरों के या बेजुबानों के हिस्से में से मारने वालों की कमी नहीं। प्रभु जी हमने लोगों को कहते सुना है, आपकी लाठी बेआवाज होती है?

● **सुशील यादव**

विश्वसनीय खबरों के लिए पढ़ते रहिए

In Pursuit of Truth

पाक्षिक

अक्स

E-Magazine पढ़ने और PDF डाउनलोड करने के लिए हमारी वेबसाइट पर जाएं

www.akshnews.com

वार्षिक सदस्यता के लिए संपर्क करें, 150, जोन-1, एम.पी.नगर भोपाल

फोन:0755-4017788,2575777

D-17008

For Any Medical & Pathology Equipments Contact Us

Science House Medicals Pvt.Ltd.

17/1, Sector-1, Shanti Niketan, Near Chetak Bridge, Bhopal (M.P.) INDIA-462023

GST. No. : 23AAPCS9224G1Z5 PH. : +91-0755-4241102, 4257687

Email : shbpl@rediffmail.com Fax : +91-0755-4257687